# चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित

दिल्ली, 22 अगस्त–28 अगस्त 2011

मूल्य 5 रुपये



**भ्रष्टाचार : संप्रभुता पर हमला**

पेज-3

**दोषी पुलिसवालों को फांसी हो**

पेज-6

**गांधी की विरासत खादी की उपेक्षा**

पेज-7

**साई की महिमा**

पेज-12


## सीएजी रिपोर्ट पर राजनीति

# प्रजातंत्र के लिए ख़तरा है

**इस बात पर हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माता विद्धान थे, सचमुच महापुरुष थे. प्रजातंत्र के मूल्यों और इसे बचाए रखने के लिए ज़रूरी संस्था की ज़रूरत को भली भांति समझते थे. वे दूरदर्शी थे. उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ सीएजी जैसी संस्था की उपयोगिता और अधिकार के बारे में बताया था. उस वक़्त के सासंदों के भाषणों को पढ़ने के बाद आज के नेता बौने दिखते हैं. ऐसा लगता है जैसे बंदर के हाथ नारियल थमा दिया गया हो. दरअसल यही फ़र्क़ है जिसकी वजह से आज सीएजी जैसी संस्था की प्रतिष्ठा पर हमला हो रहा है. कल सुप्रीम कोर्ट इन नेताओं के निशाने पर आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए.**

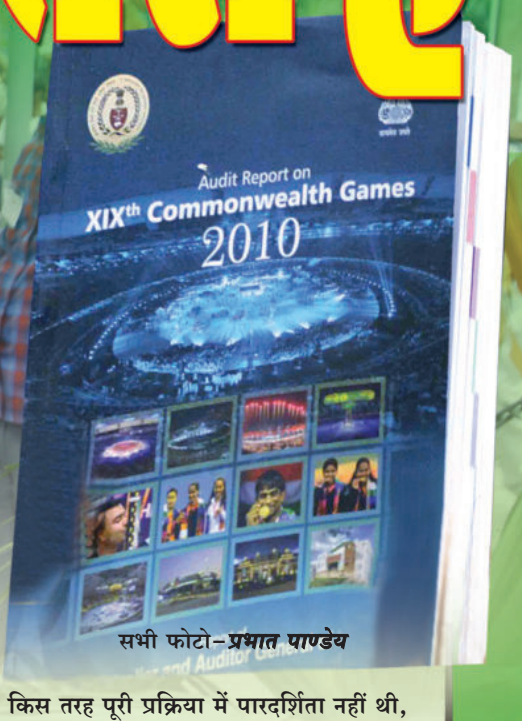


सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

मनीष कुमार

सीएजी (कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आई तो राजनीतिक हलक़ों में हंगामा मच गया. दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित विपक्ष के निशाने पर आ गईं. रिपोर्ट ने देश की जनता के सामने सबूत पेश किया कि कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स नेताओं और अधिकारियों के लिए लूट महोत्सव बन गया. कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से दलील दी गई कि सीएजी की रिपोर्ट फाइनल नहीं है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी. अब लोक लेखा कमेटी (पीएसी) में फ़ैसला होगा. अगर अब कोई कांग्रेस पर यह आरोप लगाए कि यह सीएजी की संस्था की प्रतिष्ठा नष्ट कर रही है तो यह ग़लत नहीं होगा. वैसे लोक लेखा कमेटी को कांग्रेस पार्टी ने 2जी स्पैक्ट्रम मामले में पहले ही राजनीति की भेंट चढ़ा दिया है. अब इस रिपोर्ट के साथ क्या होगा यह पता नहीं. फ़िलहाल न तो कोई चुनाव है और न ही भारतीय जनता पार्टी के पास संसद में इतनी संख्या है और न ही प्रभाव है कि यूपीए सरकार को कोई ख़तरा हो सके. यही वजह है कि सरकार विरोध का स्वर सुनने को तैयार नहीं है. भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जब दिल्ली में प्रदर्शन किया. पुलिस ने डंडों से उसका स्वागत किया. कार्यकर्ताओं की ज़बरदस्त पिटाई हुई. जब पुलिस के डंडे पोलियो ग्रस्त व्यक्ति के पैरों पर पड़ते हैं तो यह देखकर अफ़सोस होता है.

**डॉ. भीमराव अंबेडकर के बयान की रौशनी में यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सीएजी पर यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी की दलील ग़लत हैं. सीतारमैया ने संविधान सभा में कहा कि देश का सीएजी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह स्वतंत्र और आर्थिक मामलों में सुप्रीम होना चाहिए. सीएजी सिर्फ़ ऑडिटर जनरल नहीं है, वह न्यायिक अधिकारी है. इस वक्तव्य से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रधानमंत्री का बयान और संविधान सभा की भावनाओं में बहुत अंतर है.**

**सरकार की दलील से एक स्थिति उत्पन्न होती है. अगर एक ऐसा घोटाला सामने आता है, जिसमें सरकार और मुख्य विपक्षी दल के नेता दोनों शामिल हो तो फिर क्या होगा? सीएजी की रिपोर्ट तो फिर किसी भी काम नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में पीएसी में इस पर कोई फ़ैसला नहीं होगा. सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर मिल जाएं तो देश में किसी भी लूट को अंजाम देने में सफल हो जाएंगे.**

सीएजी की रिपोर्ट पर इसलिए हंगामा मचा, क्योंकि इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में गड़बड़ियों का पर्दाफ़ाश हुआ है. रिपोर्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार किए गए स्टेडियम, उपकरण, खेलगांव, सड़कों के सौंदर्यीकरण, उद्घाटन और समापन समारोह पर हुए ख़र्च में अनियमितता का ज़िक्र है. सीएजी रिपोर्ट में यह उजागर हुआ है कि किस तरह ठेका देने में नियमों का उल्लंघन हुआ, किस तरह पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी, किस तरह ठेका देने के बाद ख़र्च बढ़ाया गया, और किस तरह नक़द ख़र्च किया गया, ताकि उसके बारे में जानकारी आसानी से नहीं मिल सके. सीएजी की रिपोर्ट पर इसलिए भी हंगामा हुआ, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में कलमाड़ी की नियुक्ति को लेकर खेलमंत्री ने संसद में भ्रम फैलाने वाले बयान दिए. लेकिन रिपोर्ट में साफ़-साफ़ बताया गया कि तत्कालीन खेल मंत्री सुनील दत्त के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने पर आयोजन समिति के अध्यक्ष पद पर सुरेश कलमाड़ी की नियुक्ति हुई. मतलब यह कि एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जनता के पैसे की लूट हुई और सरकार अपराधियों को सज़ा दिलाने की बजाय सीएजी की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा रही है. सीएजी के अधिकार और रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े किए जाने लगे. ऐसे में सवाल यह है कि सीएजी के दायित्व और अधिकार पर कांग्रेस पार्टी और सरकार की तरफ़ से जो प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, क्या वह सही हैं?

कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में सीएजी की रिपोर्ट में जो लिखा है, वैसी टिप्पणी पहली बार नहीं की गई है. सरकार के फ़ैसले और नीतियों पर वह पहले भी सवाल उठा चुकी है. सीएजी की निष्पक्षता और मुस्तैदी से कृष्णा मेनन, टीटी कृष्णामाचारी, जॉर्ज फर्नांडीस जैसे राजनेता पर कार्रवाई हुई. सीएजी की रिपोर्ट का महत्व क्या है, यह बात लोक लेखा कमेटी के एक चेयरमैन पहले ही अंकित कर चुके हैं. 1967–69 में संसद के लोक लेखा कमेटी के चेयरमैन एम आर मसानी के मुताबिक़ सीएजी की रिपोर्ट किसी भी सरकारी अधिकारी की ज़िम्मेदारी ठहराने के लिए पर्याप्त है. लेकिन आज की स्थिति यह है कि सीएजी रिपोर्ट को पीएसी के पास भेज दिया जाता है, फिर जांच होती है. अब यह पता नहीं कि पीएसी के सदस्यों में ऐसी कौन सी बात है जिससे यह भरोसा हो सके कि वह प्रोफेशनल ऑडिटर से बेहतर तहक़ीक़ात कर सकते हैं. पीएसी किसी निर्णय पर भी पहुंच जाती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है. सबकुछ ठंडे बस्ते के अंदर बंद हो जाता है.


(शेष पृष्ठ 2 पर)



"Cotton ki Jhappi!"

T.T.

Healthy Innerwear

Vest • Brief • Bra-Panties • T-Shirts

Ph. : 011-45060708, E-mail: export@tttextiles.com

कुछ बाबू इसके लिए अभी से दावेदारी प्रस्तुत करने की तैयारी करने लगे हैं, लेकिन यह पद किसी के लिए भी कांटों भरा ताज ही साबित होगा.



# दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

## गोपनीयता के रखवाले

गोपनीयता का रखवाला कौन हो सकता है? संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी किसी दस्तावेज़ को गोपनीय घोषित कर सकता है. एक अंडर सेक्रेटरी एक दस्तावेज़ को सिर्फ़ कंफीडेंशियल ही घोषित कर सकता है. यह ख़ुलासा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक आरटीआई के तहत दिए गए जवाब में हुआ है. दिलचस्प रूप से डीओपीटी की यह राय गृह मंत्रालय के साथ सांझा नहीं की गई है. गृह मंत्रालय के लिए उपरोक्त क़िस्म की सूचनाएं (सिक्रेट और कंफीडेंशियल) सार्वजनिक करने का अर्थ देश के लिए ख़तरा है. निलंबित अधिकारी रवि इंदर सिंह, जिन पर सिक्रेट दस्तावेज़ लीक करने का आरोप है, ने अपने ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट से यह मांग की कि उन्हें वे सिक्रेट दस्तावेज़ मुहैया कराए जाएं, जिन्हें लीक करने का उन पर आरोप है. कोर्ट ने गृह मंत्रालय को यह आदेश दिया है कि भले ही वे दस्तावेज़ सिक्रेट हों, लेकिन उन्हें रवि इंदर सिंह को उपलब्ध कराया जाए.

## बाबू रिपोर्ट कार्ड

पिछले साल वरिष्ठ बाबुओं के परफॉर्मेंस की रेटिंग के लिए अपनाए गए ग्रेडिंग सिस्टम के परिणाम को अब सार्वजनिक किया जा रहा है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस बात से सहमत हैं कि ऐसा करने से सरकार में पारदर्शिता के साथ प्रशासन की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा. केंद्र के 62 विभागों के सचिव स्तर के बाबुओं के लिए यह थोड़ा परेशान करने वाली ख़बर है, क्योंकि इससे उन्हें मिलने वाली वित्तीय सुविधाओं पर विपरीत असर पड़ेगा. कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रेटिंग की वजह से बाबुओं का रिटायरमेंट के बाद का करियर भी प्रभावित होगा. सूत्रों के मुताबिक़ यह रेटिंग 5 स्तरों में की जा रही है यानी एक्सीलेंट से लेकर पूअर तक.

## चेहरा बदलेगा, हालत नहीं

वैश्विक आर्थिक मंदी के साये में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर डी सुब्बा राव को दो साल का सेवा विस्तार दे दिया गया है. लेकिन एयर इंडिया की ख़राब माली हालत ने इसके मुखिया अरविंद जाधव को कोई राहत नहीं पहुंचाई. सूत्रों के मुताबिक़ जाधव की जगह किसी और को लाने की बात पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. कुछ बाबू इसके लिए अभी से दावेदारी प्रस्तुत करने की तैयारी करने लगे हैं, लेकिन यह पद किसी के लिए भी कांटों भरा ताज ही साबित होगा. ज़्यादातर का यह मानना है कि जाधव के जाने के बाद भी एयर इंडिया की माली हालत नहीं सुधरने जा रही है, क्योंकि यहां पहले से ही इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि किसी भी अकेले बाबू के लिए इससे निपटना आसान नहीं होगा.

dilipcherian@gmail..com

## साउथ ब्लॉक

### सुनील कुमार सीवीओ बने

बिहार कैडर और 1983 बैच के आईएएस अधिकारी सुनील कुमार सिंह को इंडियन ऑयल कारपोरेशन का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है. इससे पहले सुनील कुमार आवास एवं शहरी ग़रीबी उन्मूलन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात थे.

### भास्कर की विदाई

ओड़िसा कैडर और 1999 बैच के आईएएस अधिकारी भास्कर ज्योति शर्मा अभी कैबिनेट सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर हैं. बहुत जल्द ही उनका तबादला अब इसी पद पर पर्यटन मंत्रालय के लिए कर दिया जाएगा.

### संजीव निदेशक बनेंगे

ओड़िसा कैडर और 1999 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक का पद संभाल सकते हैं. यह पद नवसृजित है.

### सुजीत गृह मंत्रालय जाएंगे

वर्ष 1992 बैच के आईटीएस अधिकारी सुजीत चट्टोपाध्याय को गृह मंत्रालय में उप वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त किए जाने की संभावना है. यह पद नवसृजित है.

### सात अधिकारी जेएस बनेंगे

वर्ष 1988 बैच के 7 आईए एंड एएस अधिकारियों का नाम भारत सरकार में संयुक्त सचिव पद के लिए बनाई गई सूची में शामिल कर लिया गया है. इनके नाम हैं, दीपक अनुराग, एसएस डाधे, एमएस मैथ्यू, मीरा स्वरूप, सीए बोध, मीनाक्षी शर्मा और जे विल्सन.

# प्रजातंत्र के लिए ख़तरा है

पृष्ठ एक का शेष

कांग्रेस पार्टी सीएजी पर कई आरोप लगा रही है. कांग्रेस पार्टी के मूड से तो यही लगता है कि उसने सीएजी पर ही हमला कर दिया है. क़ानून मंत्री सलमान ख़ुर्शीद कहते हैं कि सरकार की अपनी ज़िम्मेदारी है और सीएजी की अपनी ज़िम्मेदारी है. सबको अपना काम करना है. सीएजी जो भी रिपोर्ट बनाती है उसकी जांच पीएसी करती है. उनके मुताबिक़ पीएसी मिनी पार्लियामेंट है. वहां इस रिपोर्ट की जांच होगी. सीएजी की रिपोर्ट को पीएसी में भेजना कार्यप्रणाली का हिस्सा है, लेकिन क्या कार्यप्रणाली का महत्व इतना है कि संविधान की आत्मा का ही गला घोंट दिया जाए? क़ानून मंत्री की दलील संविधान निर्माताओं और संविधान सभा के विचारों और विश्वास के विरुद्ध है. क्या सरकार यह कहना चाहती है कि सीएजी की रिपोर्ट अगर किसी घोटाले के बारे में बताती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी.

सरकार की दलील से एक स्थिति उत्पन्न होती है. अगर एक ऐसा घोटाला सामने आता है, जिसमें सरकार और मुख्य विपक्षी दल के नेता शामिल हैं, तो क्या होगा? सीएजी की रिपोर्ट तो फिर किसी भी काम नहीं आएगी, क्योंकि पीएसी में इस पर कोई फ़ैसला नहीं होगा. सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर मिल जाएं तो देश में किसी भी लूट को अंजाम देने में सफल हो जाएंगे. दुख की बात यह है कि सीएजी की रिपोर्ट का क्या हो, इस बात पर सैद्धांतिक रूप में सभी दलों की राय यही है कि सीएजी की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद पीएसी में जानी चाहिए. सबकी दलील यही है कि यह लंबे समय से चली आ रही प्रथा है. पीएसी में सीएजी रिपोर्ट का क्या होता है, यह सब जानते हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स के मामले में सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी ही सीएजी रिपोर्ट पर कार्रवाई चाहती है. इसलिए, क्योंकि 2जी स्पेक्ट्रम मामले में पीएसी में कांग्रेस पार्टी ने ठीक से काम नहीं करने दिया.

सीएजी देश के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है, जो भारतीय राजनीति में जवाबदेही सुनिश्चित करती है. सीएजी को भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के रूप में जाना जाता है और इसने 16 नवंबर 2010 को अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए हैं. ऐसी संस्था का महत्व ब्रिटिश सरकार ने तब महसूस किया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1858 में सत्ता संभाली. आज दुनिया भर के देशों में सीएजी जैसी संस्था है, जो ज़्यादा शक्तिशाली है. उनके पास ऑडिट करने के साथ-साथ किसी भी मामले की जांच करने की पावर है. भारत में एक ग़लत धारणा बन गई कि सीएजी सिर्फ़ ऑडिट करने वाली संस्था है. सीएजी का पूरा अर्थ है कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. मतलब, यह सरकारी ख़र्च का नियंत्रक भी है और ऑडिटर भी है. यही हमारे संविधान में भी है. सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाती है. इस रिपोर्ट का आधार यह होता है कि सरकारी पैसे का उपयोग अधिकारियों द्वारा कितनी समझदारी, ईमानदारी और व्यवस्थित तरीक़े से किया गया है. अधिकारियों को किसी योजना के तहत ही सरकारी धन दिया जाता है. यह धन उनका निजी धन नहीं है. उस धन का सही तरीक़े से ख़र्च और योजना को सफल बनाना उसका प्राथमिक दायित्व होता है. अब सवाल यह है कि क्या सीएजी का काम सिर्फ़ ऑडिट रिपोर्ट भेजना है. क्या सीएजी का काम यह नहीं कि जहां-जहां ग़लतियां हुई हैं, उसके बारे में संसद को बताया जाए. हैरानी की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी यही मानते हैं कि सीएजी का काम सिर्फ़ ऑडिट करना है. यह सरकार की पॉलिसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती है. यह उन्होंने अपने चुने हुए पांच संपादकों के साथ बातचीत में कहा था. कॉमनवेल्थ गेम्स पर जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सीएजी ने अपनी सीमा लांघ दी है.

अब सवाल यह है कि संविधान में क्या है? भारत के संविधान के मुताबिक़ सीएजी राष्ट्रपति को ऑडिट रिपोर्ट पेश करेगी, जिसे पार्लियामेंट में रखा जाएगा. इससे ज़्यादा संविधान में कुछ नहीं कहा गया. इससे यह नहीं समझा जा सकता है कि आख़िर सीएजी का रोल क्या है. इसे समझने के लिए हमें संविधान सभा की उस बहस को जानना होगा जब इस संस्था को भारत में लागू किया जा रहा था. संविधान निर्माताओं ने सीएजी को बनाने के मक़सद को साफ़-साफ़ शब्दों में कहा है. संविधान सभा में सीएजी को लेकर जो बातें कही गईं उससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि देश के प्रजातंत्र को तानाशाही से बचाने और सरकार को जवाबदेह बनाने का दायित्व न्यायपालिका और सीएजी को दिया गया है. संविधान सभा में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सीएजी को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया था और कहा था कि सीएजी की ज़िम्मेदारी न्यायपालिका से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है. वित्तीय मामलों की सबसे बड़ी निर्णायक सीएजी होनी चाहिए, तब ही शायद देश में स्वराज स्थापित हो सकता है.

यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि संविधान सभा में डॉ. भीमराव अंबेडकर, डॉ. राधाकृष्णन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्वानों ने सीएजी के महत्व और दायित्व को सराहा. संविधान सभा में सीएजी के मामले में दिए गए बयानों में सबसे सटीक बयान है संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का. उन्होंने सीएजी को सुप्रीम कोर्ट जैसा महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि सीएजी का दायित्व न्यायपालिका से कहीं ज़्यादा बड़ा है. संविधान के कई प्रावधानों के ज़रिये सीएजी की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा स्थापित की गई है, लेकिन ग़ौर करने वाली बात यह है कि नियुक्ति के वक़्त सीएजी वैसे ही शपथ लेते हैं जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज लेते हैं. इन दोनों पर संविधान को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी है, लेकिन मंत्री जब शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि वे संविधान के मुताबिक़ काम करेंगे. डॉ. भीमराव अंबेडकर के बयान की रौशनी में यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सीएजी पर यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी के लोग जो दलीलें दे रहे हैं, वह ग़लत हैं.

क़द्दावर कांग्रेसी नेता बी पट्टावी सीतारमैया ने संविधान सभा में कहा कि देश का सीएजी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह स्वतंत्र और आर्थिक मामलों में सुप्रीम होना चाहिए. सीएजी सिर्फ़ ऑडिटर जनरल नहीं है, वह न्यायिक अधिकारी है. वह न्याय की मनोदशा से हर फ़ैसला लेगा, जिसका हर फ़ैसला न्यायपूर्ण होगा. क्योंकि वह यह बताएगा कि क्या सही है और अधिकारियों ने क्या किया है. कभी-कभी उसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ बोलना होगा और उनकी करतूतों का पर्दाफ़ाश करना होगा. इसलिए सीएजी को ऐसे अधिकार मिले हैं, ताकि वह सरकार, किसी राजनीतिक दल या किसी सरकारी विभाग के गुस्से का शिकार न बन सके. हम जब तक एक ऐसे सीएजी का गठन नहीं करते जो आर्थिक मामले का सबसे बड़ा निर्णायक हो, तब तक इस देश में स्वराज नहीं आ पाएगा. बी पट्टावी सीतारमैया के वक्तव्यों से भी यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रधानमंत्री का बयान और संविधान सभा की भावनाओं में बहुत अंतर है.

राजनीतिक दलों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि जिस अमानवीय स्थिति में देश के ग़रीब अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर यह दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में होता तो हिंसक क्रांति को कोई रोक नहीं सकता था. सरकार के पास जो भी पैसा है वह देश की जनता का पैसा है. यह देश की जनता का अधिकार है कि उन्हें यह बताया जाए कि उनके पैसे को किस तरह से ख़र्च किया जा रहा है. देश में लोगों के पैसे की ज़बरदस्त बर्बादी होती है. अगर कोई संस्था इस बर्बादी की जांच करती है, सबूत देती है और फिर भी कोई कार्रवाई न हो तो इसे क्या कहा जाए? क्या चुनाव जीतने से सरकार को तानाशाह बनने की छूट मिल जाती है? हमारे देश में सीएजी यानी कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम यही है. हमारे देश में ऑडिटिंग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा ख़र्च करती है. सरकारी धन के अनुमोदन के लिए तो कड़े क़ानून हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता पर कोई नियंत्रण नहीं है. कहने का मतलब यह है कि सरकारी धन का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं, इसकी जवाबदेही किसी की नहीं है. यही वजह है कि देश में ज़्यादातर योजनाएं विफल हो जाती हैं और किसी को सज़ा नहीं मिलती. अगर सरकारी पैसे के साथ-साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कर दी जाए, तब सरकारी धन को बर्बाद करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है. क़ानून की नज़र में भ्रष्टाचार का मामला तब आता है जब यह तय हो जाता है कि किसी ने घूस ली है या दलाली की है. लेकिन उन मामलों में कुछ नहीं होता है, जहां योजनाएं फेल हो जाती हैं और जनता के करोड़ों रुपये बर्बाद हो जाते हैं. इसलिए क़ानून निर्माताओं ने देश में एक स्वतंत्र सीएजी का गठन किया था. एक मज़बूत सीएजी का गठन कांग्रेस के ही नेताओं ने किया था. यह गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था. यही वह पार्टी है जो संविधान सभा में बहुमत में थी. आज़ादी के 64 साल बाद यह लिखते हुए बुरा लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक झूठ को सच साबित करने की ज़िद में सीएजी जैसी संस्था का राजनीतिकरण कर रही है. इसकी प्रतिष्ठा को नुक़सान पहुंचा रही है. इसका नुक़सान कांग्रेस को ही उठाना होगा. साथ ही इस संस्था की प्रतिष्ठा कम होने से देश को भी नुक़सान होगा. राजनीतिक दल अगर भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो उन्हें सीएजी पर सवाल उठाने की बजाय सीएजी को मज़बूत करने पर ध्यान देना चाहिए.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 24
दिल्ली, 22 अगस्त–28 अगस्त 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001

कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

कई दशकों से स्विट्जरलैंड तीसरी दुनिया के देशों के भ्रष्ट कारोबारियों, अफ़सरों के लिए मुफ़ीद जगह रही है. यह काले धन का स्वर्ग रहा है.



## भ्रष्टाचार

# संप्रभुता पर हमला

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

के. अशोक राव

सामान्यत: भ्रष्टाचार को एक व्यक्ति के अपराध के रूप में देखा जाता है. इस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई एजेंसियां भी बनाई गईं. मसलन, हर एक विभाग में विजिलेंस डिपार्टमेंट, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो और उनके समकक्ष विभाग, जो दोषी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि आख़िर जब कोई मामला सामने आता है तभी इस प्रकार की सक्रियता क्यों दिखाई देती है? इसके बावजूद, इस बात की क्या गारंटी है कि दोषी लोगों को समय पर उचित दंड मिल पाएगा.

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी कोई भी संस्था स्विट्जरलैंड को दुनिया का भ्रष्ट देश मानने को तैयार नहीं होगी. ऐसे में भ्रष्टाचार और ईमानदारी, अली बाबा और चोर तथा गुफ़ा के रक्षकों में कितना फ़र्क़ रह जाता है. कई दशकों से स्विट्जरलैंड तीसरी दुनिया के देशों के भ्रष्ट कारोबारियों, अफ़सरों के लिए मुफ़ीद जगह रही है. यह काले धन का स्वर्ग रहा है. इसी तरह भारत में जहां हर कोई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ईमानदारी की बात कर रहा है, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई ऐसी परिस्थितियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जिसके कारण एक से बढ़कर एक घोटाले हुए. ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस गुफ़ा के ईमानदार रक्षक हैं, जहां तमाम चोर अपनी दौलत जमा करते हैं.

एक कहावत है कि एक चोर ही चोर को पकड़ सकता है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जिसे इस पूरी चोरी के बारे में जानकारी होती है. ज़्यादातर पुलिस अधिकारी और आईएएस अधिकारी दिल्ली में या किसी लोक उपक्रम या सरकारी महकमे के सतर्कता विभाग में जगह पाना चाहते हैं. चूंकि इन अधिकारियों को अपने विभाग की कार्यवाहियों के बारे में जानकारी होती ही नहीं है, जिसकी वजह से वे विजिलेंस व्यवस्था की न तो ठीक से मॉनिटरिंग कर पाते हैं और न ही अपना दायित्व ठीक ढंग से निभा पाते हैं. नतीजतन, इससे भ्रष्ट और भ्रष्टाचार को संरक्षण ही मिलता है. उन दिनों जब ट्रेन पठानकोट से आगे नहीं जाती थी, हम जैसे कुछ छात्र जो श्रीनगर जा रहे थे, जम्मू में रुके. कुछ छात्र जुआ खेलने लगे. अगली सुबह हमें मालूम पड़ा कि हमारा एक साथी 200 रुपये हार गया. 1964 में 200 रुपये बड़ी रक़म होती थी. जब मैं अपने दोस्त से इस बारे में ऐतराज़ जताता तो वह पंजाबी ज़ुबान में मुझसे कहता, क्या परेशानी हो रही है? मेरे पिता पूरी कर देंगे और बिना समय गंवाए मुझे मेरे पैसे दिलवा देंगे. उस घटना ने मेरे इरादे को और मज़बूत कर दिया कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा. मेरे पिता और दादा ने जो सीख दी थी कि कभी भी ग़लत तरीक़े से पैसे मत कमाना, और मज़बूत हुआ. तक़रीबन एक साल बाद जब मैं एक को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में अध्यक्ष के रूप में था, तब वहां के सदस्यों ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं रजिस्ट्रार कार्यालय में हो रही वित्तीय अनियमितता ख़ासकर रिश्वत देने के मामले में अपनी सहमति ज़ाहिर करूं. मैंने कहा, मैं अपने सामने हो रही घूसख़ोरी और सौदेबाज़ी को ज़्यादा दिनों तक सहन नहीं करूंगा. ऐसे में इस संस्था की अध्यक्षता मुझसे और नहीं होगी. अपनी इस चिंता के बाद मैं रजिस्ट्रार कार्यालय गया. वहां कार्यरत एक महिला आईएएस अधिकारी को मैंने अपनी स्थिति के बारे में समझाया और उन्हें सभी दस्तावेज़ सौंपे. दस दिनों बाद जब मैं वापस लौटा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ख़ुशी है कि तुम जैसे लोग आज भी हैं. आम लोगों में मौजूद स्वार्थ उन्हें कुछ भी गलत करने को मज़बूर कर देता है. लिहाज़ा वे ग़लत चीज़ों से समझौता कर लेते हैं बिना यह सोचे–समझे कि इसका परिणाम क्या होगा? ये वही लोग हैं जो व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं. सामाजिक आंदोलन का अभाव दुराचार को खुला निमंत्रण देता है. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनेताओं में महत्वाकांक्षा नहीं थी. उनका स्वार्थ महान कार्य के लिए था. इस वजह से उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और उन्हें कारावास की सज़ा भी हुई, लेकिन मौजूदा शासन में हेराफेरी और लूटपाट करने की पूरी आज़ादी है. आज राज–नेताओं में इच्छाशक्ति का अभाव है. राजनीति जनसेवा कम, उद्यम ज़्यादा हो गई है. जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव शासन प्रक्रिया दुरुस्त करने के लिए करती है, लेकिन पारदर्शिता न होने की वजह से अराजकता ज़्यादा है. दरअसल, भ्रष्टाचार की मूल वजह हमारी त्रुटिपूर्ण चुनाव प्रणाली है. इस समस्या पर चर्चा करने की ज़रूरत है. आज भारत की सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देना संभव नहीं है. इसके पास अदालत की अवमानना का अधिकार है, जिसका इस्तेमाल जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वालों के ख़िलाफ़ किया जा सकता है. अब से पहले न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात इतनी मज़बूती से कभी महसूस नहीं की गई.

समाज के अन्य अंग जैसे ट्रेड यूनियन भी एक सौदेबाज़ एजेंट की भूमिका में आ गए हैं. वे भी आज के प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते हैं. नतीजतन, आर्थिक नीतियों में आए बदलाव की वजह से बिगड़ी परिस्थितियों में सुधार के लिए कोई भी क़दम उठा पाने में ट्रेड यूनियन असफल साबित हो रही है. इसके साथ, यह न तो इस विधायी या प्रशासनिक संरचना में बदलाव ला पा रही है जिसकी वजह से आए दिन घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं.

ऐसा नहीं है कि इस मामले की पहुंच मीडिया तक नहीं है. लेकिन जिस तरह आज पूंजी का प्रवाह है, उसने मीडिया को भी अपने अधीन कर लिया है. ऐसे हालात में, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अख़बार भी एक संपादक की ज़रूरत महसूस नहीं करता, सिवाय एक प्रतीकात्मक और क़ानूनी आवश्यकता के. मौजूदा समय में पेड न्यूज शायद मीडिया के उद्देश्य पर अंतिम हमला है. किसी भी राज्य की राजधानी या प्रमुख शहर में जाएं, वहां प्रमुख रूप से पत्रकारों, राजनेताओं और नौकरशाहों को भूमि आवंटित की जाती है. इसमें पत्रकारों की सांठगांठ नौकरशाहों से होती है और वे उसकी सराहना करते नज़र आते हैं. आर्थिक परिवर्तन के साथ एक नया शब्दकोश है नागरिक समाज. हर 600 भारतीयों के लिए एक ग़ैर सरकारी संगठन है. ग़ैर सरकारी संगठनों के दायरे काफ़ी फैल चुके हैं. यह एक धंधा बन चुका है, उनमें चारित्रिक और संगठनात्मक अभाव है. तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनी और भ्रष्ट ठेकेदार इसके लिए लॉबी कर रहे हैं. नई आर्थिक नीतियों की वजह से यह संगठन फलफूल रहे हैं. सरकार सामाजिक क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें करोड़ों रुपये का दान दे रही है. भारत में शिक्षा व्यवस्था लगातार कमज़ोर होती जा रही है. सुविधाओं के नाम पर भारत की चिकित्सा परिषद और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रमुख निकायों में भी कदाचार के मामले सामने आ रहे हैं. तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा में विनियमितीकरण एक उदाहरण है. अधिक पैसे कमाने की लालच में आज कई लोग जेल में हैं. जिस खंभे पर हमारी संसद, न्यायपालिका, मीडिया, ट्रेड यूनियनें टिकी हैं वह धीरे–धीरे कमज़ोर होता जा रहा है. ऐसे में सिविल सोसायटी पर समाज में एक बेहतर वातावरण क़ायम रखने की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है. यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि 1991 में जब नव उदारवाद का दौर शुरू हुआ और पूंजी का प्रवाह तेज़ हुआ. इसके फलस्वरूप नए आर्थिक युग की शुरुआत हुई, यह वही दौर था जब डॉ. मनमोहन सिंह तत्कालीन वित्तमंत्री थे. उसके बाद से ही हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार में बेतहाशा वृद्धि हुई.

होनोर डी बजेक की प्रसिद्ध कहावत है– हर बड़ी सफलता के पीछे एक बड़ा अपराध है. आज के भारत में यह कहावत पूरी तरह समीचीन है. यदि आज पूंजीपतियों को बॉम्बे प्लान बनाने के लिए कहा जाता तो वे एक ऐसा प्लान बनाते हैं, जो उस माफ़िया द्वारा लिखा, सुझाया गया होता है जिसने सोवियत संघ के टूटने के बाद लोगों की संपत्ति को लूटा था. औद्योगिक विकास के लिए निजी क्षेत्रों में जमशेदजी टाटा, जी.डी. बिड़ला आदि बड़े पूंजीपतियों ने काफ़ी काम किया. इससे भारत की औद्योगिक तस्वीर बदल गई. जीडी बिड़ला ने आत्मनिर्भरता पर ज़ोर दिया, लेकिन आज के दौर में अंबानी बंधु भारत की प्राकृतिक संपदा को निजी संपत्ति मान बैठे हैं, जहां उनके विवाद उनकी मां सुलझा रही है. बेल्लारी के रेड्डी बंधु अपने अवैध खनन के बिजनेस से एक निर्वाचित सरकार को हिलाने का माद्दा रखने लगे हैं. एक राजनेता के बेटे ने रॉबिनहुड की तर्ज़ पर राज्य में नई योजना की शुरुआत की. योजना थी, हर एक योजना में एक घोटाला.

हम यह सच भूल गए हैं कि भारतीय राज्य ने अर्थव्यवस्था और भौगोलिक क्षेत्र के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आधार बनाकर नीति तैयार की थी. लेकिन अब सार्वजनिक उपक्रमों को ही नज़रअंदाज़ किया जा रहा है. बाक़ायदा इसके लिए क़ानून तक बनाए जा रहे हैं. ऐसा भी नहीं है कि इस ख़ालीपन को निजी कंपनियां भर रही हों. यहां फ़ायदे का निजीकरण हो रहा और घाटे का राष्ट्रीयकरण. यही सोच सार्वजनिक संपत्ति को लूटने और घोटालों के लिए एक उपजाऊ ज़मीन तैयार कर रही है. नए आर्थिक परिपेक्ष्य में समाजवादी देशों ने पूंजीवाद के साथ एक प्रयोग किया, जिसका उदाहरण तत्कालीन सोवियत संघ सहित विश्व के कई देशों में देखने का मिला. इस संदर्भ में रशिया में आईएमएफ के रिकॉर्ड के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता और विश्व बैंक पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार युसूफ़ स्टिगलिट्ज कहते हैं कि स्थिरता के लिए मैक्रोइकोनॉमिक्स पर ज़्यादा ज़ोर था. निजीकरण को पीछे धकेला गया, वह भी बिना किसी सही विनियामक फ्रेमवर्क के. पश्चिमी सलाहकार यह ग़लत सोचते हैं कि निजीकरण की वजह से संपत्ति के अधिकार की रक्षा की मांग उठेगी. उन्होंने यह भी कहा कि तीसरी दुनिया में निजीकरण असल में घूसख़ोरी के रूप में ही पनपा.

भारत के संदर्भ में वित्तीय क्षेत्र में सुधार समिति के प्रमुख और शिकागो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रघुराम जी. राजन कहते हैं कि रूस के बाद सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या भारत में है. राजन का कहना है कि बेशक, हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुक़ाबले कम है, लेकिन रूस की तुलना में असाधारण रूप से हमारी हालत इतनी लचर नहीं है. आय और धन के मामले में तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता. मिसाल के तौर पर ब्राजील में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में उनकी हालत अच्छी नहीं है. वहां केवल 18 अरबपति हैं, जर्मनी में तीन हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या ज़्यादा है.

**होनोर डी बजेक की प्रसिद्ध कहावत है- हर बड़ी सफलता के पीछे एक बड़ा अपराध है. आज के भारत में यह कहावत पूरी तरह समीचीन है. यदि आज पूंजीपतियों को बॉम्बे प्लान बनाने के लिए कहा जाता तो वे एक ऐसा प्लान बनाते हैं, जो उस माफ़िया द्वारा लिखा, सुझाया गया होता है जिसने सोवियत संघ के टूटने के बाद लोगों की संपत्ति को लूटा था. औद्योगिक विकास के लिए निजी क्षेत्रों में जमशेदजी टाटा, जी.डी. बिड़ला आदि बड़े पूंजीपतियों ने काफ़ी काम किया. इससे भारत की औद्योगिक तस्वीर बदल गई. जीडी बिड़ला ने आत्मनिर्भरता पर ज़ोर दिया, लेकिन आज के दौर में अंबानी बंधु भारत की प्राकृतिक संपदा को निजी संपत्ति मान बैठे हैं.**

**ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी कोई भी संस्था स्विट्जरलैंड को दुनिया का भ्रष्ट देश मानने को तैयार नहीं होगी. ऐसे में भ्रष्टाचार और ईमानदारी, अली बाबा और चोर तथा गुफ़ा के रक्षकों में कितना फ़र्क़ रह जाता है. कई दशकों से स्विट्जरलैंड तीसरी दुनिया के देशों के भ्रष्ट कारोबारियों, अफ़सरों के लिए मुफ़ीद जगह रही है. यह काले धन का स्वर्ग रहा है. इसी तरह भारत में जहां हर कोई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ईमानदारी की बात कर रहा है, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई ऐसी परिस्थितियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जिसके कारण एक से बढ़कर एक घोटाले हुए. ऐसे में प्रधानमंत्री उस गुफ़ा के ईमानदार रक्षक हैं, जहां तमाम चोर अपनी दौलत जमा करते हैं.**

*(लेखक एनसीओए के अध्यक्ष हैं और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के सलाहकार हैं)*

feedback@chauthiduniya.com

मणिपुर विधानसभा चुनाव अगले साल फ़रवरी में होने हैं. ऐसे में जातियों के बीच तनाव या झगड़े का मक़सद राजनीतिक दलों का ध्यान आकृष्ट करने का भी होता है.

# मणिपुर जातीय तनाव की चपेट में

**देश के सुदूर उत्तर-पूर्व राज्यों की सुध लेने वाला कोई नहीं है. राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी इस बारे में गंभीर नहीं है. कम से कम पिछले एक सप्ताह से मणिपुर को जोड़ने वाली लाइफ लाइन यानी एनएच 53 और 39 की आर्थिक नाकेबंदी से तो ऐसा ही लग रहा है. मामला सदर हिल्स डिस्ट्रिक बनाने की मांग का है. आम आदमी परेशान है, लेकिन राज्य सरकार इस सब से मानो बेख़बर है. आख़िर, मणिपुर इस जातीय तनाव से कब मुक्त होगा?**

एस. बिजेन सिंह

सदर हिल्स डिस्ट्रिक की मांग धीरे-धीरे तूल पकड़ रही है. लोग सड़क पर उतर रहे हैं. महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं. शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही है. कई गाड़ियां जलाई गईं, एनएच 53 के बीचोंबीच खुदाई कर रखी है. पेसेंजर बस सेनापति ज़िले में फंसी रही. सामान लाने वाली गाड़ियां सिक्युरिटी द्वारा कोहिमा से उखूल ज़िले के जेसामी होते हुए इंफाल लाई जा रही हैं. पुलिस लाचार है. इस इकोनॉमी ब्लॉकेड से आम जीवन प्रभावित हो रहा है. रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग होने वाले सामान की कमी से वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं. किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं.

मणिपुर में छोटी-छोटी जातियों के बीच सांप्रदायिक तनाव हमेशा होता रहा है. इस बार फिर सदर हिल्स डिस्ट्रिक डिमांड कमेटी ने सदर हिल्स डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग की है और जिसे लेकर प्रदेश में काफ़ी तनाव है. 31 जुलाई की रात से मणिपुर के दोनों राष्ट्रीय राज्यमार्ग (एनएच 53 और 39) नाकेबंदी शुरू हो गई थी. इस दौरान एक छात्र समेत पांच लोगों की मौत हो गई. 10 सरकारी ऑफिस भी जलाए गए, जिनमें सपरमैना स्थित डीआई ऑफिस के गोडाउन, ट्राइवल डेवलपमेंट ऑफिस और साइकुल स्थित एसडीओ ऑफिस आदि शामिल हैं. एनएच 53 में स्कोर्ट के लिए गई एक गाड़ी खाई में गिर गई और छह एमआर (मणिपुर रायफल्स) के जवान घायल हो गए. खाने-पीने का सामान ढोकर आ रही 150 गाड़ियां एनएच 53 में फंसी हुई हैं.

मणिपुर विधानसभा चुनाव अगले साल फ़रवरी में होने हैं. ऐसे में जातियों के बीच तनाव या झगड़े का मक़सद राजनीतिक दलों का ध्यान आकृष्ट करने का भी होता है. सेनापति ज़िले को दो टुकड़ों में तोड़ कर सदर हिल्स ज़िला बनाने की यह मांग काफ़ी समय से की जा रही है. सदर हिल्स डिस्ट्रिक डिमांड कमेटी कुकियों की है. सदर हिल्स एरिया में नगा जाति अधिक संख्या में है. जब 1992 में नगा और कुकी जातियों के बीच लड़ाई हुई थी, तब से दोनों जातियों के बीच हमेशा तनाव बना हुआ था. भले ही दोनों जातियों के बीच बाहरी दिखावा हो, मगर उन दोनों का पॉलिटिकल एजेंडा अलग-अलग है. घाटी स्थित बड़ी आबादी वाली मीतै जाति भी दोनों जातियों के बीच की लड़ाई में कुछ नहीं बोल रही है. मीतै ने सदर हिल्स डिस्ट्रिक बनाने की मांग पर अभी तक कोई राय ज़ाहिर नहीं की है. मगर सेनापति ज़िले में बसी नगा जाति का दावा है कि यह ज़िला केवल उन लोगों का है. इसलिए यह ज़िला उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं बन सकता. सदर हिल्स डिस्ट्रिक बनाने में सबसे ज़्यादा आपत्ति नगा जाति को है. अगर नगा जाति का विरोध नहीं होता तो सदर हिल्स डिस्ट्रिक बहुत पहले बन गया होता. कुकी जाति की उप जातियां- आइमोल, अनाल, चोथे, चीरू, गांटे, मार, कोइरेंग, कोम, लमकां, लूसाइ, मोयोन, मोनशांग, पाइटे, थादौ, वाइफै, पुरुम, जौ आदि शुरुआत से ही मणिपुर में रह रही थीं. मणिपुर के राजा नरसिंह के समय से ये कुकी उप जातियां पहाड़ों पर बसने लगी थीं. उन लोगों की मदद से राजा नरसिंह की सैन्य ताक़त में और भी बढ़ोतरी हुई थी. ऐसा माना जाता है कि कुकी जातियां म्यांमार के चितांगों पहाड़ों से आई हैं. वह मणिपुर के राजा से दोस्ती कर मोयरांग नामक जगह पर बस गई थीं. माउ सब डिविजन से कुछ जगह, तमेंगलोंग से कुछ गांव, सेंट्रल इंफाल ज़िले से कुछ इलाक़े निकाल कर सदर हिल्स बनाया था. सदर हिल्स में दो तिहाई तो नगा जाति बसी हुई है. इसलिए कुकी होमलैंड बनाने की बात को लेकर नगा जाति परेशान रहती है. इस तरह नगाओं के मालिकाना होने के बाद भी सदर हिल्स डिस्ट्रिक बनाने की कुकियों की यह मांग एंटी नगा पॉलिसी मानी जा रही है.

आख़िर इस तरह के जातीय तनाव पर सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए, अन्यथा धीरे-धीरे यह जातीय तनाव पूरे प्रदेश में भी फैल सकता है. सदर हिल्स डिस्ट्रिक डिमांड कमेटी को नगा संगठनों से बातचीत करनी चाहिए, ताकि हल का रास्ता निकल आए.

sbijensngh@gmail.com

### नगाओं की अनुमति के बिना सरकार फ़ैसला नहीं कर सकती : एस.डी.एस.ए.

सदर हिल्स को पूर्ण ज़िला बनाने को लेकर हो रही मांग पर सेनापति डिस्ट्रिक स्टूडेंट एसोसिएशन ने कहा कि राज्य सरकार नगाओं की अनुमति के बिना निर्णय लेगी तो उसके बाद जो भी घटना घटेगी, उसकी ज़िम्मेदारी मणिपुर सरकार की होगी. सदर हिल्स डिस्ट्रिक डिमांड कमेटी 31 जुलाई से एनएच 39 और 53 की आर्थिक नाकेबंदी कर आम जनता को ज़्यादा परेशान कर रही है. मेडिकल एंबुलेंस पर पथराव करना, श्राद्ध कर्म पर जाने वाली गाड़ी रोकना और स्कूली बच्चों की गाड़ी रोकना, परीक्षा के लिए जा रहे छात्रों को रोकना, ये सब ग़लत है. एसडीएसए ने कहा कि मानवीय मुद्दों पर छूट देनी चाहिए. नगाओं के हक़ को नकारते हुए अगर ज़िला बनाया तो जातियों के बीच काफ़ी तनाव पैदा होगा, इसलिए सरकार सही निर्णय ले.

# राज्यपाल की चौखट पर लोकायुक्त की दस्तक



अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं. राज्य सरकार की बेरुख़ी के कारण भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई नहीं हो रही है. भ्रष्टाचार के क़रीब 80 मामले ऐसे हैं, जिनमें राजनेताओं और नौकरशाहों के ख़िलाफ़ सरकार और शासन की तरफ़ से कोई क़दम नहीं उठाया गया है. अब आहत लोकायुक्त ने राज्यपाल बीएल जोशी की चौखट पर भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ दस्तक दी है. लोकायुक्त द्वारा राज्यपाल को भेजे गए प्रतिवेदन में तीन मंत्रियों, एक सांसद, एक विधायक, चार पूर्व विधायकों, ग्यारह निकाय अध्यक्ष, तीन आईएएस अधिकारियों सहित कई बड़े लोगों के नाम शामिल हैं. मंत्रियों के ख़िलाफ़ जांच आगे बढ़ाए जाने का आदेश सरकार को देना है, जबकि नौकरशाहों के ख़िलाफ़ मुख्य सचिव को अनुमति देनी है, लेकिन दोनों ही स्तरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी.

बहरहाल, भले ही बढ़ी संख्या में भ्रष्ट मंत्रियों और नौकरशाहों के ख़िलाफ़ जांच का आदेश लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन के महरोत्रा को नहीं मिला हो, लेकिन माया सरकार के दो मंत्री ज़रूर लोकायुक्त की जांच में फंस गए हैं. भ्रष्टाचार के ताज़ा मामलों में फंसे राज्य मंत्री अनीस अहमद ख़ां के ख़िलाफ़ आरोप साबित होने के बाद लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री मायावती को रिपोर्ट सौंप दी है, जबकि राज्यमंत्री अवधपाल सिंह के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की जांच क़रीब-क़रीब पूरी हो चुकी है. लोकायुक्त स्तर से चल रही जांच में भ्रष्टाचार के पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया है. जल्द ही मंत्री अवधपाल सिंह के ख़िलाफ़ जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने की संभावना है. वैसे अवधपाल पहले मंत्री नहीं हैं, जो लोकपाल के दायरे में आए हों. इससे पहले राज्य सरकार के चार अन्य मंत्रियों के ख़िलाफ़ लोकायुक्त के स्तर से भ्रष्टाचार की जांच हो चुकी है, जिसमें कुछ माह पहले लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट पर राज्य सरकार के धर्मार्थ कार्य मंत्री राजेश त्रिपाठी को मुख्यमंत्री मायावती ने मंत्रिमंडल से हटा दिया था. इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्र, बेसिक शिक्षा मंत्री धर्म सिंह सैनी तथा राकेश धर त्रिपाठी के ख़िलाफ़ भी भ्रष्टाचार की जांच लोकायुक्त स्तर से हुई थी, जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री धर्म सिंह सैनी के ख़िलाफ़ आरोप साबित होने पर जांच रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी जा चुकी है, जबकि रंगनाथ मिश्र के ख़िलाफ़ जांच चल रही है. इसके अलावा राकेश धर त्रिपाठी के ख़िलाफ़ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण जांच बंद की जा चुकी है.

भ्रष्टाचार के ताज़ा मामले में जांच में फंसे राज्यमंत्री अवधपाल सिंह पर एटा और आसपास के जनपदों में पशु चिकित्सालय का ठेका अपने बेटों को दिलाने तथा वसूली के आरोप हैं. सरकार के इस मंत्री के ख़िलाफ़ सुबोध यादव ने कुछ माह पहले लोकायुक्त के यहां मामला दर्ज कराया था. राज्यमंत्री के ख़िलाफ़ अपने बेटों को पशु चिकित्सालयों का ठेका दिलाने तथा अवैध वसूली के आरोपों पर लोकायुक्त के स्तर से मौक़े पर जाकर छानबीन की गई, जिसमें सरकार के इस मंत्री के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के पुख्ता साक्ष्य



राकेश धर



धर्म सिंह सैनी



अनीस अहमद ख़ां



रंगनाथ मिश्र

लोकायुक्त को मिले थे. अवधपाल के ख़िलाफ़ जांच क़रीब-क़रीब पूरी हो चुकी है और अब लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा को राज्य सरकार के इस मंत्री के जवाब का इंतज़ार है. जांच में भ्रष्टाचार की जो बातें साबित हुई हैं, उस पर लोकायुक्त कार्यालय मंत्री को अपना पक्ष रखने का मौक़ा देना चाहता है. इसके बाद लोकायुक्त के यहां से जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी. इधर, माया सरकार के मंत्री अनीस अहमद के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार साबित होने के बाद लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री मायावती को रिपोर्ट सौंप दी है. रिपोर्ट में मंत्री पर विधायक निधि में 80 लाख रुपये की गड़बड़ी का आरोप साबित हुआ है. लोकायुक्त की जांच पर मंत्री ने विधायक निधि में गड़बड़ी का ठीकरा सीडीओ के सर पर फोड़ दिया था.

लोकायुक्त के दायरे में आने के बाद मायावती के क़रीबी और काबीना मंत्री अवधपाल की कुर्सी खिसकती नज़र आने लगी है. यही हाल दबंग काबीना मंत्री कुशवाहा का भी है. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बसपा सुप्रीमो क़दम फूंक-फूंक कर रख रही हैं. अवधपाल सिंह यादव की बात की जाए तो उन्होंने अपनी हरकतों से बसपा सरकार का असली चेहरा ही उजागर किया है. संगीन आरोपों के घेरे में आए सूबे के पशुधन एवं दुग्ध राज्यमंत्री अवधपाल को लोकायुक्त जस्टिस एनके मेहरोत्रा किसी भी हालत में राहत देने के मूड में नहीं हैं. लोकायुक्त ने साफ़ कहा है कि यह ट्रिपल मर्डर का मामला है. उधर, लोकायुक्त द्वारा मुख्यमंत्री मायावती को सीडी भेजने की बात सार्वजनिक होने से न सिर्फ़ ज़बरदस्त खलबली मची है, बल्कि अवधपाल को मायावती के दरबार में हाज़िर होकर अपनी सफ़ाई भी देनी पड़ी. माना जा रहा है कि सरकार अपने दामन पर दाग़ न लगने देने के लिए किसी भी समय अवधपाल को बाहर का रास्ता दिखा सकती है. इस पूरे मामले में अहम मोड़ इसलिए आया, क्योंकि लोकायुक्त जस्टिस एनके मेहरोत्रा ने इस आपराधिक वारदात के बाबत दाख़िल की गई सीडी मुख्यमंत्री मायावती के पास भिजवा दी थी. प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध राज्यमंत्री का नाम दबंग और माफ़िया राजनेताओं की फ़ेहरिस्त में शामिल है. अवधपाल पर अपने महकमे व विधानसभा क्षेत्र अलीगंज (एटा) में तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. लखनऊ के सुबोध यादव ने उनके ख़िलाफ़ परिवाद लोकायुक्त के पास दाख़िल किया था. अवधपाल पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर पैतृक गांव में ग्राम समाज की ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने के साथ बेटे को लाभ पहुंचाने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में 21 पशु चिकित्सालय बनवा दिए. सरकारी डेरियों में दूध पैकिंग के काम के ज़रिए अपने परिजनों को फ़ायदा पहुंचाया. इसके साथ ही उन्होंने अलीगंज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में फ़र्ज़ी वोट भी डलवाए थे. मंत्री ने संगीन आरोपों की जांच कर रहे लोकायुक्त को जवाब देने के लिए तीन महीने की मोहलत मांगी थी. इस पूरे मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही का कहना था कि माया सरकार के कुछ मंत्री नहीं पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है. मुख्यमंत्री मायावती से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ लगाम लगाएं, क्योंकि कि वह तो स्वयं ही इस भ्रष्टाचार की जनक हैं. वही सपा के राष्ट्रीय महासचिव मो. आज़म ख़ान ने कहा है कि प्रदेश में न क़ानून है और न ही व्यवस्था.

ज़िला एटा के जयथरा में हुए तीहरे हत्याकांड के ख़िलाफ़ 6 अगस्त को ज़िले की सीजीएम कोर्ट ने बसपा नेता अवधपाल सिंह यादव, एमएलसी चंद्र प्रताप तथा उनके बेटे रंजीत सहित 15 लोगों के ख़िलाफ़ हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.

feedback@chauthiduniya.com

इस साल विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार अंधश्रद्धा निर्मूलन क़ानून पारित कराने पर अड़ी हुई है. हालांकि, अंधश्रद्धा के विरोध में पिछले 31 सालों से कुछ सामाजिक संगठन आंदोलन भी कर रहे हैं.



बिहार

# नवल व रामबदन ने लालू को ललकारा

सरोज सिंह

सही कहा गया है कि वक़्त से बलवान दुनिया में कोई नहीं होता. हर इंसान का वक़्त आता है और चला जाता है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बारे में अगर कहा जाए कि वह इस समय अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन वक़्त से गुज़र रहे हैं तो ग़लत नहीं होगा. लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में हार, मंत्रिमंडल में शामिल न हो पाना, रेलवे पर सीएजी की रिपोर्ट और अब नवल यादव व रामबदन राय का बग़ावती तेवर कभी देश व बिहार की राजनीति के लिए अपरिहार्य बन गए लालू प्रसाद की कमज़ोर पड़ती पकड़ को उजागर कर रहा है. विधानसभा में नीतीश कुमार से करारी शिकस्त खाने के बाद लालू ने छह माह चुप रहकर दिल्ली में गुज़ारे. इस बीच लालू के मंत्री बनने की चर्चाएं पटना से दिल्ली तक तैरती रहीं. लालू लाख कहें कि यह सब अफ़वाह थी, पर दिल्ली में उनके घर आने जाने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह इन दिनों उनके निवास पर मंत्रालय के आवंटन को लेकर बहस चलती रहती थी.

ख़ैर, यह बात तो अब पुरानी हो गई है. ताज़ा चुनौती राजद के भीतर से ही मिली है. मुद्दा बनाया गया है कालेधन व भ्रष्टाचार को और केंद्र में हैं बाबा रामदेव और निशाना बनाया जा रहा है लालू प्रसाद को. दरअसल नवल यादव व रामबदन राय यह कहकर लालू प्रसाद को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि रामदेव को भला बुरा कहना ठीक नहीं है. बाबा रामदेव ने जिस कालाधान व भ्रष्टाचार का मसला उठाया है, उसे देश की जनता का भी व्यापक समर्थन मिल रहा है. इसके अलावा राजद की लड़ाई नीतीश कुमार व कांग्रेस के ख़िलाफ़ है तो बाबा रामदेव की आलोचना करने से क्या मिलेगा. नवल यादव कहते हैं कि लालू प्रसाद को यह साफ़ करना चाहिए कि बाबा रामदेव पर उन्होंने जो टिप्पणी की है, वह उनकी व्यक्तिगत राय है या पार्टी की. अगर राय व्यक्तिगत है तो और बात है, पर अगर राय पार्टी की है तो मेरे जैसे लाखों राजद के लोग कुछ बड़े फ़ैसले लेने को तैयार बैठे हैं. रामबदन राय कहते हैं कि बाबा रामदेव तो कालाधन वापस लाने की बात कह रहे हैं, इसमें ग़लत क्या है. लालू प्रसाद को भी उनके इस अभियान का समर्थन करना चाहिए. राय कहते हैं कि राजद कार्यकर्ताओं का बड़ा समूह चाहता है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने के लिए बड़ा आंदोलन किया जाए, पर बात बाबा रामदेव पर आकर अटक जा रही है. रामबदन राय कहते हैं कि नौ अगस्त के धरने ने यह साबित कर दिया कि कालाधन व भ्रष्टाचार का मसला समाज के हर वर्ग के लोगों को चिंतित कर रहा है. अल्पसूचना पर जितने लोग इस धरने में जुटे थे इससे यह साफ़ होता है कि हम सही रास्ते पर निकले हैं. नवल यादव कहते हैं कि राजद सहित कई दलों के बड़े नेता इस धरने में आना चाहते थे, पर फ़िलहाल एक रणनीति के तहत उनसे अभी शांत रहने को कहा गया है. जैसे-जैसे कारवां आगे बढ़ेगा सभी लोग साथ आते जाएंगे. धरने पर पी के सिन्हा, अलोक हर्ष, डॉ. रविंद्र यादव, मिथिलेश सिंह, महेश्वर यादव, रामदेव सिंह यादव और भोला सिंह की उपस्थिति यह जतलाने के लिए पर्याप्त है कि उनके आंदोलन को हर दल व वर्ग का समर्थन मिल रहा है. धरने से पहले नवल यादव व रामबदन राय को मनाने का पूरा प्रयास किया गया, पर बात नहीं बन सकी. दोनों नेताओं ने मध्यस्थों को साफ़ कह दिया कि उनका आंदोलन लालू के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि कालाधन वापस लाने व भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ है.

**नवल यादव कहते हैं कि लालू प्रसाद को यह साफ़ करना चाहिए कि बाबा रामदेव पर उन्होंने जो टिप्पणी की है वह उनकी व्यक्तिगत राय है या पार्टी की. अगर राय व्यक्तिगत है तो और बात है, पर अगर राय पार्टी की है तो मेरे जैसे लाखों राजद के कार्यकर्ता कुछ बड़े फ़ैसले लेने को तैयार बैठे हैं.**

दरअसल इस पूरी क़वायद के पीछे राजद के भीतर बढ़ रहा असंतोष है. लालू के केंद्र में मंत्री न बन पाने के कारण इस असंतोष को और भी हवा मिल गई. राजद के एक बड़े नेता ने बताया कि लालू के नाम से नीतीश को फ़ायदा होता है और साफ़ कहा जाए तो वर्तमान भूमिका में लालू हम लोगों के लिए ताक़त नहीं, बल्कि कमज़ोरी बन गए हैं. लालू को चाहिए कि वह एक बेदाग़ चेहरे को आगे कर बिहार में बड़े जनआंदोलन का मार्गदर्शन करें. बिहार की जनता अब लालू को अभिनेता नहीं, बल्कि चरित्र अभिनेता के रूप में देखना चाहती है. ऐसा नहीं होने के कारण ही ज़मीन से जुड़े नेता धीरे-धीरे खिसक रहे हैं और नीतीश के ख़िलाफ़ एक मज़बूत विकल्प बनाने में जुट रहे हैं. बताया जा रहा है कि नवल व रामबदन की जोड़ी जल्द ही ज़िलों में घूमकर ज़मीन तलाशेगी और ज़ाहिर है इससे सबसे ज़्यादा नुक़सान राजद का ही होगा. इसके अलावा कहा जा रहा है शंभू श्रीवास्तव से भी उनकी बात हो गई है और जल्द ही ये लोग एक मंच पर आ सकते हैं. केंद्र व राज्यस्तर पर समन्वय समीति का गठन होगा और नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी.

छह अगस्त को राजद के धरने में भी असंतोष साफ़ झलका. जगदानंद सिंह मंच पर नहीं बैठे और धरने के बीच से ही चले गए. सांसद उमाशंकर सिंह तो काफ़ी अरसे से राजद के किसी कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं. जाबिर हुसैन का भी यही हाल है. रघुवंश सिंह हालांकि धरने पर थे, पर बाक़ी समय दूर-दूर ही रह रहे हैं. नवल यादव व रामबदन राय राजद में उत्पन्न इसी परिस्थति का लाभ उठाना चाह रहे हैं. उनकी कोशिश है कि बिहार के लिए नए सिरे से सोचने वाले हर दल के लोग उनके साथ आएं. इसके लिए एक मज़बूत रणनीति बनाई गई है. जल्द ही इसके नतीजे सामने आने लगेंगे. ये नेता लालू प्रसाद के सारे राजनीतिक तिकड़मों को अच्छी तरह समझते हैं इसलिए हर क़दम फूंक-फूंक कर उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी राह में अभी बहुत कांटे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

# जादू टोने पर रोक लगेगी

युधिष्ठिर जोशी

महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री का नाम है शिवाजी राव मोघे. उनके कार्यकाल में महाराष्ट्र में नरबलि और अन्य अमानवीय, अनिष्ट, अघोरी प्रथा व जादू-टोना पर प्रतिबंध लगाने के लिए हाल में संपन्न विधान मंडल के मानसून सत्र में एक विधेयक लाया गया. हालांकि, मोघे को यहां एक बात स्पष्ट करनी चाहिए कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा की सीमा रेखा कौन-सी है? क्या अब तक शिवाजी राव मोघे ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितने लोगों को अंधश्रद्धा से मुक्त कराया? क्या इस बात का जवाब उनके पास है? इस बारे में उनकी दलील चाहे जो भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि अंधविश्वास आज भी हमारे समाज में बदस्तूर क़ायम है, फिर भला महाराष्ट्र शासन के मंत्री अपवाद कैसे हो सकते हैं. वैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए राज्य सरकार वर्ष 2004 से ही प्रयत्नशील है.

इस विधेयक का नाम महाराष्ट्र नरबलि व अन्य अमानवीय अनिष्ट, अघोरी प्रथा व जादूटोना प्रतिबंध अधिनियम 2011 है. पिछले 10 सालों में अघोरी व अनिष्ट प्रथा के सिर्फ़ 109 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि हत्या, डकैती, बलात्कार के एक लाख आठ सौ छह मामले राज्य में हुए हैं. ये आंकड़े बिहार से भी ज़्यादा है. अंधश्रद्धा के विरोध में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे 2004 में अध्यादेश लाने वाले थे, लेकिन प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल डॉ. मोहम्मद फ़ज़ल ने उस क्रांतिकारी अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था और राज्य सरकार को जनमत जानने की सलाह दी थी. डॉ. फ़ज़ल को उस अध्यादेश से सामाजिक जीवन में किस तरह के बदलाव व उसके क्या दुष्परिणाम होते यह अच्छी तरह से पता था. इस दौरान राज्य में कई मुख्यमंत्री व मंत्री बदले, लेकिन सरकार इस दिशा में कुछ ख़ास नहीं कर पाई.

इस साल विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार अंधश्रद्धा निर्मूलन क़ानून पारित कराने पर अड़ी हुई है. हालंकि, अंधश्रद्धा के विरोध में पिछले 31 सालों से कुछ सामाजिक संगठन आंदोलन भी कर रहे हैं. ऐसे गांव जहां निराकार भगवान की पूजा होती है. उन जगहों पर जहां न तो कोई मंदिर-मस्जिद हो और न ही गिरिजाघर, जहां जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक में कोई धार्मिक अनुष्ठान न हो और उस गांव के पुजारी ब्राह्मण के घर में खाने के लाले पड़े हों. मौलवी और धर्मोपदेशक बेकार बैठे हों, जिस गांव में जादूटोना, करणी और भानामति पर कोई भी विश्वास नहीं करता हो, वहां अगर किसी बिल्ली ने रास्ता काट भी दे तो राहगीर रुकता नहीं है, जहां सब नास्तिक हों उनका ज्योतिष पर कोई यक़ीन न हो, वे पूर्णतः विज्ञानवादी हों, क्या ऐसा आदर्श गांव बनाने की कोशिश प्रो. श्याम मानव और डॉ. नरेंद्र दाभोलकर ने कभी की है?

अगर देखा जाए तो समाज के कथित सुशिक्षित और प्रतिष्ठित लोग ही ज़्यादातर अंधविश्वास के घेरे में हैं. औरंगाबाद में ख़ुल्ताबाद का मारुति, नागपुर टेकड़ी के गणपति, मुंबई का प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर और शिरडी के सांईबाबा मंदिर में दिन-प्रतिदिन लोगों की भीड़ बढ़ रही है. करोड़ों रुपयों का चढ़ावा मंदिर को मिल रहा है. ऐसा नहीं है कि उस भीड़ में सिर्फ़ आम जनता ही होती है. यहां आने वाले लोगों में माननीय मंत्री से लेकर सांसद, विधायक भी होते हैं. इस साल आषाढ़ महीने में राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने पंढरपुर स्थित पांडुरंग भगवान से राज्य में अच्छी बारिश के लिए आशीर्वाद मांगा. हक़ीक़त में श्रद्धा, अंधविश्वास यह व्यक्ति सापेक्ष मामला है. एक ही कुटुंब के कुछ लोग किसी एक पर श्रद्धा रखते हैं, तो उसी कुटुंब के बाक़ी लोग उस व्यक्ति को अविश्वासी समझते हैं, आख़िर ऐसा क्यों है? इसका जवाब विज्ञान भी नहीं दे सकता.

## शिवाजी राव मोघे से कुछ सवाल

- क्या यह क़ानून सिर्फ़ हिंदू समाज के लोगों और उनके देवी-देवताओं और मंदिरों के लिए है?
- क्या हिंदुओं के सभी धार्मिक कर्मकांड और प्रथा का विरोध किया जाएगा?
- क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों और उनके धार्मिक रीति-रिवाज़ों को इससे अलग रखा जाएगा?
- श्रद्धा, अंधश्रद्धा, प्रथा और अनिष्ट प्रथा की स्पष्ट व्याख्या इस विधेयक में क्यों नहीं है?

**अगर देखा जाए तो समाज के कथित सुशिक्षित और प्रतिष्ठित लोग ही ज़्यादातर अंधविश्वास के घेरे में हैं. औरंगाबाद में ख़ुल्ताबाद का मारुति, नागपुर टेकड़ी केगणपति, मुंबई का प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर और शिरडी के सांईबाबा मंदिर में दिन-प्रतिदिन लोगों की भीड़ बढ़ रही है.**

feedback@chauthiduniya.com

पुलिस द्वारा की जाने वाली फ़र्ज़ी मुठभेड़ दयाहीन और अमानवीय हत्या के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध माना जाएगा.



## फ़र्ज़ी एंकाउंटर

# दोषी पुलिसवालों को फांसी हो

डॉ. क़मर तबरेज़

गत दिनों राजस्थान में दारा सिंह की फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे का प्रयोग करते हुए कहा है कि फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में संलिप्त पुलिस वालों को फांसी पर लटका देना चाहिए. दारा सिंह एक संदिग्ध डाकू था, जिसकी राजस्थान पुलिस ने 23 अक्टूबर को एक फ़र्ज़ी मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी. बीते 8 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मारकंडे काटजू और न्यायाधीश चंद्रमोली कुमार प्रसाद की एक पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस को क़ानून का संरक्षक माना जाता है और इनसे यह आशा की जाती है कि वह लोगों की जान की सुरक्षा करेगी, न कि वह उनकी जान ही ले लेगी. दोनों न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा की जाने वाली फ़र्ज़ी मुठभेड़ दयाहीन और अमानवीय हत्या के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध माना जाएगा, और इसके लिए दोषी पुलिसवालों को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए, उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने दारा सिंह की फ़र्ज़ी मुठभेड़ के मामले में शामिल राजस्थान के दो आईपीएस अधिकारियों, अतिरिक्त डीजीपी अरविंद जैन और एसपी अरशद को चेतावनी दी है कि वह या तो आत्मसर्मपण कर दें या फिर सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी की प्रतीक्षा करें.

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी पुलिस वालों के मुंह पर न केवल एक बड़ा तमाचा है, बल्कि उनके लिए एक सीख भी है. पुलिस वाले आख़िर सुधरने का नाम क्यों नहीं लेते? देश के उच्च वर्ग से लेकर छोटे से बड़े आदमी तक अगर पुलिस के बारे में इनकी राय जानने की कोशिश की जाए, तो सबका जवाब पुलिस के प्रति नकारात्मक ही होगा. शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो पुलिस की तारीफ़ करे, और फिर ऐसे में पुलिस द्वारा अंजाम दी जाने वाली फ़र्ज़ी मुठभेड़ों के मामलों ने तो मानो आग में घी का काम किया. इन फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में न केवल बदमाशों, डाकुओं और लुटेरों की जानें गईं, बल्कि देश के बहुत से निर्दोष नागरिक भी मारे गए हैं. इस पर भी हाल यह है कि सैकड़ों फ़र्ज़ी मुठभेड़ों को अंजाम देने के बाद कुछ पुलिस वाले ख़ुद को एंकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाना अधिक पसंद करते हैं. ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा की जाने वाले फ़र्ज़ी मुठभेड़ों के बारे में पहली बार इस तरह के सख्त लहजे का प्रयोग किया हो. देश के न्यायालय पहले भी पुलिस को इस मामले में लताड़ लगा चुके हैं, लेकिन पुलिस है कि उसे कुछ फ़र्क़ ही नहीं पड़ता. दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पुलिस कुछ मामलों में अदालत का सामना ही नहीं करना चाहती. उसे जब यह अहसास हो जाता है कि फ़लां सरग़ना, डकैत या ख़ूंख़ार अपराधी के मामले में अदालती कार्यवाही लंबी हो सकती है, शायद वह अपराधी अदालत द्वारा बरी भी हो जाए, तो वह फिर फ़र्ज़ी मुठभेड़ के कारनामे को अंजाम देती है. चंदन की लकड़ी और हाथी दांत के देश के सबसे बड़े तस्कर वीरप्पन की कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ के मामले में भी शायद पुलिस की यही मानसिकता काम कर रही थी. इन मामलों में कुछ बातें ऐसी भी सामने आई हैं, जब देश के लोगों की आम राय भी कुछ ऐसी ही बनती दिखाई देती है कि फ़लां मुजरिम को कब तक जेल की सलाख़ों के पीछे रखा जाएगा. कब तक अदालतों में उसके ख़िलाफ़ गवाहों–सबूतों को पेश करने की कार्यवाही चलती रहेगी, जबकि सैंकड़ों आंखों ने इसे जुर्म करते हुए देखा है. 2008 के मुंबई हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादी आमिर क़साब के मामले को इसकी ताज़ा मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है. यह भी महज़ इत्तेफ़ाक़ है कि जिस दिन नई दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ी मुठभेड़ के मामले में उपरोक्त बयान सामने आ रहा था, ठीक इसी दिन कश्मीर के पुंछ ज़िले के सोरनकोट सेक्टर में दो विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा फ़र्ज़ी मुठभेड़ का एक और खेल खेला जा रहा था. टेरीटोरियल आर्मी की 156वीं बटालियन के दो पुलिस अधिकरियों नूर हसन और अब्दुल मजीद ने कश्मीर के युवक अबु उस्मान को एक फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मार गिराया, और दावा किया कि उन्होंने लश्करे–तैयबा के डिवीज़नल कमांडर की हत्या कर दी है. बाद में जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो राज्य सरकार के साथ–साथ केंद्र सरकार भी हरकत में आई. रक्षामंत्री ए.के. एंटनी ने सेनाध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह को आदेश दिया कि वह ख़ुद घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच करें और पूरे मामले की रिपोर्ट उन्हें सौंपें.

### विभिन्न राज्यों में फ़र्ज़ी मुठभेड़ों की संख्या

| राज्य | कुल एंकाउंटर |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 120 |
| मणिपुर | 61 |
| पश्चिम बंगाल | 23 |
| तमिलनाडु | 15 |
| मध्य प्रदेश | 15 |
| जम्मू कश्मीर | 14 |
| झारखंड | 13 |
| उड़ीसा | 12 |
| छत्तीसगढ़ | 1 |
| दिल्ली | 6 |

### भारत में फ़र्ज़ी मुठभेड़ों की शुरुआत

भारत में फ़र्ज़ी मुठभेड़ों की शुरुआत 1990 के दशक में मुंबई में हुई, जिसका सिलसिला 2000 के मध्य तक चलता रहा. इस दौरान सैकड़ों फ़र्ज़ी मुठभेड़ों को अंजाम दिया गया और इन्हें अंजाम देने वाले पुलिस अधिकारियों को एंकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से याद किया जाने लगा. पुलिस का यह मानना था कि एंकाउंटर करके वह न्याय प्रक्रिया में तेज़ी ला रही है. हालांकि बाद में यह सोच नकारात्मक होती चली गई. मुंबई को चूंकि अंडरवर्ल्ड का गढ़ माना जाता है, लिहाज़ा बाद में कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आईं कि पुलिस वालों ने अंडरवर्ल्ड से पैसे लेकर किसी व्यक्ति की फ़र्ज़ी एंकाउंटर में हत्या कर दी, तो अदालत ने भी अपनी टिप्पणी में यही कहा कि पुलिस अब जनता की रक्षक न होकर एक पेशेवर क़ातिल बन चुकी है. इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट के फ़ैसले को देखा जा सकता है.

इसी तरह 1984 से 1995 के बीच पंजाब में आतंकवाद जिस समय हावी हो रहा था, उस समय भी पुलिस ने एंकाउंटर के नाम पर सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या की. यही परिस्थिति पिछले कुछ सालों से जम्मू और कश्मीर में भी है, लेकिन चूंकि वहां पर फ़ौज और सुरक्षाकर्मियों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए फ़र्ज़ी मुठभेड़ की घटनाओं में संलिप्त फ़ौजियों या पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कोई सख्त सज़ा का प्रावधान नहीं है. फ़र्ज़ी मुठभेड़ को अंजाम देने का पहलू यह भी है कि पुलिस विभाग को स्पेशल सेल, एस.टी.एफ., एसआईटी आदि के अस्तित्व को बरक़रार रखने, फिर उनके लिए सरकार की तरफ़ से आवंटित लाभ को प्राप्त करने, मीडिया में अपने नाम और झूठी शान को बरक़रार रखने, अपनी बहादुरी की दुकान चलाने के लिए भी ऐसी फ़र्ज़ी मुठभेड़ों को अंजाम देना पड़ता है. फ़ौज के संबंध में भी ऐसे कुछ मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें फ़ौज के कुछ जवानों या अधिकारियों ने भारत सरकार से मैडल प्राप्त करने या फिर पदोन्नति प्राप्त करने के लिए मासूमों की जानें ली हैं, और मीडिया और अन्य सूत्रों से देश को गुमराह किया है.

### फ़र्ज़ी एंकाउंटर का खेल कैसे खेला जाता है

आम तौर पर जब पुलिस को लंबे समय के बाद यह महसूस होता है कि मीडिया में उसकी चर्चा नहीं हो रही है, नेताओं की ओर से उन पर टिप्पणी की जा रही है या फिर पुलिस पर कोई बड़ा सवालिया निशान लगाया जा रहा है, तो ऐसे में वह किसी बड़ी मुठभेड़ को अंजाम देती है. इसके लिए एक बड़ा स्टेज तैयार किया जाता है. पुलिस अधिकारियों द्वारा पूरी कहानी पहले से तैयार कर ली जाती है. पुलिस की स्पेशल सेल के काम का तरीक़ा यह होता है कि वह साधारण वेतन पर कुछ लड़कों को बतौर मुख़बिर अपने साथ जोड़ लेते हैं, फिर उन्हें मोबाइल फोन और सुरक्षा देते हैं. पुलिस के ये मुख़बिर इन इलाक़ों के बेरोज़गार नौजवानों से दोस्ती बढ़ाते हैं, फिर एक ग्रुप तैयार करके फ़र्ज़ी डकैती को अंजाम देने की योजना बनाई जाती है. इसके लिए पुलिस उन्हें क्षेत्रीय स्तर पर आसानी से मिलने वाले हथियार भी उपलब्ध कराती है. इसके बाद पुलिस के ये मुख़बिर नौजवानों के इस ग्रुप को चोरी की हुई कोई गाड़ी दे देते हैं, जिन पर सवार होकर यह ग्रुप इस कथित डकैती को अंजाम देने के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन ये जवान जब वहां पहुंचते हैं तो अचानक वहां पहले से तैनात पुलिस का सामना उनसे होता है, मुठभेड़ होती है, और ये नौजवान मारे जाते हैं. इसके बाद मीडिया वालों को बुलाकर इसका पूरी तरह प्रचार किया जाता है कि फ़लां जगह की पुलिस ने एक बड़े बदमाश को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है. उनके परिवार वालों को भी डरा कर चुप करा दिया जाता है या फिर पैसे देकर भी मृतकों के परिजनों का मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है. इन मामलों की सच्चाई हमारे सामने तब आती है जब इस फ़र्ज़ी मुठभेड़ में किसी प्रभावशाली या अमीर आदमी के घर का कोई सदस्य मारा जाता है, और फिर उसने पुलिस के ख़िलाफ़ अदालत में मुक़दमा दायर कर दिया हो. हैरत की बात तो यह है कि इस तरह के अधिकतर मामलों में पुलिस वाले साफ़ बचकर निकल गए और अदालत में उनके ख़िलाफ़ कोई जुर्म साबित नहीं हो सका. इस संबंध में पुलिस इंस्पेक्टर दयानायक, इंस्पेक्टर प्रफुल्ल भोंसले, सहायक सब इंस्पेक्टर (एआईसी) रविंद्र आगरे, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सचिन हिंदुराॅय वाजे, पुलिस इंस्पेक्टर विजय सालेस्कर, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं. इनमें से कुछ या तो पुलिस अधिकारियों की आपसी रंजिश का शिकार हुए, या फिर किसी आतंकवादी घटना में मारे गए. पुलिस के किसी नामवर एंकाउंटर स्पेशलिस्ट को इसके ही किसी जूनियर अफ़सर ने किसी बड़ी घटना के दौरान गोली मार कर हत्या कर दी, ताकि वह ख़ुद शौहरत और इज़्ज़त के साथ साथ प्रमोशन पा सके. बाटला हाउस एंकाउंटर में मारे गए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत को लेकर कुछ लोगों की ओर से ऐसे आरोप लगाए जा चुके हैं.

feedback@chauthiduniya.com

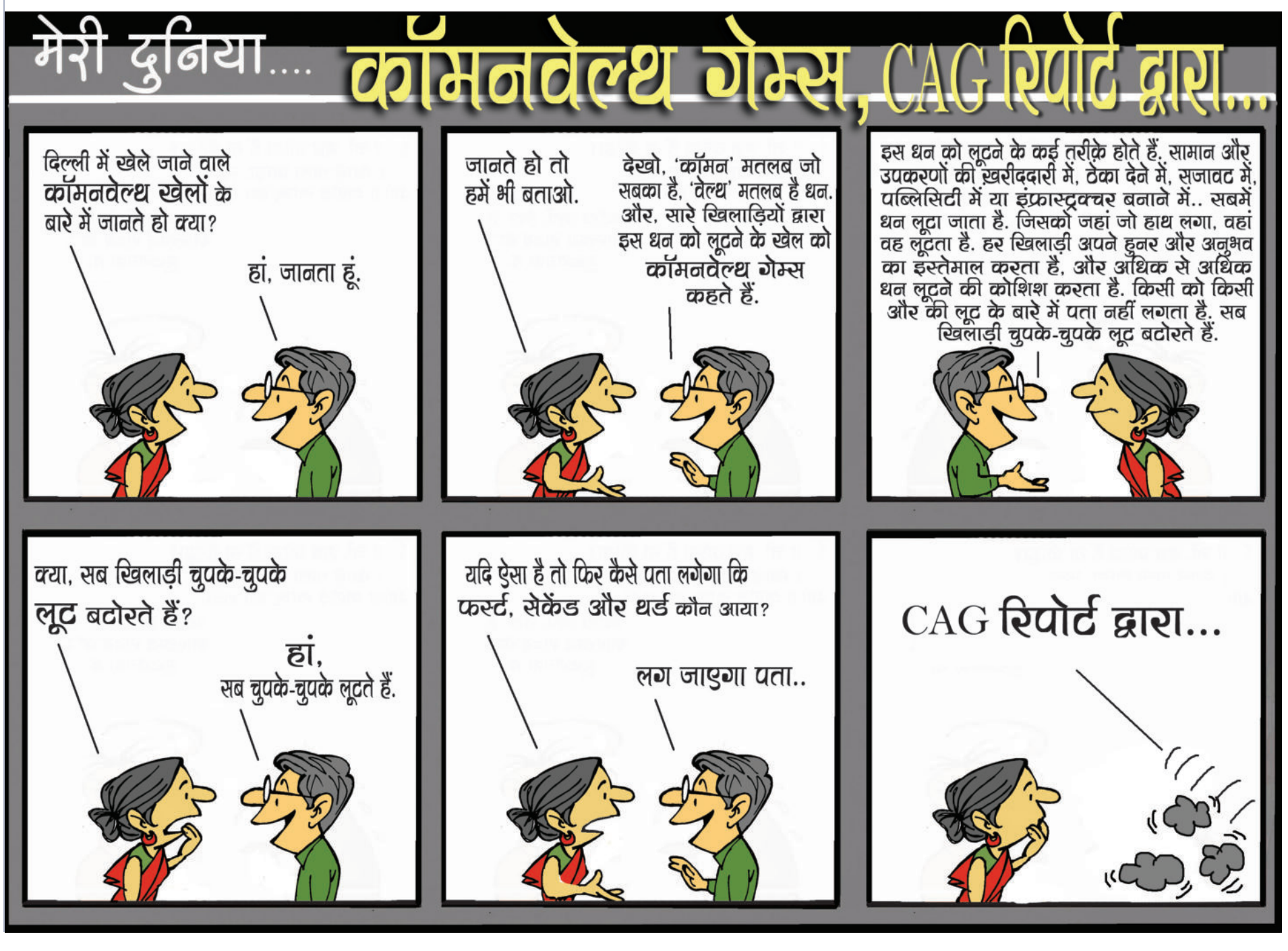

गांधीजी ने इस बात को समझा और खादी को एक आंदोलन का रूप दिया. उन्होंने यह नारा दिया कि यदि भारतीय विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें, तो अंग्रेज़ों को देश से भगाना आसान हो जाएगा.

## खादी ग्रामोद्योग आयोग

# खादी की दुर्दशा का ज़िम्मेदार है

अभिषेक रंजन सिंह

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस खादी को देश में स्वरोजगार पैदा करने का माध्यम बनाया था, उसी देश में आज़ादी के 64 साल बाद खादी ग्रामोद्योग आयोग की हालत बद से बदतर होती जा रही है. हर साल 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को ही खादी के कपड़े नज़र आते हैं. इन अवसरों पर खादी के विकास की अनेक बातें भी की जाती हैं, लेकिन ये तमाम वायदे अब भी अधूरे हैं. खादी ग्रामोद्योग की दुर्दशा उन सरकारों ने ही की है, जिनसे इस संस्था को काफ़ी उम्मीदें थीं. फ़िलहाल देश भर में खादी ग्रामोद्योग आयोग हैं. यह संस्था भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है. मंत्रालय चाहे लाख दावा करे, लेकिन मौजूदा समय में खादी ग्रामोद्योग की हालत संतोषप्रद नहीं कही जा सकती है. खादी ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारी भले ही हालात सही बता रहे हों, लेकिन इन खादी भवनों में क्या-क्या गड़बड़ियां हो रही हैं, उनकी फ़ेहरिस्त काफ़ी लंबी है. यहां कामगारों की दयनीय हालत के अलावा खादी की आड़ में हैंडलूम के कपड़े धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं. इतना ही नहीं बिहार जैसे राज्य जहां खादी ग्रामोद्योग के कई केंद्र हैं, वहां की स्थिति और ज़्यादा ख़राब है. मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, कटिहार और मुंगेर ज़िलों में खादी ग्रामोद्योग पूरी तरह मृतप्राय हो चुके हैं. सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात यह है कि मधुबनी और कटिहार ज़िले में खादी भंडार की ज़मीनों पर भू-माफ़िया का क़ब्ज़ा भी हो चुका है. वहां स्थानीय छुटभैये नेता खादी भंडार के भवनों में अपने निजी कार्य को अंजाम देते हैं. जैसा कि सभी को पता है खादी महज़ एक कपड़ा नहीं, बल्कि यह महात्मा गांधी के विचारों की बुनियाद है. हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, न्यायपूर्ण समता आधारित सामाजिक व्यवस्था का अर्थशास्त्र खादी है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी में कई प्रयोग किए, मसलन खादी की मदद के लिए उन्होंने ग्रामोद्योग बनाया. हालांकि, अब वे प्रयोग बंद हो चुके हैं और खादी की क़ब्र पर ग्रामोद्योग का मेला सजाने के अलावा कुछ ख़ास नहीं किया जा रहा है. अगर आप इस कड़वी सच्चाई को देखना चाहते हैं तो, आपको आयोग के खादी ग्रामोद्योग भवन का रुख़ करना होगा. दिल्ली में कनॉट प्लेस की रीगल बिल्डिंग में यह भवन है. कॉरपोरेट लुक लिए इस खादी भवन में खादी के कपड़े कम और हैंडलूम के उत्पाद ज़्यादा बिक रहे हैं. राजधानी दिल्ली में रहने वाले पुराने लोग, जिन्हें खादी की अच्छी परख है उनका यहां आना लगभग ख़त्म हो चुका है. खादी आश्रम में काम करने वाले कामगार भी इस हक़ीक़त को समझते हैं. इसके कारण उनमें अपने प्रबंधन को लेकर व्यापक असंतोष भी है. वहीं खादी ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों की मानें तो एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने खादी में गुणवत्ता सुधार एवं विकास कार्यक्रम हेतु 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्वीकृति प्रदान की है. आयोग ने पहले ही 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 96 करोड़ रुपये की पहली क़िस्त प्राप्त की है. इस धनराशि की मदद से देश की 300 खादी संस्थाओं में सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाएगा. खादी के उत्पादों की बढ़ती क़ीमतों के बारे में खादी आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि देश में कपास की क़ीमतें बढ़ी हैं और इसकेउत्पादन में कमी आई है, लेकिन उनका यह दावा सही नहीं है. कपास उत्पादन के वर्ष 2011 के आंकड़ों के मुताबिक़ भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक और निर्यातक देश है. वर्ष 2011 में भारत में 27 मिलियन कपास की गांठों का उत्पादन हुआ.

हालांकि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारी संघ का मानना है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तमाम दावे खोखले हैं. दरअसल, यहां नौकरशाही पूरी तरह हावी है. यहां पौधों की जड़ों की बजाय उसके पत्तों की सिंचाई की जा रही है. उनके मुताबिक़ खादी और ग्रामोद्योग आयोग भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ चुका है. वर्कर यूनियन और खादी आयोग के आला अधिकारियों के बीच लंबे समय से संवादहीनता की स्थिति है. इस वजह से चाहे जितनी भी वित्तीय मदद क्यों न मिले, उसका दुरुपयोग होना तय है.

दरअसल, गांधी के देश में खादी की दुर्दशा के लिए वही लोग ज़िम्मेदार हैं, जो गांधी के वचनों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं. आख़िर वह कौन-सी ऐसी ताक़ते हैं, जो खादी ग्रामोद्योग को तबाह करने पर तुली हैं? खादी पर सबसे पहला हमला उस वक़्त हुआ, जब खादी की ख़रीद में दी जाने वाली छूट बंद की गई. देश भर में आज भी तक़रीबन सात हज़ार खादी भंडारों से कुल दस हज़ार परिवारों का भरण-पोषण हो रहा है. वह भी इस यांत्रिक युग में. भारत में खादी और ग्रामोद्योग के तहत चलने वाले 7 हजार केंद्रों पर खादी के कपड़े की सालाना बिक्री 1,000 करोड़ रुपये की है. इसके बावजूद आज हमारे देश में सूती और ब्रांडेड कपड़े पहनने का फैशन चल पड़ा है, लेकिन देश के नौजवानों को खादी की तरफ़ आकर्षित करने के तमाम सरकारी प्रयास निष्फल साबित हुए हैं. इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश में खादी का प्रचार-प्रसार पूरी ईमानदारी के साथ किया ही नहीं गया. इसके लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ही सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है, जिसे बनाने का मक़सद था खादी को देश भर में बढ़ावा देना, लेकिन नतीजा निकला सिफ़र.

सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिहाज़ से भी खादी से बेहतर कोई दूसरा कपड़ा नहीं है. इतना ही नहीं खादी से आज भी कई घरों के चूल्हे जल रहे हैं. इससे गांव के ग़रीब लोगों को रोज़गार मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ़ मिलों में कपड़े बनाने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा भी उत्पन्न हो रहा है. खादी के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला कपास भी हमारे ही देश में उत्पन्न होता है. खादी का प्रचार-प्रसार न होने के कारण खादी की बिक्री लगातार कम होती जा रही है. जिन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम देखा होगा वह गांधी के विचारों एवं खादी से क़ायल हुए बिना नहीं रह सके होंगे. महात्मा गांधी के कमरे में रखे चरखे को देखकर सचमुच एक रोमांच पैदा होता है. दरअसल, गांधी जी ने इसकी मदद से अंग्रेज़ों से मुक़ाबला किया था. तक़रीबन डेढ़ सौ वर्ष पहले जब हमारे देश में कपड़ों की मिलें नहीं थीं, तब यही खादी हमारे तन ढंकने का ज़रिया थी. इस वजह से लाखों लोगों को रोज़गार मिल जाता था. जब यूरोप में यांत्रिक युग शुरू हुआ, तब हालात बदल गए. अंग्रेजों ने अपने देश में बने कपड़े भारत भेजने शुरू कर दिए. इससे खादी का प्रचलन कम होने लगा.

गांधीजी ने इस बात को समझा और खादी को एक आंदोलन का रूप दिया. उन्होंने यह नारा दिया कि यदि भारतीय विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें, तो अंग्रेज़ों को देश से भगाना आसान हो जाएगा. लेकिन उस समय भारतीय मिल मालिकों ने भारतीय कपड़ों की कालाबाज़ारी कर मुनाफ़ा कमाना शुरू कर दिया. गांधीजी ने इस बात को समझा और 1920 में अपने अभियान के दौरान गुजरात के विजापुर में देशी चरखा की मदद से खादी वस्त्र बनाने शुरू किए. इस तरह से खादी को लेकर एक अभियान ही शुरू हो गया. इसके बाद 1947 में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के प्रयासों से खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की स्थापना की गई. हालांकि, इसकी स्थापना तो खादी के विकास के लिए की गई थी, पर उस वक़्त एक भूल के कारण खादी एक अभियान न बन पाई. इस आयोग की ख़ासियत यह थी कि इसका अध्यक्ष कोई उद्योगपति या कोई राजनेता ही होता था. उनका स्वार्थ मिल-मालिकों से जुड़ा होता था. इसलिए वे खादी के बजाय देश में बने सूती कपड़ों का प्रचार करते थे. वे खादी को मिलों के कपड़ों की तुलना में महंगी दरों पर बेचने की सिफ़ारिश करते थे. यह परंपरा आज भी बदस्तूर क़ायम है. नतीजतन खादी आम आदमी और ग़रीबों से दूर होती चली गई. सर्वोदय आंदोलन के जनक आचार्य विनोबा भावे को अपने अंतिम समय में खादी के प्रति सरकार की नकारात्मक भूमिका की जानकारी हो गई थी. इसके मद्देनज़र उन्होंने नारा दिया-खादी को कमीशन नहीं, मिशन बनाया जाए. विनोबा भावे के इस नारे के बाद सरकार ने देश के अनेक हिस्सों में खादी भंडारों की स्थापना की.

**भारत में खादी और ग्रामोद्योग के तहत चलने वाले 7 हजार केंद्रों पर खादी के कपड़े की सालाना बिक्री 1,000 करोड़ रुपये की है. इसके बावजूद आज हमारे देश में सूती और ब्रांडेड पहनने का फैशन चल पड़ा है, लेकिन देश के नौजवानों को खादी की तरफ़ आकर्षित करने के तमाम सरकारी प्रयास निष्फल साबित हुए हैं. इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश में खादी का प्रचार-प्रसार पूरी ईमानदारी के साथ किया ही नहीं गया.**

## मधुबनी खादी भंडार की बदहाली

एक ज़माने में गौरवशाली अतीत के रूप में प्रसिद्ध मधुबनी खादी भंडार से कभी महात्मा गांधी, राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे सहित अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खादी के बेमिसाल कपड़े, धोती, कुर्ता व चादरें भेजी जाती थीं. यहां निर्मित खादी के कपड़े देश केविभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते थे, जिससे यहां के हज़ारों बुनकरों को रोज़ी-रोटी मुहैया होता था. पिछले कई वर्षों से सरकारी सहायता तथा पूंजी के अभाव में ढाई बीघा में फैला खादी भंडार खंडहर हो चुका है. संघ के पदाधिकारियों की गुटबाज़ी ने भी इसे नुक़सान पहुंचाया है. ग़ौरतलब है कि खादी ग्रामोद्योग के तहत यहां मधुमक्खी पालन तथा घरेलू उद्योग पूरी तरह बंद हो गए हैं. यहां चलने वाले कोल्हू से सरसों तेल की ख़रीदारी करने वाले तथा सर्दी के मौसम में यहां रज़ाई बनवाने वालों की भारी भीड़ देखी जाती थी. विभिन्न मौक़ों पर खादी कपड़ों की ख़रीदारी पर ग्राहकों को दी जाने वाली छूट पर रोक लगने से खादी की बिक्री में भारी गिरावट देखी जा रही है. एक दशक पूर्व तक यहां खादी के उत्पादों की बिक्री करोड़ों में होती थी, जो अब घटकर महज़ 10 लाख रुपये तक रह गई है. मधुबनी ही नहीं, देश के अन्य राज्यों के खादी ग्रामोद्योग की भी कमोबेश यही हालत है.

### कामगारों की दलील

सरकार कॉरपोरेट लुक देकर खादी की बिक्री बढ़ाना चाहती है, लेकिन खादी से लोगों का रिश्ता उसके स्टोर की ख़ूबसूरती से नहीं है, बल्कि खादी से भावनात्मक लगाव के कारण है. खादी स्टोर पर जाने वाले ग्राहकों को इस बात का पूरा यक़ीन होता है कि जो वस्तु वे ख़रीद रहे हैं, वह शुद्ध है. खादी ग्रामोद्योग पर वर्षों से क़ायम इस यक़ीन की बरक़रार रखना मौजूदा समय में एक बड़ी चुनौती है. कामगारों का मानना है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग में सरकार की ओर से वर्कर यूनियन की मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता. यहां नौकरशाही इस क़दर हावी है कि मंत्रालय भी आयोग के अधिकारियों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है.

### आशंका

अधिकांश खादी आश्रम में लोग ढाई-तीन दशकों से काम कर रहे हैं. ये सभी सरकार के कर्मचारी हैं. यदि सरकार इसे निजी हाथों में सौंप देती है, तो निश्चित तौर से उनके समक्ष रोज़गार का संकट पैदा हो जाएगा. सरकार को भले ही यह भरोसा हो कि खादी के कारोबार को निजी हाथों में सौंपने से उसका कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन खादी आश्रम में काम करने वाले कर्मचारी इससे सहमत नहीं हैं. दिल्ली के रीगल सिनेमा स्थित खादी आश्रम में काम करने वाले एक कर्मचारी की मानें तो, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय लगातार हो रहे राजस्व घाटे के कारण खादी आश्रम दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और पटना केंद्रों को बंद करने की मंशा ज़ाहिर कर चुका है. खादी को पसंद करने वालों की लंबी फ़ेहरिस्त है. देश के पहले राष्ट्रपति डॉ.राजेंद्र प्रसाद हों या पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी उन सबने खादी को न सिर्फ़ अपनाया बल्कि, खादी ग्रामोद्योग के उद्धार के लिए काफ़ी कुछ किया. फ़िलहाल गांधी की उस विरासत को उनकेही देश में भुलाया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा दौर में भारत सरकार की ग़लत नीतियों की वजह से खादी के साथ वैसा ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो गुलामी के दिनों में होता था.

feedback@chauthiduniya.com

संप्रति भारत में बालिग़ मताधिकार, ख़ासकर जब बहुसंख्यक प्रजा अनपढ़ या अनभिज्ञ है, कोई विशेष मायने नहीं रखता. यह तो अंधेरे में मारी हुई छलांग है.



राजनीति का तिरस्कार नव उदारवादी राजनीति को ही मज़बूत नहीं बनाता, सांप्रदायिक राजनीति को भी वैसा ही मज़बूत करता है.





महावीर प्रसाद आर मोरारका

# न्याय चक्र धनिकों द्वारा संचालित



न्यायालयों में न्याय होता है. कहा जाता है न्याय तो अंधा है, उसके लिए धनी–निर्धन सब बराबर हैं. न्याय के सामने किसी में भेदभाव नहीं होगा, पर वस्तुतः क्या यह सत्य है? पुस्तकों में जो भी क़ानून हैं वे ज़रूर सारे देश के लिए समान रूप से लागू हैं, पर उनका संचालन या नियमन किस ढंग से होता है, ज़रा ग़ौर कीजिए.

आपकी थोड़ी–सी ज़मीन है. आपके पड़ोसी ने मनमानी करके उसका कुछ हिस्सा दबा लिया है. अब आपको न्यायालय में पुकार करनी होगी. कोर्ट फीस भर कर आपने दावा दायर किया. वकील या बैरिस्टर को अच्छी फीस देकर आपने उसे आपकी तरफ़ से दलील करने को तैनात किया. आप या आपके कई पड़ोसियों ने आपकी बात साबित करने के लिए महीनों दौड़–धूप की, कचहरी के चक्कर लगाए. आख़िर साल, दो साल या दस साल बाद मान लीजिए कि न्याय ही हुआ तो, आपकी ज़मीन जो आपके पड़ोसी ने दबा ली थी, वह आपको वापस मिल गई. इस सौदे में आपको जितनी हैरानी या परेशानी उठानी पड़ी वह तो अलग, पर कोर्ट–फी, वकील बैरिस्टर–फी और कचहरी आने–जाने के ख़र्च में आपको शायद ज़मीन की कुल [illegible]

[illegible]

...दूसरे व्यक्ति, चुनाव में उस नामज़द व्यक्ति का खुलेआम विरोध करते हैं.

इस देश में अनुशासन भंग इतने अनुपात में बढ़ गए हैं कि उसकी सीमा ही नहीं, और उसका मूल कारण वही असमान–वित्त–वितरण ही है.

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com



मेघनाद देसाई

# अब बीमारी भी नेताओं का विशेषाधिकार है

सबसे पहले, हम सभी सोनिया गांधी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं. बेशक, हमें यह नहीं बताया गया कि उन्हें कौन सी परेशानी थी. लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसमें सर्जरी करने की ज़रूरत हो और फिर पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए दो से तीन सप्ताह का समय लगे, ज़रूर इसे गंभीर माना जाना चाहिए. यह बेहद अफ़सोस की बात है कि भारत के अभिजात्य वर्ग के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में ज़रूरत से ज़्यादा ही गोपनीयता बरती जाती है. दो साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह की बाईपास सर्जरी हुई थी. इस बारे में अस्पताल और पार्टी के हवाले से विस्तृत जानकारी दी गई थी. अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि सेहत से जुड़ा उनका मामला निजी है, जिसे वह गुप्त रखना चाहते हैं. वहीं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह इस देश की नागरिक ही नहीं हैं, बल्कि भारतीय राजनीति में वह एक निर्णायक व्यक्तित्व हैं. सोनिया गांधी को यह दर्जा महज़ इसलिए हासिल नहीं हुआ है कि उन्होंने राजीव गांधी से शादी की. राजीव की असामयिक मृत्यु के बाद उन्हें पार्टी की ओर से पद की पेशकश की गई, शुरू में उनके लिए यह स्वीकार्य नहीं था, लेकिन सात साल के बाद उन्होंने पद ग्रहण किया और पार्टी को बिखरने से बचाया.

एक लोकतांत्रिक देश में अपने नेताओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कोई पर्दा नहीं होना चाहिए. अमेरिका में एक बार जॉन कैनेडी को कई बीमारियों का सामना करना पड़ा. उन्हें लगातार दवाइयों का सेवन करना पड़ा. लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की भनक किसी को नहीं लगने दी गई. [illegible]

[illegible]

...में भी काफ़ी छूट दी जाती है. मसलन, क़ानूनी प्रक्रिया [illegible] जाने वाली सुविधाएं या फिर आचरण का ही मामला क्यों [illegible] राजनीति की मनोवृति ही ऐसी है जिसमें राजनेताओं चाहे वे [illegible] नगर निगम में पार्षद ही क्यों न हों, को आम आदमी से अ[illegible]

मौजूदा समय में लोकसभा में पेश किए गए लोकपाल [illegible]



[illegible]

feedback@chauthiduniya.com



संतोष भारतीय

## जब तोप मुक़ाबिल हो

# कांग्रेस की चार सदस्यीय कमेटी की अग्नि परीक्षा

श्रीमती सोनिया गांधी अमेरिका में अपनी बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं. उन्होंने हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई. उनकी अनुपस्थिति में पार्टी का सारा काम यह कमेटी देखने वाली है और महत्वपूर्ण फ़ैसले लेने वाली है. इस कमेटी में राहुल गांधी, ए के एंटनी, जनार्दन द्विवेदी और अहमद पटेल हैं. क्रम में देखें तो पहला नंबर राहुल गांधी का, दूसरा अहमद पटेल, तीसरा जनार्दन द्विवेदी और चौथा ए के एंटनी का होना चाहिए. ए के एंटनी इस कमेटी में इसलिए रखे गए हैं, क्योंकि ए के एंटनी को सोनिया गांधी का सर्वाधिक वफ़ादार माना जाता है और दस जनपथ की राय में सबसे हार्मलेस अगर कोई आदमी है तो वह ए के एंटनी हैं, पर इस कमेटी को बनाने में सोनिया गांधी से एक चूक हो गई. चूक सोनिया गांधी की नज़र में नहीं हुई होगी, लेकिन यह चूक कांग्रेस के कार्यकर्ता की नज़र में हुई है. उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं. विधानसभा के चुनाव में जाने या अनजाने में राहुल गांधी ने अपनी साख उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ जोड़ दी है. राहुल गांधी कुछ जगहों पर जा सकते हैं. राहुल गांधी के जाने से चुनाव जीता नहीं जा सकता, हवा बनाई जा सकती है. अगर हवा बनती है तो उसको कंसोलिडेट कौन करेगा. उत्तर प्रदेश में इस समय जो टीम काम कर रही है उसके अगुवा दिग्विजय सिंह हैं, परवेज़ हाशमी हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के नाम आते हैं. अगर इस चार सदस्यीय कमेटी को सोनिया गांधी ने पांच सदस्यीय बना दिया होता और इसमें दिग्विजय सिंह को भी रख दिया होता तो उत्तर प्रदेश के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं में यह संदेश जाता कि दिग्विजय [illegible]

[illegible]

...तो दिल्ली में कम से कम हम यह कहने के लायक़ हो जाएंगे कि हम इतने वोट लाए और आगे इतने वोट लाएंगे. इस तरह दिल्ली के सत्ता के गलियारे में कुछ काम करने या करवाने की हैसियत में आ जाएंगे, पर इससे पार्टी नहीं खड़ी होती, इससे संगठन नहीं बनता. कांग्रेस की मजबूरी यह है कि कांग्रेस संगठन कैसे बनाए, इसके बारे में कांग्रेस नेताओं में ही एक मत नहीं है. एक सीधा रास्ता है. उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के लगभग 20 सांसद हैं. इन 20 सासंदों को अगर उत्तर प्रदेश में ज़िले बांट दिए जाएं और इन

**उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर राहुल गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर किसी का रोल है, तो वह दिग्विजय सिंह हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश के ज़िले–ज़िले में, क़स्बे–क़स्बे में कई मीटिंगें की हैं. वहां पर उन्होंने समीकरण बनाए हैं, कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है. पार्टी को तेज़ गति में लाने के लिए अपनी सारी ताक़त लगा दी, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी भी मूर्छित अवस्था में है.**

सांसदों से कहा जाए कि वे इन्हीं ज़िलों में रहकर ही कांग्रेस का संगठन बनाएं, इन्हीं ज़िलों में रहें. सांसदों के पास संसाधन भी ज़्यादा होते हैं. सांसद साधन इकट्ठा कर सकते हैं. और उस स्थिति में, जो चुने हुए लोग हैं, वे वहां के लोगों की नब्ज़ भी अच्छी तरह समझ सकते हैं. अगर कांग्रेस पार्टी इनका इस्तेमाल करे तो अभी भी पार्टी मूर्छित [illegible]

[illegible]

संपादक
editor@chauthiduniya.com

## भ्रष्टाचार विरोध के बहाने



प्रेम सिंह

# राजनीति का तिरस्कार

मज़ेदार बात यह है कि राजनीति को भ्रष्ट मानने और बताने वाले लोग मनमोहन सिंह को परम ईमानदार और सोनिया गांधी को त्याग की देवी बताते हैं. नव उदारवाद की प्रयोगशाला में जो दो भावी प्रधानमंत्री तैयार हो रहे हैं– राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी – इनसे भी इन सबको कोई शिकवा–शिकायत नहीं है. ख़ुद भी सब राज्यसभा जाने का सपना पाले रहते हैं और इसके लिए आपस में होड़ भी लगाते हैं. राजनीति के शीर्ष पर बैठे नेता प्रशंसा के पात्र हैं, आप ख़ुद पिछले दरवाज़े से संसद में दाख़िल होना चाहते हैं– फिर राजनीति को भ्रष्ट बताने का क्या अर्थ है? मनुष्य की सामाजिकता की कोशिशों को ही हम मानव सभ्यता कहते हैं. आधुनिक काल में सामाजिकता के निर्धारण का काम राजनीति करती है. इसी तरह सामाजिकता की भूमिका और स्वरूप राजनीति को नकार कर नहीं बन सकते. तभी लोहिया ने राजनीति को अल्पकालिक धर्म और धर्म को दीर्घकालिक राजनीति कहा है.

नव उदारवाद में हर चीज़ की कसौटी मुनाफ़ा और इसे कमाने का अखाड़ा बाज़ार है. सामाजिकता का भी इसका वही पैमाना है, जिसमें भारत सहित दुनिया की अधिकांश आबादी का [illegible]



[illegible]

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं समाजवादी चिंतक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

# पाठकों की दुनिया

## सर्वश्रेष्ठ पत्र

### राज़ ही रहेगा काला धन

काले धन पर मचे बवाल के मद्देनज़र भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड सरकार से एक क़रार किया है. इसके तहत इस क़ानून के बनने के बाद स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा काले धन की जानकारी मिल सकेगी, लेकिन समस्या वही की वही है, क्योंकि सिर्फ़ उन्हीं खातों की जानकारी मिल सकेगी, जो इस क़ानून के लागू होने के बाद खोले जाएंगे. पूर्व में खुले खातों की जानकारी नहीं दी जा सकेगी. सरकार ने अपने इस काम से सांप भी मर गया, और लाठी भी नहीं टूटी वाली कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है. विपक्ष इस मुद्दे पर ख़ामोश है. बहरहाल, इस क़रार से कई चेहरे बेनक़ाब होने से बच गए.

*आदिल ख़ान, ओखला, नई दिल्ली*

### महंगाई से जनता बेहाल

[illegible]

### बेशर्म भ्रष्टाचार

[illegible]

### जल संकट की चुनौती

[illegible]

### यमुना का संघर्ष

[illegible]

### धर्म का धंधा

[illegible]

### जनता से धोखा

[illegible] कुछ ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर इस योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं. अगर ऐसा होता है तो देश का हर नागरिक निजी कंपनियों के मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा बन जाएगा. यह देश की जनता के साथ किसी धोखे से कम नहीं है.

**फ़िरोज़**, *ईमेल से*

राजकमल प्रकाशन समूह

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

ख़तरे के पैमाने के तौर पर सिगरेट पीने, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल पर ज़ोर दिया, क्योंकि दिल की बीमारी केलिए ये ही ख़तरनाक माने जाते हैं.



सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

# अपील व शिकायत के फ़र्क़ को समझें

आरटीआई क़ानून के तहत शिकायत का क्या अर्थ होता है. शिकायत कब, कहां और कैसे दाख़िल की जाती है. दरअसल, अपील और शिकायत में एक बुनियादी फ़र्क़ है. कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने आरटीआई आवेदन में जो सवाल पूछा है उसका जवाब आपको ग़लत दे दिया जाता है. और, आपको पूर्ण विश्वास है कि जो जवाब दिया गया है वह ग़लत, अपूर्ण या भ्रामक है. इसके अलावा, आप किसी सरकारी महकमे में आरटीआई आवेदन जमा करने जाते हैं और पता चलता है कि वहां तो लोक सूचना अधिकारी ही नियुक्त नहीं किया गया है. या फिर आपसे ग़लत फीस वसूली जाती है. तो, ऐसे मामलों में हम सीधे राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत कर सकते हैं. ऐसे मामलों में अपील की जगह सीधे शिकायत करना ही समाधान है. आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को एक लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी तक पहुंच, का अधिकार प्रदान करता है. यदि आपको कोई जानकारी देने से मना किया गया है तो आप केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग (जैसा मामला हो) में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

सूचना क़ानून की धारा 18 (1) केतहत यह केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य है, जैसा भी मामला हो, कि वे एक व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करें और पूछताछ करें. जो केंद्रीय सूचना लोक अधिकारी या राज्य सूचना लोक अधिकारी के पास अपना अनुरोध जमा करने में सफल नहीं होते, जैसा भी मामला हो, इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि उक्त अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, इस अधिनियम के तहत नियुक्त न किया गया हो जैसा भी मामला हो, ने इस अधिनियम के तहत अग्रेषित करने के लिए कोई सूचना या अपील के लिए उसके आवेदन को स्वीकार करने से मना कर दिया हो, जिसे वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास न भेजे या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग में अग्रेषित न करें, जैसा भी मामला हो.

- जिसे इस अधिनियम के तहत कोई जानकारी तक पहुंच देने से मना कर दिया गया हो. ऐसा व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर सूचना के लिए अनुरोध या सूचना तक पहुंच के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया हो.
- जिसे शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता हो, जिसे वह अनुपयुक्त मानता/मानती है.
- जिसे विश्वास है कि उसे इस अधिनियम केतहत अपूर्ण, भ्रामक या झूठी जानकारी दी गई है.
- इस अधिनियम के तहत अभिलेख तक पहुंच प्राप्त करने या अनुरोध करने से संबंधित किसी मामले के विषय में.

## पाठकों के पत्र

### पांच साल बाद सूचना मुफ्त मिली

पीएमओ से मैंने कुछ सूचनाएं मांगी थीं. 8 पेज की सूचना के लिए मुझसे 16 रुपये जमा कराने को कहा गया था. यह पांच साल पुरानी घटना है, लेकिन मैंने 16 रुपये जमा कराना उचित नहीं समझा और इस मामले को केंद्रीय सूचना आयोग में ले गया. आयोग ने सुनवाई के लिए दो बार नोटिस जारी कर दोनों पक्षों को उपस्थित होने का आदेश दिया. लेकिन बेगूसराय स्थित एनआईसी

स्टूडियो के ख़राब होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी. इसके बाद 20 जून 2011 को दिल्ली स्थित सूचना आयोग में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद आयोग ने सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

**गिरीश प्रसाद गुप्ता,** *बेगूसराय, बिहार*

### शिक्षक नियोजन पत्र नहीं मिला

मैंने सरायरंजन प्रखंड, समस्तीपुर में सामान्य शिक्षक पद के लिए साल 2008 में द्वितीय शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन किया था, जिसमें मेरा चयन भी हो गया था. लेकिन जब मैं नियोजन पत्र के लिए चयनित स्थल पर गया तो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने मानव संसाधन विकास विभाग की अगली प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नियोजन पत्र देने की बात कही. जब आरटीआई के तहत मैंने इस संबंध में सूचना मांगी तो आधी-अधूरी सूचना दी गई, वह भी छह महीने बाद. भेजी गई सूची में मेरा नाम प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ अंतिम मेधा सूची में भी है और प्रतीक्षा सूची में भी है. आरटीआई के तहत यह भी जानकारी मिली कि 12/8/2010 तक पांच सीटें बची हुई थीं, फिर भी एक प्रशिक्षित उम्मीदवार को नियुक्ति नहीं दी गई. आख़िर ऐसा क्यों हुआ, यह सूचना अब तक नहीं मिल सकी है.

**राजीव कुमार शर्मा,** *समस्तीपुर, बिहार*

***आप इस मामले में अपेक्षित सूचना पाने के लिए राज्य सूचना आयोग में भी अपील कर सकते हैं.***

**चौथी दुनिया ब्यूरो**
*feedback@chauthiduniya.com*

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

**चौथी दुनिया**
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

## सूचना आयोग के पते/फोन नं.

**केंद्रीय सूचना आयोग**
मुख्य सूचना आयुक्त
क्लब बिल्डिंग
ओल्ड जेएनयू कैंपस
बेर सराय, नई दिल्ली-67
011-26161137

**बिहार राज्य सूचना आयोग**
मुख्य सूचना आयुक्त
चौथा तल, सूचना भवन
(नए सचिवालय के सामने)
पटना-1
0612-2235466

**झारखंड राज्य सूचना आयोग**
मुख्य सूचना आयुक्त
इंजीनियर हॉस्टल
धुर्वा, रांची
09431364947
फैक्स-0651-2401418

**मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग**
मुख्य सूचना आयुक्त
बी-22, छर इमली
भोपाल
0755-2761366/2761367

**छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग**
मुख्य सूचना आयुक्त
निर्मल छाया भवन
मीरा दातर रोड
नियर बॉटली हाउस,
शंकर नगर, रायपुर
0771-4014406
फैक्स-0771-2442132

**उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग**
मुख्य सूचना आयुक्त
छठा तल, इंदिरा भवन
लखनऊ
0522-2288598/2288600

**उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग**
मुख्य सूचना आयुक्त
सैक्टर 1, सी-10
डिफेंस कॉलोनी
देहरादून
0135-2666778

## ज़रा हट के

# सिगरेट उम्र घटाती है

एक शोध के मुताबिक़ अगर आप उच्च रक्तचाप और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से जूझने के बावजूद सिगरेट पीते हैं तो आपकी आयु दस साल घट सकती है. ब्रिटेन में हुए एक शोध में 19 हज़ार नौकरशाहों पर नज़र रखी गई, जिनकी उम्र 40 से 69 साल के बीच थी और यह देखा गया कि 38 वर्षों के बाद उनका स्वास्थ्य कैसा है. ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक़ उक्त रक्तचाप और कॉलेस्ट्रॉल होते हुए सिगरेट पीने की लत के कारण मौत स्वस्थ लोगों की तुलना में दस साल पहले ही दस्तक दे सकती है. 1967-1970 में इस शोध की शुरुआत तब हुई थी जब ब्रिटेन में हृदय रोग एक महामारी की तरह फैला था. जिन 19 हज़ार लोगों पर शोध किया गया है, उनकी जांच जब 40 साल बाद हुई तब पता चला कि उनमें से 13 हज़ार पांच सौ लोगों की मौत हो चुकी है. ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का कहना है कि 40 से ऊपर की उम्र वाले पुरुषों को अपने हृदय की जांच करानी चाहिए. ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में ख़तरे के पैमाने के तौर पर सिगरेट पीने, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल पर ज़ोर दिया, क्योंकि दिल की बीमारी केलिए ये ही ख़तरनाक माने जाते हैं. इसके बाद ख़तरों के पैमाने को बढ़ाया गया और उसमें मोटापे, मधुमेह और रोज़गार के स्तर को शामिल किया गया. इसकेबाद पांच प्रतिशत ऐसे लोग, जिनमे ख़तरे के पैमाने सबसे ज़्यादा थे, और पांच प्रतिशत वे, जिनमें ख़तरे के पैमाने कम थे, के बीच तुलना की गई. इसमें पाया गया कि दोनों के बीच की औसत उम्र में 15 वर्षों का फ़र्क़ था.

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर रॉबर्ट क्लार्क ने इस शोध का नेतृत्व किया है. उनका कहना है कि हमने दिखाया है कि एक व्यक्ति ,जो पचास साल का है, और जो सिगरेट पीता है, जिसे उच्च रक्तचाप है और कोलेस्ट्रोल भी बढ़ा हुआ है, वह 74 साल तक ज़िंदा रहने की उम्मीद कर सकता है, जबकि वे लोग जिनमें अभी बताए गए ख़तरे का कोई भी पैमाने मौजूद नहीं हैं, उनकी उम्र 83 साल तक की हो सकती है. रॉबर्ट क्लार्क का कहना है कि अगर आप सिगरेट पीना छोड़ देते हैं और उच्च रक्तचाप और बढ़े हुए वज़न पर संयम रखने की कोशिश करते हैं तो आप लंबी उम्र की उम्मीद कर सकते हैं.

# अजब ग़ज़ब हड़ताल

अभी तक आपने महंगाई और भ्रष्टाचार पर हड़ताल होते देखी होगी, लेकिन ये कुछ अलग तरह की हड़ताल है. श्रीलंका में वन्य अभयारण्यों में तैनात पशु चिकित्सक हाथियों के पक्ष में हड़ताल पर चले गए हैं. श्रीलंका के पशु चिकित्सकों का कहना है कि सरकार जंगली हाथियों और लोगों के बीच संघर्ष को रोकने में नाकामयाब रही है. इसके विरोध में सभी 11 पशु चिकित्सक हड़ताल पर चले गए. श्रीलंका में जंगली हाथियों की संख्या घटकर चार हज़ार रह गई है, क्योंकि इनके लिए संरक्षित क्षेत्रों पर लोगों का क़ब्ज़ा होता जा रहा है. पिछले साल हिंसक जंगली हाथियों ने लगभग 50 लोगों की जान ले ली थी. पिछले दिनों ही हाथियों ने दो बुज़ुर्गों को निशाना बनाया था. दूसरी ओर लगभग 228 हाथियों को लोगों ने निशाना बनाया. दरअसल लोग संरक्षित क्षेत्रों में बिजली के तार लगा देते हैं और झटका लगने की वजह से हाथी उत्तेजित हो जाते हैं. पशु चिकित्सक संघ के सचिव विजेता परेरा ने कहा कि मुख्य समस्या यह है कि हाथियों के खाने-पीने के स्थानों का अतिक्रमण हो रहा है और सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर रही है. उनका कहना है कि घरेलू जानवर संरक्षित क्षेत्र में हाथियों के क्षेत्रों में चर रहे हैं और हाथियों को दूर रखने के लिए पटाख़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनसे ये जानवर बहरे होते जा रहे हैं. विजेता परेरा का कहना है कि हर सप्ताह लगभग चार हाथी मारे जा रहे हैं. हालांकि श्रीलंका सरकार ने हाथियों के संरक्षण केलिए कुछ क़दम उठाए हैं और कुछ हाथियों को बड़े पार्कों में पहुंचाया गया है. वन्यजीव विभाग के महानिदेशक आनंदा विजयसूर्या का कहना है कि पशु चिकित्सकों ने उनसे बात करने से इंकार कर दिया है और कहा है कि वह इस मुद्दे पर उनसे नहीं, मंत्री से बात करना चाहते हैं. उल्लेखनीय है कि वन्यजीव विभाग नए मंत्रालय के अधीन आता है और इस विभाग के मंत्री राष्ट्रपति राजपक्षे के भाई हैं.

**चौथी दुनिया ब्यूरो**
*feedback@chauthiduniya.com*

# राशिफल

**मेष** (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह आप अपने बनाव श्रृंगार या फैशन के अनुरूप अपने को सजाने संवारने की हसरत ही नहीं, बल्कि अन्य इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं. आपको अपने प्रेमीजन से मुलाक़ात का अवसर मिल सकता है. हां कुछ ख़र्च करने की हिम्मत भी आपको करनी होगी वरना मज़ा नहीं आएगा.

**वृष** (21 अप्रैल से 20 मई)
अपने अटके हुए उधार को वसूल करने के लिए यह सप्ताह अच्छा है. हो सकता है वह आपको देखकर कुछ लज्जित भी या फिर बहानेबाज़ी भी करे, लेकिन अड़ियल रुख़ अपनाकर ही आप लाभान्वित हो सकते हैं. लचीलापन ही दिखाना है, तो फिर यह भी तय है कि सारा सप्ताह व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त रहेगा.

**मिथुन** (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में आपको अपनी पढ़ाई से लेकर बचे-खुचे पत्राचार और रिटर्न आदि दाख़िल करने के लिए तैयार रहना होगा. हो सकता है घर की ज़रूरत के मुताबिक़ खाने-पीने के आइटम भी शॉपिंग कॉम्पलेक्स से मंगाने पड़ें या फिर कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि आपकी व्यवस्था भी कुछ काम का बोझ भी हल्का कर दे.

**कर्क** (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह आप परंपराओं और अंधविश्वासों के घोर विरोधी हो सकते हैं. आपको समय सुरक्षित रखना होगा, परंतु यह भी ध्यान रखें कि कुछ लोग आपके साथ एकदम एकांत और निजी क्षणों की चाहत रखते हैं. बेहतर होगा अपने साथी से सलाह कर लें कि सप्ताह का अंतिम दौर कैसे और कहां बिताना है.

**सिंह** (21 जुलाई से 20 अगस्त)
हमेशा की तरह यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी व्यस्तता से भरा होगा. यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी में हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए अपना सिलेबस तैयार करने के लिए तय है. आय के क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

**कन्या** (21 अगस्त से 20 सितंबर)
यह सप्ताह आपके लिए घर के छोटे-मोटे मसले निपटाने के लिए सुरक्षित रहना चाहिए. यदि आप किसी मित्र या प्रेमी की दावत पर जाना चाहते हैं, तो अपनी ड्रेस का ध्यान रखें. हो सकता है आपका व्यक्तित्व अन्य लोगों से कुछ अलग क़िस्म का नज़र आए, परंतु आपको कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे लोगों के गॉसिप का विषय बनाया जाएं.

**तुला** (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह आप अपने वर्तमान संकट से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति अपनाएंगे. किसी धार्मिक या ऐतिहासिक स्थल की यात्रा के दौरान कोई अजनबी आपको बहुत भाएगा या फिर उसका ईमेल, मोबाइल नंबर भी आपको गुदगुदी पैदा करेगा, संकोच नहीं करें आगे बढ़ें.

**वृश्चिक** (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
हो सकता है काफ़ी समय से चल रही मंदी व रोज़गार की कमी का असर आपके ऊपर भी हो रहा हो. परंतु इस सप्ताह ऐसी ही किसी समस्या का हल निकल आएगा, इस जद्दोजहद में आपके शुभचिंतक या विपरीत योनि के मित्र ज़्यादा सहायक हो सकते हैं.

**धनु** (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
जीवन में चाहे कितना भी शोर शराबा हो जाए या फिर लोगों के साथ मिलजुल कर किसी उत्सव पार्टी का आयोजन हो रहा है, परंतु आप अपने व्यापार के झंझटों से बाहर नहीं निकल पाते हैं. यदि आप अपने वाहन के मालिक हैं, तो यह बेहतर होगा कि उसका रखरखाव एक दिन पहले ही कर लें, ताकि बीच रास्ते में कोई रुकावट न आ पाए.

**मकर** (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस सप्ताह आप कुछ ऐसे अनुबंध या संपर्क प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लंबे समय तक आपके कारोबार या व्यापार का हिस्सा रहेंगे. फिर मौज बाहर की भी इच्छा को भी तो अपने जीवन के दायरे में शामिल करना चाहिए, परंतु आप उन सबसे अलग हैं, जो कमाई के साथ-साथ उसका इस्तेमाल भी बेहतर तरीक़े से करना जानते हैं.

**कुंभ** (21 जनवरी से 20 फरवरी)
यह सप्ताह आपको बहुत व्यस्त रखने वाला होगा. वैसे भी आपका सारा जीवन अच्छा रहन-सहन और खाने पीने की चाहत में व्यतीत हुआ है, यही कारण है कि आप सदैव ख़ुश नज़र आते हैं. जहां आप अपने छोटे बड़े स्वजनों और परिजनों सहित नए कार्य के बारे में सोच रहे हैं, वहां आप नए अतिथियों के आने पर बेहद प्रसन्न हो जाते हैं.

**मीन** (21 फरवरी से 20 मार्च)
भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए इस सप्ताह कुछ ऐसे काम का आगाज़ करें, जिससे आपको ऐसे समय में आर्थिक सहायता मिल सके जब आप बिल्कुल ख़ाली हों. हो सकता है कि किसी संगोष्ठी में आपकी उपस्थिति आवश्क हो या फिर किसी मित्र का हालचाल पूछने का अवसर मिल जाए.

**पंडित सुदर्शन**
*feedback@chauthiduniya.com*

फ़ाई को अकस्मात गिरफ्तार किया जाना भारत के लिए कोई अमेरिकी पुरस्कार नहीं है. यह अमेरिका और पाक के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान का नतीजा है.

# अमेरिका में आईएसआई का नेटवर्क

# सेमिनार के ज़रिए कूटनीतिक युद्ध

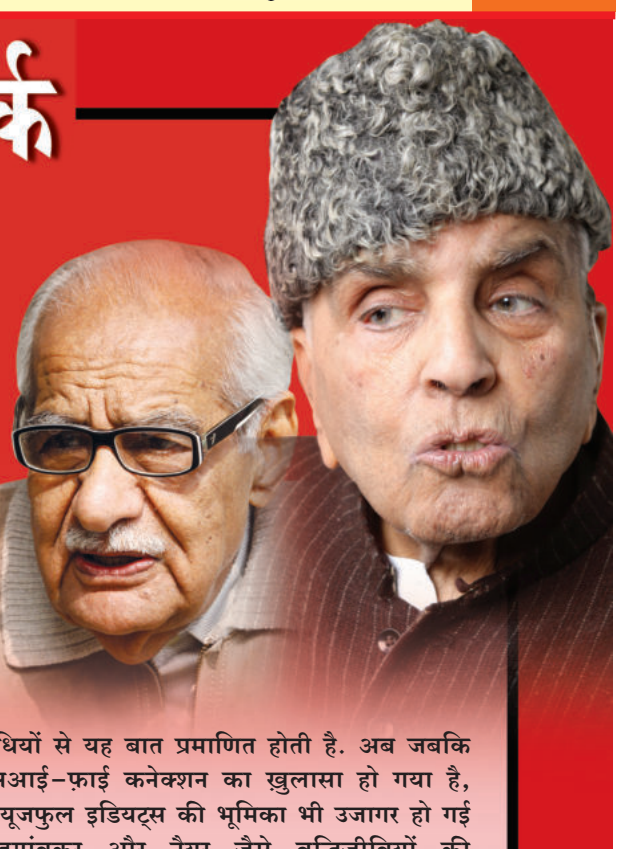

बिग्रेडियर (सेवानिवृत्त) हेमंत महाजन

कश्मीर प्रचारक गुलाम नबी फ़ाई की अमेरिका में गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. फ़ाई को अमेरिका ने इसलिए पकड़ा है, क्योंकि वह तथाकथित रूप से यह बताने में विफल रहा कि वह पाकिस्तान सरकार और उसकी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था. सवाल यह भी है कि भारतीय उदारवादी जानबूझकर या अनजाने में कहीं आईएसआई की यूजफुल इडियट्स यानी कठपुतली तो साबित नहीं हो रहे. यूजफुल इडियट्स विशेषण मूल रूप से पश्चिमी देशों में सोवियत संघ से सहानुभूति रखने वाले उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो यह समझते थे कि सोवियत संघ उनका दोस्त है. वास्तव में सोवियत संघ केवल कठपुतली की तरह उनका इस्तेमाल करता था. इससे ज़्यादा उनका कोई महत्व नहीं था.

उन लोगों के विषय में पूरी ईमानदारी से जांच की जानी चाहिए, जिन्होंने आईएसआई के सहयोग से फ़ाई द्वारा प्रायोजित वार्षिक कश्मीर सम्मेलनों में हिस्सा लिया. यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि अमेरिका को फ़ाई के आईएसआई के साथ संबंधों और उसकी गतिविधियों में हिस्सा लेने के बारे में अचानक पता चला है. वे बहुत पहले से इस बारे में जानते थे और सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि उसे बेनक़ाब किया जा सके. एक न्यूज चैनल ने खोजी अभियान चलाया, ताकि यह पता लगा सके कि फ़ाई द्वारा आयोजित कश्मीर सम्मेलनों में किन लोगों ने हिस्सा लिया. यह बात सामने आई है कि फ़ाई अमेरिकी राजनेताओं, जिनमें डैन बार्टन भी शामिल हैं, से लॉबिंग करता था. भारत को सदैव गुमराह करने वाले बार्टन अब कह रहे हैं कि वह नहीं जानते थे कि आईएसआई फ़ाई को धन उपलब्ध करा रही थी. फ़ाई के विषय में हम अच्छी तरह जानते हैं कि कश्मीर को लेकर उसकी सहानुभूति पाकिस्तानी आक़ाओं के कारण थी.

आईएसआई से मिले धन की बदौलत वह भारत में पांचवी शक्ति (स्तंभ) बनाने की कोशिश कर रहा था. फ़ाई के कृपापात्रों के रूप में जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें जम्मू–कश्मीर में सरकारी वार्ताकार और पत्रकार दिलीप पड़गांवकर, प्रसिद्ध लेखक व पत्रकार कुलदीप नैयर, न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर और नक्सली समर्थक गौतम नवलखा का नाम भी शामिल है. क्या ये सभी लोग देशद्रोही हैं या केवल नासमझी में फ़ाई का साथ दिया. ये सभी बुद्धिजीवी और जानकार हैं और यह मानते हैं कि जो कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं, सही है. देश का बच्चा–बच्चा जानता है कि फ़ाई पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली है, जो भारत से कश्मीर को हर हाल में अलग करना चाहता है, लेकिन हमारे इन बुद्धिजीवियों ने फ़ाई का कृपापात्र बनने से कोई परहेज़ नहीं किया. अब जबकि यह समझ गए हैं कि स्टार नाश्ता कराकर और बिजनेस क्लास में सफ़र करा कर फ़ाई ने उनका इस्तेमाल किया है तो वे स्वयं को ठगा–सा महसूस कर रहे हैं.

## गिरफ्तारी का नाटक

फ़ाई को अकस्मात गिरफ्तार किया जाना भारत के लिए कोई अमेरिकी पुरस्कार नहीं है. यह अमेरिका और पाक के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान का नतीजा है. अमेरिका आईएसआई को दरकिनार कर उस पर दबाव बनाना चाहता है, ताकि तालिबान को ठिकाने लगाते हुए अफ़गानिस्तान के मुद्दे से छुटकारा पा सके. वह चाहता है कि मुल्ला उमर जैसे चरमपंथी पर किसी तरह नकेल कस सके. पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना अमेरिका से एक अलग खेल खेल रही है, ताकि सैन्य व अन्य तरह की सहायता हासिल कर सके. जिस तरह अमेरिका फ़ाई के विषय में सब कुछ जानता था. उसी तरह वह डेविड कोलमैन हेडली के बारे में भी सब कुछ जानता था. वह जेहादी के रूप में डबल एजेंट था. हम अमेरिकी सोच से भलीभांति परिचित हैं. अमेरिका केवल उसी सीमा तक इन दोनों पर कार्रवाई करेगा, जिस सीमा तक वे उसके हितों को पूरा करने के लिए पाक पर दबाव बनाते रहेंगे. पड़गांवकर और कुलदीप नैयर को आत्म परीक्षण करना चाहिए कि क्या वे नहीं जानते थे कि आईएसआई कठपुतली की तरह उनका इस्तेमाल कर रही है. उन्हें सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या ग़लत किया है. क्या भारतीय क़ानून दुश्मन देश की ख़ुफ़िया एजेंसी से धन लेने की इजाज़त देता है? क्या उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा नहीं चलाया जाना चाहिए? चाहे अरुंधति रॉय हों या कोई अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ता, समस्या यही है कि उनके विचारों का इस्तेमाल अलगाववादी विचारधारा को घोषित करने के लिए किया जाता है. दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे मानवाधिकार कार्यकर्ता आईएसआई के लिए यूजफुल इडियट्स साबित होते हैं, जो स्वयं यह सोचते हैं कि कश्मीर में मानवाधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं. लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अलगाव और फूट को ही बढ़ावा देते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि पाकिस्तान और आईएसआई भारत को सैंकड़ों घाव देकर लहूलुहान करने की षड़यंत्रकारी रणनीति पर अमल कर रहे हैं. उदारवादियों के साथ समस्या यही है कि जब भारतीय सरकार के हाथों मानवाधिकार उल्लंघन की कोई घटना होती है तो वे शोर मचाने लगते हैं, लेकिन जब तथाकथित आज़ादी को लेकर ऐसा किया जाता है तो वे ख़ामोश रहते हैं. इसी कारण उन्हें आईएसआई की कठपुतली कहा जाता है. भारत के ख़िलाफ़ शोर मचाना और जिहादियों की गतिविधियों का चुपचाप रहकर अप्रत्यक्ष समर्थन करना देशद्रोह से कम नहीं है.

## कश्मीरियों के नाम पर स्वार्थ सिद्धि

यदि यह मान भी लें कि इन विवेकशील उदारवादियों ने अपने बयानों को संतुलित करना सीख लिया है और वाक़ई कश्मीर की आज़ादी और स्वायत्ता चाहते हैं, तब भी वे यह नहीं बता पाते कि उन्हें कैसी आज़ादी चाहिए? जो कश्मीरियों के हितों पर बयानबाज़ी करते हैं, वे केवल अपने हितों को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं. वे केवल आईएसआई का मुखौटा हैं, जिनकी रावलपिंडी स्थित मुख्यालय में ज़ोर–शोर से अगवानी की जाती है. जब तथाकथित कश्मीर समर्थक ये नेता राज्य के अन्य हिस्सों की भयावह स्थिति पर कुछ नहीं बोलते तो कोई आश्चर्य नहीं होता है. पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) और गिलगिट बलतिस्तान की हालत किसी से छुपी नहीं है. जब उदारवादी नेता आज़ादी की मांग करते हुए कश्मीरी युवाओं की भावनाओं को हवा देने की कोशिश करते हैं तथा बार–बार कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के बयान देते हैं तो उनकी पाक समर्थक मानसिकता खुलकर सामने आ जाती है. गिलानी, मीरवाइज़ और यासीन मलिक जैसे लोग कश्मीरियों के प्रतिनिधि नहीं हैं. वे केवल आईएसआई का मुखौटा हैं. जब भी वे वार्ता का राग अलापने लगें, भारत को स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए, अपने आक़ाओं से बात कराओ. हिज्बुल मुजाहिदीन और लश्करे तैयबा की घाटी में बढ़ती सक्रियता से ख़ुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी सेना और जिहादियों का गठजोड़ ही आतंकी घटनाओं को नियंत्रित कर रहा है. दहशतगर्दों को खुलेआम धन उपलब्ध करा रहा है. भारत को नुक़सान पहुंचाने के लिए कश्मीर पाक का खिलौना बन गया है. आम कश्मीरी उसकी इस साज़िश का शिकार हो रहे हैं. यदि भारत सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए मज़बूत मशीनरी बना लेता है तो आतंकी घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी. कश्मीर में गत वर्ष आंदोलनों के दौरान पथराव की घटनाएं हुईं और दर्जनों लोग मारे गए. यदि आईएसआई और फ़र्ज़ी नाम से उसकी गतिविधियों को चलाने वाली संस्थाओं का उन घटनाओं में हाथ नहीं होता तो इतना हो–हल्ला नहीं मचता. यह पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी की सफलता है कि उसने अपने मुखौटों के ज़रिए युवाओं के हाथों में पत्थर थमाए. एक तरफ़ आईएसआई कश्मीर में हिंसा की आग भड़काने का काम कर रही है, वहीं भारत सहित विश्व भर में दुष्प्रचार का काम भी कर रही है.

## वामपंथी उदारवादी धड़े की सोच पर सवालिया निशान

इन सब बातों से यह प्रश्न पैदा हो गया है कि भारत का वामपंथी उदारवादी धड़ा सोच–समझकर आईएसआई को उसका लक्ष्य हासिल करने में मदद तो नहीं कर रहा है? भले ही वे कुछ भी कहें, लेकिन उनमें से कुछ की गतिविधियों से यह बात प्रमाणित होती है. अब जबकि आईएसआई–फ़ाई कनेक्शन का ख़ुलासा हो गया है, उनकी यूजफुल इडियट्स की भूमिका भी उजागर हो गई है. पड़गांवकर और नैयर जैसे बुद्धिजीवियों की आईएसआई प्रायोजित सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए नहीं, बल्कि वहां अपने विचार व्यक्त करने के लिए आलोचना की जानी चाहिए. इन भारतीय वक्ताओं ने इन पक्षपातपूर्ण सम्मेलनों में हिस्सा लेकर देश की छवि धूमिल की है. भारतीय मीडिया का एक समूह (प्रवीण स्वामी और सीमा सिरोही जैसे लोग) ने फ़ाई और उसके उपक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. लगभग एक दशक से वे उसकी सहायता कर रहे हैं.

फ़ाई की साज़िश के ख़ुलासे के बाद इन हाई प्रोफाइल लोगों के फ़ैसले और बुद्धिमत्ता पर सवालिया निशान लग गया है. यह हमारे हित में है कि चाहे कश्मीर हो या देश हित के मुद्दे उनकी भूमिका को राष्ट्र विरोधी क़रार दिया जाए. फ़ाई प्रकरण भारत के अनेक मीडिया दिग्गजों, बुद्धिजीवियो, वक्ताओं और विशेषज्ञों के लिए सबक़ है. उन्हें राष्ट्रविरोधी तत्वों के किसी कार्यक्रम, सभा–सम्मेलनों में हिस्सा लेने या अन्य किसी लालच का शिकार होने से पहले ख़ूब सोच–विचार कर लेना चाहिए. विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में. गुलाब नबी फ़ाई के ख़िलाफ़ एफबीआई ने जो चार्जशीट दाख़िल की है, भारत सरकार उसे लेकर अब तक ख़ामोश है. सरकार को और क्या करना चाहिए? उसे लंदन और ब्रूसेल्स स्थित दो मुख्य कश्मीर केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. उसे ब्रिटिश सरकार और ईयू पार्लियामेंट पर दबाव बनाकर उनके ख़िलाफ़ जांच करवा कर बंद करवाना चाहिए. साथ ही उसे आईएसआई के पैसों पर पलने वाले कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. भारत के लिए यह सुनहरा अवसर है जब वह स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दे पर अपना रुख़ कड़ाई से पेश करे. फुटबॉल मैच की भाषा में कहें तो यह स्ट्राइकर के लिए खुला अवसर है, जब उसे गेंद गोल पोस्ट में डालनी है. भारत को इस बार नहीं चूकना चाहिए. हालांकि हम अक्सर देखते हैं कि सुनहरे अवसरों को गंवा दिया जाना है. डर है कि इस बार भी कहीं ऐसा ही न हो.

## आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं

कश्मीर की आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं है. आज़ादी चाहिए तो केवल पाक प्रायोजित आतंकवाद से, कुप्रशासन से, भ्रष्टाचारियों से, दाग़ी राजनेताओं, अफ़सरों से, दुष्प्रचार से. और आज़ादी चाहिए ढोंगी धर्मनिरपेक्षवादियों अरुंधती रॉय, पड़गांवकर, कुलदीप नैयर, गौतम नवलखा और राजिंदर सच्चर जैसे लोगों से.

feedback@chauthiduniya.com

## सत्यमेव जयते

क्या हमारे उदारवादी सदैव आईएसआई के हाथों की कठपुतली बने रहेंगे? जिस तरह युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र के मैदान में ग़फ़लत में अश्वथामा की मौत की ख़बर फैला दी थी, क्या वे भी ऐसा ही करते रहेंगे? भारत सरकार ने कश्मीर में सुशासन स्थापित करने को लेकर देश के अन्य हिस्सों और विश्व की नज़र में अपनी विश्वसनीयता खो दी है. यदि अब भी वह राष्ट्रविरोधी तत्वों से सख्ती से नहीं निपट पाती तो आतंकवाद को और बढ़ावा मिलेगा. हालांकि इस मुद्दे पर उसे ख़ामोश रहने की वर्तमान नीति को छोड़ कर प्रिंट मीडिया और टीवी चैनलों पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रचार युद्ध तेज़ कर उसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए. पूरी सरकार को गंभीरता से प्रयास करने चाहिए और दुश्मनों के दुष्प्रचार का उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए. उसे कश्मीरी अलगाववादी नेतृत्व को बेनक़ाब करना चाहिए. कुर्सियों पर बैठ कर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोरी बयानबाज़ी करने वाले मुखौटा धर्मनिरपेक्षवादियों को भी उनकी जगह दिखानी होगी. भारत से सुविधाएं हासिल कर आलीशान ज़िंदगी गुज़ारने वाले और देश की पीठ में छुरा घोंपने वाले जिहाद समर्थकों से सावधान रहने की आवश्यकता है. इसके साथ ही भारत सरकार को राष्ट्रविरोधी तत्वों से वैचारिक स्तर पर मुक़ाबला जीतने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए संयमित, संगठित प्रयास करने होंगे. सत्यमेव जयते ही भारत का वर्षों से राष्ट्रीय उद्देश्य है. अंत में सत्य की ही विजय होती है, लेकिन उसे सबके सामने लाने की आवश्यकता होती है. क्या सरकार इसमें सफल हो पाएगी?

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक–संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम–उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301 www.chauthiduniya.tv

यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी. केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी.



# भक्ति का बीजारोपण

मां होने के कारण नारी का स्थान भगवान से भी ऊंचा है.
*प्रेमचंद*

विचारों को दबाया नहीं जा सकता. एक दिन विचार कंदरा फोड़ कर संसार पर छा जाते हैं.
*स्व. तारा चंद्र मेहरोत्रा*

**दासगणू का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूं और अपने कुटुम्ब का भरण-पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूं. यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा. भाग्य ने पल्टा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया. उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई. अब केवल संकल्प ही शेष रहा.**

बाबा की महिमा इतनी निराली है कि वह किसी न किसी बहाने अपने भक्तों के हृदय में शिक्षा का संचार करते रहते हैं. बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर ज़िलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नानासाहेब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगणू के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोकण (बंबई प्रांत) में भी फैल गई. इसका श्रेय केवल श्री दासगणू को ही है. भगवान उन्हें सदैव सुखी रखें. उन्होंने अपने कीर्तन से बाबा को घर-घर पहुंचा दिया. श्रोताओं की रुचि प्राय: भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है. किसी को हरिदासों की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत-विवेचन और किसी को उनकी मुख्य कथा रुचिकर प्रतीत होती है. परंतु ऐसे बिरले ही हैं, जिनके हृदय में संत-कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता हो. श्री दासगणू का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था. एक ऐसी घटना नीचे दी जाती है.

एक समय ठाणे के श्रीकौपीनेश्वर मंदिर में श्री दासगणू कीर्तन और श्री साईबाबा का गुणगान कर रहे थे. श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, भी वहां उपस्थित था. दासगणू का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूं और अपने कुटुम्ब का भरण-पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूं. यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा. भाग्य ने पल्टा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया. उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई. अब केवल संकल्प ही शेष रहा. शुभस्य शीघ्रम. श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुम्ब भी बड़ा था. अत: वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग-व्यय जुटाने में असमर्थ हुआ. ठाणे ज़िले में एक कहावत प्रचलित है कि नाठे घाट व सहाद्रि पर्वत श्रेणियां कोई भी सरलतापूर्वक पार कर सकता है, परंतु ग़रीब को उंबर घाट (गृह-चक्कर) पार करना बड़ा ही कठिन होता है.

श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक था. उसने मितव्ययी बनकर, अपना ख़र्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया. इस कारण उसने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया और इस तरह कुछ द्रव्य एकत्रित कर वह शिरडी पहुंचा. उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्पानुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोला कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है. मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपादृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थीं. मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापूसाहेब जोग भी वहीं उपस्थित थे. जब वे दोनों वहां से जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना. इन अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ. उनके नेत्रों से अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगीं और वे प्रेम से विह्वल होकर श्रीचरणों पर गिर पड़े. श्री जोग को अधिक शक्कर सहित चाय के प्याले अतिथि को दो, यह विचित्र आज्ञा सुनकर बड़ा कोतूहल हो रहा था कि यथार्थ में इसका अर्थ क्या है.

बाबा का उद्देश्य तो श्री चोलकर के हृदय में केवल भक्ति का बीजारोपण करना ही था. बाबा ने उन्हें संकेत किया था कि वे शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से भली भांति परिचित हैं. बाबा का यह कथन था कि यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा. यद्यपि मैं शरीर से तो यहां हूं, परंतु मुझे सात समुद्रों के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है. मैं तुम्हारे हृदय में विराजीत, तुम्हारे अंतरस्थ ही हूं. जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है, उसकी ही पूजा करो. धन्य और सौभाग्यशाली वही है, जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है. बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

## श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ ख़ाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

# विश्वास और महिमा

एक बार गोवा के एक मामलतदार ने, जिनका नाम राले था, लगभग 300 आमों का एक पार्सल शामा के नाम शिरडी भेजा. पार्सल खोलने पर प्रायः सभी आम अच्छे निकले. भक्तों में उनके वितरण का कार्य शामा को सौंपा गया. उनमें से बाबा ने चार आम दामू अण्णा के लिए अलग निकाल कर रख लिए. दामू अण्णा की तीन स्त्रियां थीं, परंतु अपने दिए हुए वक्तव्य में उन्होंने बतलाया था कि उनकी केवल दो ही स्त्रियां थीं. वह संतानहीन थे, इस कारण उन्होंने अनेक ज्योतिषियों से इसका समाधान कराया और स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन कर ज्ञात कर लिया कि जन्म कुंडली में एक पापग्रह के स्थित होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का मुख देखने का कोई योग नहीं है, परंतु बाबा के प्रति तो उनकी अटल श्रद्धा थी. पार्सल मिलने के दो घंटे पश्चात ही वह पूजनार्थ मस्जिद में आए. उन्हें देख कर बाबा कहने लगे कि लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं, परंतु ये तो दामू के हैं. जिसके हैं, उन्हीं को खाने और मरने दो. इन शब्दों को सुन दामू अण्णा के हृदय पर वज्राघात सा हुआ, परंतु म्हालसापति (शिरडी के एक भक्त) ने उन्हें समझाया कि इस मृत्यु शब्द का अर्थ अहंकार के विनाश से है और बाबा के चरणों की कृपा से तो वह आशीर्वाद स्वरूप है, तब वह आम खाने को तैयार हो गए. इस पर बाबा ने कहा कि वे तुम न खाओ, उन्हें अपनी छोटी स्त्री को खाने दो. इन आमों के प्रभाव से उसे चार पुत्र और चार पुत्रियां उत्पन्न होंगी. यह आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने वे आम ले जाकर अपनी छोटी स्त्री को दिए. धन्य है श्री साईबाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य-विधान पलट कर उन्हें संतान-सुख दिया. बाबा की स्वेच्छा से दिए वचन सत्य हुए, ज्योतिषियों के नहीं.

बाबा के जीवन काल में उनके शब्दों ने लोगों में अधिक विश्वास और महिमा स्थापित की, परंतु महान आश्चर्य है कि उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनका प्रभाव पूर्ववत ही है. बाबा ने कहा कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो. यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी. केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी, फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी, जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे. निराश न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा. तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित पाओगे. यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मूल रूप से इंद्रधनुष के सात रंगों को ही रंगों का जनक माना जाता है. ये सात रंग हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी. लाल रंग को रक्त रंग भी कहते हैं, क्योंकि ख़ून का रंग लाल होता है.

# पांच दशक से समीक्षा कर्म में लगे हैं मधुरेश


अनंत विजय

प्रेमचंद की मशहूर कहानी पंच परमेश्वर में अलगू चौधरी और ख़ाला के बीच एक संवाद है– क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे. यह बात उस प्रसंग में कही गई है जब ख़ाला, जुम्मन से परेशान होकर पंचायत करवानी चाहती है. जब वह अलगू को पंचायत में बोलने का अनुरोध करती है तो अलगू अपने दोस्त से रिश्ते बिगड़ने की दुहाई देता है जिसपर ख़ाला कहती है कि– क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे. अभी हाल में हिंदी की आलोचक निर्मला जैन का एक लेख पढ़कर मुझे ख़ाला की बात याद आ गई. हिंदी की वरिष्ठ आलोचक निर्मला जैन ने हाल में अपने एक लेख में लिखा– आज के रचनाकारों में सहनशीलता का ह्रास हुआ है. आलोचना के नाम पर वे प्रशंसा सुनना चाहते हैं. मूल्यांकन ज़रा भी समीक्षात्मक या आलोचनात्मक हुआ, रचनाकार उसे बदनीयती से जोड़कर देखने लगते हैं. इसलिए समीक्षात्मक लेखन सभी बड़े आलोचकों ने लगभग बंद कर दिया है. निर्मला जी का यह कथन आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से तो इसे क़तई स्वीकार नहीं किया जा सकता है. अगर पूरे तौर पर यह मान लिया जाए कि रचनाकारों के नाराज़ होने के डर से बड़े आलोचकों ने समीक्षात्मक लेखन बंद कर दिया है तो यह न सिर्फ़ हिंदी साहित्य के लिए चिंता की बात है, बल्कि उन तथाकथित बड़े आलोचकों के विवेक और निर्णय लेने की उनकी क्षमता पर भी एक बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देता है. आलोचकों से तो यह अपेक्षा की जाती है कि वे भयमुक्त होकर बग़ैर किसी लाभ–लोभ के वस्तुनिष्ठता के साथ समीक्षात्मक लेखन करेंगे. रचनाकारों के नाराज़ होने का ख़तरा उठाने का साहस अगर बड़े आलोचकों में नहीं है तो वे किस बात के बड़े आलोचक हैं. क्या सिर्फ़ बड़े कवियों पर लंबे–लंबे लेख लिखने से ही कोई बड़ा आलोचक हो सकता है. या फिर तुलसीदास, कबीरदास या मैथिलीशरण गुप्त पर ही लिखकर कोई बड़ा आलोचक हो जाता है. मेरे विचार से तो बड़ा आलोचक वह होता है जो अपने समकालीन लेखकों की रचनाओं को आलोचना की कसौटी पर बग़ैर किसी डर भय के कसता है. और हिंदी आलोचना–समीक्षा की परंपरा भी यही रही है. यहां निर्मला जैन आलोचना को समीक्षा से अलग कर देख रही हैं जो उचित नहीं है. समीक्षा रूपी फूल को आलोचना के गुलदस्ते से अलग कर देखना उसके साथ अन्याय होगा. नामवर सिंह भी जबतक पृथ्वीराज रासो में फंसे थे तबतक उनका डंका नहीं बज पाया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने समकालीन लेखकों को अपने स्तंभ हाशिये पर, में परखना शुरू किया तो उनका शुमार बड़े आलोचकों में होने लगा. दरअसल जैसे ही कोई भी व्यक्ति साहित्य जगत में थोड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है या फिर उसके लिखे लंबे लेख को आलोचना मान लिया जाता है तो वह ख़ुद भी समीक्षा से दूर हो जाता है. निर्मला जी जिन्हें बड़ा आलोचक कह रही हैं वे लेखकों के डर से नहीं, बल्कि अपनी छवि ख़राब होने के डर से समीक्षा नहीं लिखते हैं. उन बड़े आलोचकों को लगता है कि समीक्षा तो आलोचना के मुक़ाबले दोयम दर्जे की रचना होती है.

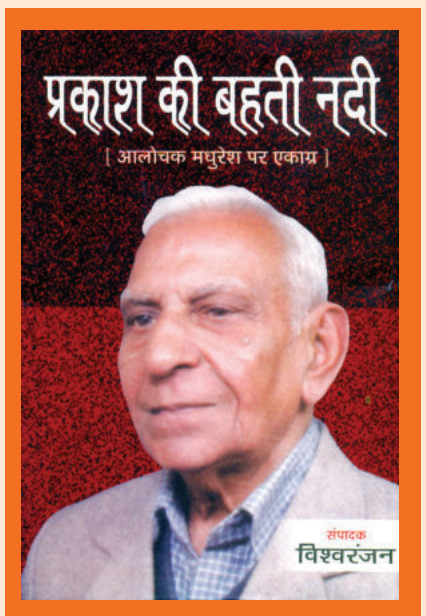




समीक्ष्य कृति : प्रकाश की बहती नदी
संपादक : विश्वरंजन
प्रकाशक : शिल्पायन, वेस्ट गोरखपार्क, शाहदरा, दिल्ली–110032
मूल्य : 1000 रुपये

दूसरी बात यह कि आज के रचनाकारों में सहनशीलता का ह्रास हुआ है, यह भी ग़लत है. रचनाकारों में सहनशीलता का अभाव तो काफ़ी पहले से ही रहा है. जब शैलेश मटियानी के कहानी संग्रह महाभोज की समीक्षा मधुरेश ने कहानी पत्रिका में की थी तो वह नाराज़ हो गए थे. इसी तरह अपनी रचनाओं की मनमाफ़िक़ समीक्षा न होने से अश्क जी के नाराज़ होने के भी कई क़िस्से हैं और मुझे लगता है कि निर्मला जी को वे मालूम भी होंगे. नाराज़ होनेवाले लेखकों की एक लंबी सूची है. तो अब के लेखकों में सहनशीलता का ह्रास हुआ है, ऐसा नहीं है.

लेकिन अब भी एक बड़े आलोचक हैं जो नियमित रूप से समीक्षा लिखते हैं और उनकी समीक्षाओं को हिंदी जगत में गंभीरता से लिया जाता है. उनका नाम है मधुरेश जो लगभग पांच दशक से समीक्षा कर्म में लगे हैं. उनकी समीक्षाओं को लेखक गंभीरता से लिखते हैं. जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि समीक्षा को आलोचना के मुक़ाबले दोयम दर्जे का समझा जाता है और साहित्य जगत में बड़े आलोचक समीक्षकों को भाव नहीं देते हैं. यह कुछ हद तक मधुरेश के साथ भी हुआ. मधुरेश ने इसपर एक पूरा लेख लिखा है कि– मैं समीक्षा क्यों लिखता हूं. अपने उस लेख में मधुरेश ने लिखा है– पुस्तक समीक्षा की विश्वसनीयता का सवाल एक मुख्य सवाल है. मेरे विचार से समीक्षा के विश्वसनीय होने का मतलब उसका लेखक के पक्ष में होना नहीं है. उसके पक्ष–विपक्ष में होने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जिस तर्कपद्धति द्वारा समीक्षकों ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं, वे पाठकों को वस्तुपरक, पूर्वग्रह रहित और अनिवार्य लगने चाहिए. मधुरेश ने अपनी समीक्षाओं में कमोबेश इसका पालन भी किया है. लंबे समय से लिखने के बावजूद मधुरेश को उन तथाकथित बड़े आलोचकों में नहीं माना जाता है जो अबतक तुलसीदास से ही उलझ रहे हैं या फिर बहुत से बहुत निराला और मुक्तिबोध तक पहुंच पाए हैं. अपने इस दर्द को भी मधुरेश ने बयान किया है. पिछले काफ़ी समय से लोगों के दिमाग़ पर यह बात बिठाने की कोशिश की गई है कि समीक्षा लिखना एक घटिया और दोयम दर्जे का काम है. बहुत मामूली सा प्रकाशक भी यह सुझाव आसानी से दे देता है कि समीक्षाएं नहीं कोई पूरी किताब दे तो उसे छापकर ख़ुशी होगी. मित्र भी सलाह दे देते हैं कि साहित्य में ज़िंदा रहने के लिए आलोचना के क्षेत्र में कुछ गंभीर काम करना चाहिए– इन समीक्षाओं से आख़िर बनता क्या है. मधुरेश को इस बात का अफ़सोस भी है, लेकिन गर्व भी कि उन्होंने अपना ध्यान समीक्षा कर्म पर केंद्रित किया है और पिछले पांच दशकों से उसमें सक्रिय हैं. ऐसा नहीं है कि मधुरेश ने आलोचनात्मक कार्य नहीं किया है, वह भी किया है. प्रमोद वर्मा स्मृति संस्थान, रायपुर के सहयोग से मधुरेश पर केंद्रित एक किताब आई है– प्रकाश की बहती नदी, इसके संपादक हैं विश्वरंजन. विश्वरंजन रायपुर में रहकर साहित्य के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं. प्रमोद वर्मा स्मृति संस्थान के तहत कई किताबों का प्रकाशन किया गया है. उसी कड़ी में मधुरेश पर लगभग सात सौ पन्नों की यह किताब प्रकाशित हुई है. इस किताब में मधुरेश के व्यक्तित्व पर पूर्व में लिखे गए लेख, उनका परिचय, उनकी प्रकाशित और प्रकाश्य किताबों की सूची, मधुरेश के कुछ चुनिंदा लेख, उनके साक्षात्कार और उनकी कृतियों पर लिखे गए समीक्षात्मक लेख संकलित हैं. यह किताब मधुरेश को जानने समझने के लिए एक उपयोगी किताब है, लेकिन इसमें मधुरेश पर सम्मिलित लेखों के चयन में सावधानी बरतने की ज़रूरत थी. सब कुछ समेट लेने की हड़बड़ी में बहुत हल्के लेख भी संकलित हो गए हैं, जो अगर इस किताब में नहीं होते तो बेहतर होता और किताब का मूल्य भी कम होता. ऐसा लगता है कि विश्वरंजन ने संपादन न करके संकलन किया है.

*(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)*
anant.ibn@gmail.com

# रंगों की कहानी रंगों की ज़ुबानी




फ़िरदौस ख़ान

मानव सभ्यता में रंगों का काफ़ी महत्व रहा है. हर सभ्यता ने रंगों को अपने तरीक़े से अपनाया. दुनिया में रंगों के इस्तेमाल को जानना भी बेहद दिलचस्प है. कई सभ्यताओं को उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों की वजह से ही पहचाना गया. विक्टोरियन काल में ज़्यादातर लोग काला या स्लेटी रंग इस्तेमाल करते थे. एक तरह से ये रंग इनकी पहचान थे. फ़िरऔन हमेशा काले कपड़े पहनता था. वैसे भी हर रंग के अपने सकारात्मक और नकारात्मक असर होते हैं. इसलिए यह नहीं कर सकते कि काला रंग हमेशा बुरा ही होता है. हालांकि कई सभ्यताओं में इसे शोक का रंग माना जाता है. शिया मोहर्रम के दिनों में ज़्यादातर काले कपड़े ही पहनते हैं. विरोध जताने के लिए भी काले रंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे काले झंडे दिखाना, सर पर काला कपड़ा या काली पट्टी बांध लेना. ऐसा इस्लामी देशों में ज़्यादा होता है, लेकिन अब भारत में भी इस तरह विरोध जताया जाने लगा है, विशेषकर बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी यानी छह दिसंबर को मुस्लिम समुदाय के लोग काली पट्टी बांधकर ही अपना विरोध ज़ाहिर करते हैं.

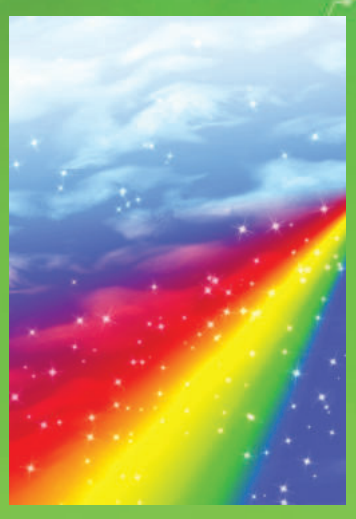



महान दार्शनिक अरस्तु ने 4 ईसा पूर्व में नीले और पीले रंगों की गिनती शुरुआती रंगों में की. उन्होंने इसकी तुलना प्राकृतिक वस्तुओं से की, जैसे सूरज–चांद और दिन–रात आदि. उस वक़्त ज़्यादातर कलाकारों ने उनके सिद्धांत को माना और तक़रीबन दो हज़ार साल तक इसका असर देखने को मिला.

इसी बीच मेडिकल प्रेक्टिस के पितामाह कहे जाने वाले 11वीं शताब्दी के ईरान के चिकित्सा विशेषज्ञ हिप्पोकेट्स ने अरस्तु के सिद्धांत से अलग एक नया सिद्धांत पेश किया. उन्होंने रंगों का इस्तेमाल दवा के तौर पर किया और इसे इलाज के लिए बेहतर ज़रिया क़रार दिया. उनका मानना था कि सफ़ेद फूल और वॉयलेट फूल के अलग–अलग असर होते हैं. उन्होंने एक और सिद्धांत दिया, जिसके मुताबिक़ हर व्यक्ति की त्वचा के रंग से भी उसकी बीमारी का पता लगाया जा सकता है और रंगों के ज़रिये ही इसका इलाज भी मुमकिन है. उन्होंने इसका ख़ूब इस्तेमाल भी किया.

15वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड के चिकित्सक वॉन होहेनहैम ने ह्यूमन स्टडी पर काफ़ी शोध किया, लेकिन उनके तरीक़े हमेशा विवादों में रहे. उन्होंने जख्म भरने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया. 17–18वीं शताब्दी में न्यूटन के सिद्धांत ने अरस्तु के विशेष रंगों को सामान्य रंगों में बदल दिया. 1672 में न्यूटन ने रंगों पर अपना पहला परचा पेश किया. यह काफ़ी विवादों में रहा, क्योंकि अरस्तु के सिद्धांत के बाद इसे स्वीकार करना इतना आसान नहीं था. रंगों के विज्ञान पर काम करने वाले लोगों में जॉन्स वॉल्फगैंग वॉन गौथे भी शामिल थे. उन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को पूरी तरह नकारते हुए थ्योरी ऑफ कलर पेश की. उनके सिद्धांत अरस्तु की थ्योरी से मिलते जुलते थे. उन्होंने कहा कि अंधेरे में से सबसे पहले नीला रंग निकलता है, वहीं सुबह के उगते हुए सूरज की किरणों से पीला रंग सामने आता है. नीला रंग गहरे रंगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पीला रंग हल्के रंगों का. 19वीं शताब्दी में कलर थैरेपी का असर कम हुआ, लेकिन इसके बाद 20वीं शताब्दी में यह नए रूप में सामने आया. आज भी कई चिकित्सक कलर थैरेपी को इलाज का अच्छा ज़रिया मानते हैं और इससे अनेक बीमारियों का उपचार भी करते हैं. आयुर्वेद चिकित्सा में भी रंगों का विशेष महत्व है. रंग चिकित्सा के मुताबिक़ शरीर में रंगों के असंतुलन के कारण ही बीमारियां पैदा होती हैं. रंगों का समायोजन ठीक करके बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है. ऑस्टवाल्ड ने आठ आदर्श रंगों को विशेष क्रम में संयोजित किया. इस चक्र को ऑस्टवाल्ड वर्ण कहा जाता है. इसमें पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, समुद्री हरा और हरा रंग शामिल है. 60 के दशक में एंथ्रोपॉलिजिस्ट्स केन ने रंगों पर अध्ययन किया. उनके मुताबिक़ सभी सभ्यताओं ने रंगों को दो वर्गों में बांटा–पहला हल्के रंग और दूसरा गहरे रंग.

## कौन–सा रंग क्या कहता है

मूल रूप से इंद्रधनुष के सात रंगों को ही रंगों का जनक माना जाता है. ये सात रंग हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी. लाल रंग को रक्त रंग भी कहते हैं, क्योंकि ख़ून का रंग लाल होता है. यह शक्ति का प्रतीक है, जो जीने की इच्छाशक्ति और अभिलाषा को बढ़ाता है. यह प्रकाश का संयोजी प्राथमिक रंग है, जो क्यान रंग का संपूरक है. यह रंग क्रोध और हिंसा को भी दर्शाता है. हरा रंग प्रकृति से जुड़ा है. यह ख़ुशहाली का प्रतीक है. हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है. यह प्राथमिक रंग है. हरे रंग में ऑक्सीजन, एल्यूमीनियम, क्रोमियम, सोडियम, कैल्शियम, निकिल आदि होते हैं. इस्लाम में इसे पवित्र रंग माना जाता है. नीला रंग आसमान का रंग है. यह विशालता का प्रतीक है. भारत का क्रीड़ा रंग भी नीला ही है. यह धर्मनिरपेक्षता का भी प्रतीक है. यह एक संयोजी प्राथमिक रंग है. इसका संपूरक रंग पीला है. गहरा नीला रंग अवसाद और निराशा को भी प्रकट करता है. पीला रंग ख़ुशी और रंगीन मिज़ाजी को दर्शाता है. यह आत्मविश्वास बढ़ाता है. यह वैराग्य से भी संबंधित है. हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है. विष्णु और कृष्ण को यह रंग प्रिय है. बसंत पंचमी तो इसी रंग से जुड़ा पर्व है. डल पीला रंग ईर्ष्या को दर्शाता है. सफ़ेद रंग पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक माना जाता है. यह शांति और सुरक्षा का भाव पैदा करता है. यह अकेलेपन को भी प्रकट करता है. काला रंग रहस्य का प्रतीक है. यह बदलाव से रोकता है. यह नकारात्मकता को भी दर्शाता है.

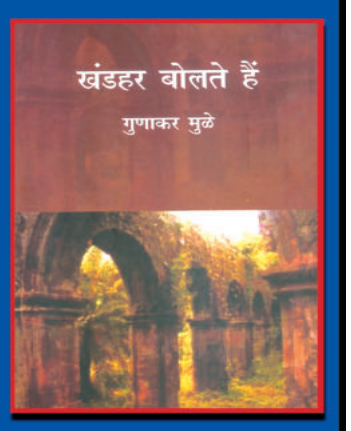

firdaus@chauthiduniya.com

## किताब मिली

पुस्तक का नाम: खंडहर बोलते हैं
लेखक: गुणाकार मुले
प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन
मूल्य: 300 रुपये




इस किताब में देश की विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों के बारे में जानकारी दी गई है.

पानी में कई अशुद्ध चीज़ें भी मौजूद होती हैं, इन्हें हटाकर शुद्ध पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए यूरेका फोब्स के आर ओ में टोटल डिजॉल्वड सॉलिड के अलग-अलग लेवल को जांच कर उन्हें हटाने की व्यवस्था की गई है.



# मर्सिडीज एसएलके 350

फोटो- सुनील मल्होत्रा

**कंपनी द्वारा इस कार को अपनी श्रेणी में सबसे सुरक्षित कारों में दर्ज किया गया है. सुरक्षा के मामले में इसे यूरोप की प्रमुख संस्था ने 5 स्टार दिया, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन सुरक्षा मानक है. इसके साथ ही देर तक कार चलाने में आ रही सुस्ती का पता लगाने वाली अटेंशन असिस्ट तकनीक लगाई गई है, जो ज़्यादा थकान की स्थिति में पहले ही चेतावनी देकर चालक को सतर्क कर देती है.**

मर्सिडीज बेंज इंडिया ने अपनी दर्शनीय और मनमोहक नई जेनरेशन एसएलके 350 रेंज का उद्घाटन किया. एसएलके दुनिया भर में रोडस्टर सेगमेंट में अग्रणी है. एसएलके के साथ मिलकर मर्सिडीज बेंज ने रोडस्टर को नए सिरे से तैयार किया है, जिसमें दुनिया का पहला मैजिक स्काई कंट्रोल लगाया गया है. इसमें वी6 इंजन लगाया गया है जो इसे शक्तिशाली बनाता है. कंपनी द्वारा इस कार को अपनी श्रेणी में सबसे सुरक्षित कारों में दर्ज किया गया है. सुरक्षा के मामले में इसे यूरोप की प्रमुख संस्था ने 5 स्टार दिया, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन सुरक्षा मानक है. इसके साथ ही देर तक कार चलाने में आ रही सुस्ती का पता लगाने वाली अटेंशन असिस्ट तकनीक लगाई गई है, जो ज़्यादा थकान की स्थिति में पहले ही चेतावनी देकर चालक को सतर्क कर देती है. इसके अलावा कार चलाते हुए ड्राइवर का ध्यान इधर-उधर भटकने पर भी यह अटेंशन असिस्ट तकनीक ख़ुद ब ख़ुद ड्राइवर को सचेत कर देती है. मर्सिडीज बेंज इंडिया के विपणन एवं विक्रय निदेशक देवाशीष मित्रा ने इस कार को पेश करते हुए बताया कि कंपनी ने इस नई एसएलके रोडस्ट को नए सिरे से तैयार किया है, लेकिन इसमें मर्सिडीज की सारी ख़ूबियां मौजूद है. उन्होंने बताया कि इसमें आरामदायक परफॉरमेंस के साथ ही अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है. इसके साथ ही इसके लुक को स्पोर्टी बनाया गया है. इस कार में 3.5 लीटर इंजन के साथ ब्ल्यूएफिशिएंसी तकनीक लागू की गई है, जो पर्यावरण के अनुकूल और बेहतरीन परफॉरमेंस के लिए है. कार की लांच के दौरान इसके विशिष्ट, महत्वाकांक्षी डिज़ाइन और प्रभावशाली स्पोर्टी आकार को शोकेस किया गया, जो एसएलएस-एएमजी और एसएल क्लास से काफ़ी मेल खाता है. मर्सिडीज बेंज इंडिया के लग्ज़री कार पोर्टफोलियो में एक और चीज़ अहम रही, और वह है इसमें पहली बार शामिल किया गया मैजिक स्काई कंट्रोल यानी पैनोरेमिक वेरियो रूफ. इसके अलावा शानदार स्पोर्टी लुक के साथ अद्वितीय सुरक्षा. नई एसएलके में आरामदायक परफॉरमेंस के साथ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. मर्सिडीज एसएलके 350 की क़ीमत 61.90 लाख रुपये है.

# दिखें हॉट और स्टाइलिश

स्टाइल और पर्सनलिटी को निखारने के लिए कपड़े महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. मौसम बदलते ही कपड़ों का स्टाइल बदल जाता है. गर्मियों के लिए कपड़ों की नई रेंज बाज़ार में नज़र आने लगी है. युवा अपनी ज़िंदगी में काफ़ी व्यस्त हैं, यही वजह है कि ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. इसी को देखते हुए इंकफ्रूट डॉट कॉम पर भी कपड़ों की नई रेंज को पेश किया गया है. युवा फैशन और नए स्टाइल के दीवाने होते हैं, इसका ख्याल रखते हुए कंपनी के डिज़ाइनर्स ने नई तरह की अल्ट्रा वायलेट टी शर्ट्स बनाई हैं. यह इलेक्ट्रिक कलेक्शन बेवसाइट पर बेहतरीन डिज़ाइन के साथ उपलब्ध है, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए पांच दिनों के भीतर मंगवाया जा सकता है. यह कलेक्शन बिल्कुल नए, ठंडक देने वाले और ताज़गी भरने वाले फैब्रिक से तैयार किए गए हैं. इन ड्रेसेस में गर्मियों के अनुकूल शेड और ट्रेंडी डिज़ाइन का भी पूरा ध्यान रखा गया है. बेहद आरामदायक और आकर्षक डिज़ाइन वाले इस कलेक्शन में रंगों का चुनाव बिल्कुल अलग हटकर किया गया है. कंपनी ने यह संग्रह उन महिलाओं और युवतियों के लिए प्रस्तुत किया है जो अपने व्यवहार के अनुसार अपने व्यक्तित्व में भी बदलाव लाकर चार चांद लगाना चाहती हैं. आधुनिक फैशन और ट्रेंड को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए इस कलेक्शन को 100 प्रतिशत सुपर कॉम्बड कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है. इन पर अल्ट्रा वायलट डिज़ाइनिंग उच्चतम क्वालिटी के स्क्रीन प्रिंटिंग और ट्रांसफर प्रिंटिंग के ज़रिए तैयार किया गया है. कंपनी ने इस कलेक्शन के ज़रिए युवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ परिधानों के तमाम विकल्प प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ताकि वे फैशनेबल ट्रेंडी लुक में भी आरामदायक और तरोताज़ा महसूस कर सकें. कंपनी अपने उत्पाद को लेकर काफ़ी सतर्क रहती है, ताकि वह अपने ग्राहकों की गुणवत्ता और फैशन संबंधी मांगों को पूरा कर सके. यह कलेक्शन 540 रुपये से लेकर 599 रुपये तक की रेंज में देश के सभी प्रमुख स्टोरों में भी उपलब्ध है.

# स्लिम स्मार्ट फोन

इन दिनों अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है तो वह है मोबाइल फोन. मोबाइल फोन कई तरह के होते हैं और उनमें सबसे नई कड़ी है स्मार्ट फोन की. स्मार्ट फोन दरअसल एक ऐसा एडवांस फोन है जिसके गणन की क्षमता और कनेक्टिविटी सामान्य फोन से कई गुना ज़्यादा होती है. एक स्मार्ट फोन में पर्सनल डिजिटल सिस्टम (पीडीए) और मोबाइल फोन का सम्मिश्रण होता है. ये मीडिया प्लेयर, वाई-फाई और मोबाइल ब्रॉडबैंड की भी सुविधा देते हैं. इनमें टच स्क्रीन भी होती है, जो अमूमन हाई रिजॉल्यूशन होती है. इनमें कैमरे भी होते हैं. स्मार्ट फोन पूरी तरह से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. ये सिस्टम हैं गूगल ऐंड्रायड, एप्पल आईओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फोन 7, नोकिया सिंबियन, ब्लैकबेरी ओएस, मीमो और मीगो. दुनिया भर में स्मार्ट फोन के ख़रीदारों की तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है. स्मार्ट फोन के बाज़ार में यूं तो हर फोन में कुछ न कुछ ख़ास होता है. दुनिया के सबसे पतले स्मार्ट फोन का ख़िताब है एलजी ऑप्टिमस ब्लैक के नाम. दुनिया के सबसे स्लिम स्मार्ट फोन का ख़िताब हासिल करने के लिए इस फोन ने एप्पल के आईफोन4 को पछाड़ दिया है. इसकी मोटाई मात्र 9.2 मिलीमीटर है. इस फोन में एंड्रॉयड 2.2 फोरयो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा, टच सेंसिटिव कंट्रोल, 2जीबी इंटरनल स्टोरेज, 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं. साथ ही इसका वज़न भी बेदह कम, केवल 109 ग्राम है.

# सुपर है ये कैमरा

**कैमरों के लिए मशहूर कंपनी कोडेक ने नया कैमरा बाज़ार में उतारा है जिसका नाम है मेक्स जेड 990. कैमरा मेक्स जेड 990 12 मेगापिक्सल का है. इसमें तस्वीर को ज़्यादा क्लोज करने के लिए 30 एक्स का ऑप्टिकल ज़ूम लैंस भी लगाया गया है.**

आपके ख़ूबसूरत पलों को संजोने के लिए कोडेक कंपनी ने एक ख़ास तरह का कैमरा बाज़ार में उतारा है. फोटोग्राफी के शौक़ीन लोगों के लिए बाज़ार में आया नया कैमरा फेवरिट गैजेट बन सकता है, क्योंकि इसमें ख़ास फीचर्स मौजूद हैं जो फोटोग्राफी को आसान बनाने के अलावा अच्छी क्वालिटी भी देते हैं. कैमरों के लिए मशहूर कंपनी कोडेक ने नया कैमरा बाज़ार में उतारा है जिसका नाम है मेक्स जेड 990. कैमरा मेक्स जेड 990 12 मेगापिक्सल का है. इसमें तस्वीर को ज़्यादा क्लोज करने के लिए 30 एक्स का ऑप्टिकल ज़ूम लैंस भी लगाया गया है. ऑप्टिकल ज़ूम के साथ ही इसमें स्टीरियो साउंड भी लगाया गया है. यह कैमरा सिर्फ़ स्टील फोटोग्राफी ही नहीं, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है. मेक्स जेड 990 कैमरा फुल एचडी 1080 वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है. इस कैमरे में क्लीयरिटी की कोई परेशानी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें 3.1 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन भी किया जा सकता है. इसमें स्टीरियो साउंड होने की वजह से रिकॉर्ड की गई वीडियो की आवाज़ ख़राब नहीं होगी और बाद में भी बिल्कुल साफ़ आवाज़ सुनाई दे सकेगी. कंपनी का मानना है कि यह कैमरा उपभोक्ताओं की सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा. इससे साफ़ और स्पष्ट तस्वीरें खींचने के साथ ही वीडियो फिल्म भी बनाई जा सकती है.

पैंटीन शैपू की नई ब्रांड एंबेसडर बनी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# शुद्ध जल से जीवन सरल है

यूरेका फोब्स ने उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन आर ओ वाटर प्यूरी फायर को एक्वागार्ड टोटल इंहांस के तहत लांच किया है, जो अबतक का पहला एंवायरमेंटल फ्रेंडली वाटर प्यूरी फायर है. इससे पानी को शुद्ध करने के दौरान पानी में होने वाले आवश्यक तत्व को दूसरे वाटर प्यूरी फायर के मुक़ाबले 30 प्रतिशत तक बचा सकते हैं. इंहांस रेंज में तीन तरह के आर ओ वाटर प्यूरी फायर हैं जो अलग-अलग टोटल डिजॉल्वड सॉलिड लेवल में अलग-अलग इस्तेमाल के लिए हैं. पानी में कई अशुद्ध चीज़ें भी मौजूद होती हैं, इन्हें हटाकर शुद्ध पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए यूरेका फोब्स के आर ओ में टोटल डिजॉल्वड सॉलिड के अलग-अलग लेवल को जांच कर उन्हें हटाने की व्यवस्था की गई है. इनमें पहला ग्रीन आर ओ ऐसी जगहों के लिए है, जहां टोटल डिजॉल्वड सॉलिड लेवल 500 से कम है. दूसरा इंहांस आर ओ 500-1500 तक के स्तर के टोटल डिजॉल्वड सॉलिड लेवल वाले स्थान पर लगाने के लिए है, जिससे टोटल डिजॉल्वड सॉलिड लेवल को कम करके पानी को मीठा और प्योर बनाया जा सके. इंहांस आर ओ प्लस 15000 से ज़्यादा टोटल डिजॉल्वड सॉलिड लेवल वाले स्थान पर इस्तेमाल किए जाने के लिए है. पानी में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्सियम, सोडियम और पोटाशियम जैसे मिनरल्स होते हैं, जो शरीर और दिमाग़ की तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी हैं. ग्रीन आर ओ तकनीक वाले यूरेका फोब्स आर ओ इन मिनरल्स को पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया में छान कर नहीं निकालता है, जिससे पानी में ये ज़रूरी मिनरल्स मौजूद रहते हैं. ग्रीन आर ओ वाटर प्यूरी फायर के साथ कंपनी विश्वस्तरीय सुरक्षा मानक उपलब्ध करा रही है, जिनका किसी भी स्थान पर और किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है. भारत जैसे विकासशील देशों में जहां 80 प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल की वजह से होती हैं, वहां प्योराइट कॉम्पैक्ट उपभोक्ताओं को पीलिया, अतिसार, हैज़ा एवं टायफाइड जैसी जलजनित बीमारियों से पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देता है. इसकी अनूठी तकनीक बिना पानी उबाले, बिना बिजली यानी रनिंग वाटर के सभी प्रकार के हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं, परजीवियों एवं अशुद्धियों को समाप्त कर देती है. यह देश के सभी अग्रणी रिटेल आउटलेट्स में उपलब्ध है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

भोपाल गैस पीड़ितों के मुताबिक़ डाओ को ओलंपिक का प्रायोजक बनाने का अर्थ हमारी भावनाओं का मज़ाक़ उड़ाने के बराबर है. यह बात कुछ ऐसी ही है जैसे कि मृतकों की क़ब्रों पर नाच आयोजन किया जा रहा हो.



## ओलंपिक 2012

# डाओ प्रायोजक बना, विवाद शुरू

**हालांकि, किसी खेल के लिए प्रायोजक का चुनाव करना मेज़बान देश का मामला है और यह उसका अधिकार भी है. डाओ को लेकर जो समस्याएं भोपाल के लोगों को हैं, वह ज़रूरी नहीं कि मेज़बान देश को भी हो. ऐसे में लंदन ओलंपिक पर या ब्रिटेन की सरकार पर सवाल खड़ा करना मुश्किल है. लेकिन, हैरत की बात यह है कि भारत सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर अपना मुंह बंद ही रखा है. क्यों सरकार भोपाल गैस पीड़ितों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए एक बार भी औपचारिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराने से परहेज़ कर रही है?**

जैसे ही यह ख़बर आई कि डाओ कंपनी को भी लंदन ओलंपिक का प्रायोजक बनाया गया है, भारत में इस बात को लेकर भोपाल गैस पीड़ित संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया, लेकिन एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि भारत सरकार की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई भी बयान नहीं आया है. 2012 ओलंपिक खेलों में डाओ केमिकल्स स्टेडियम के आसपास 70 लाख पौंड के आर्टवर्क का ख़र्च उठाएगी. दरअसल, डाओ केमिकल्स ही वह अमेरिकी कंपनी है जिसने यूनियन कार्बाइड को ख़रीदा है. और यूनियन कार्बाइड ही वह कंपनी है जो 1984 में भोपाल में हुए गैस रिसाव की वजह से हज़ारों लोगों की मौत के लिए ज़िम्मेदार है और जिसके मुखिया वारेन एंडरसन की तलाश आज भी जारी है, ताकि उसे न्यायालय के दरवाज़े तक लाया जा सके और भोपाल गैस पीड़ितों को इंसाफ़ दिलाया जा सके.

दिसंबर 1984 की उस काली रात ने भोपाल को क़ब्रिस्तान में बदल डाला था. मौत का एक ऐसा खेल हुआ था, जिसे हज़ारों भोपालवासी अभी तक नहीं भूल पाए हैं. गैस रिसाव की वजह से भोपाल के कुछ इलाक़ों का भूजल अब भी प्रदूषित है. आज भी यहां के बच्चे जन्म से ही कई विकारों के साथ पैदा हो रहे हैं. दुनिया की औद्योगिक दुर्घटना के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती है. बाद में इसी यूनियन कार्बाइड को डाओ केमिकल्स ने ख़रीद लिया था. लेकिन वह अब तक वह भोपाल से अपना कारोबार शुरू नहीं कर सका है. चूंकि कई याचिकाएं अदालत में विचाराधीन है और साथ ही मुआवज़े का मामला भी अभी तक अटका हुआ है. डाओ के मुताबिक़ यूनियन कार्बाइड ने 1989 में 47 करोड़ डॉलर के मुआवज़े के बारे में जो समझौता किया था, वह अंतिम है. इस राशि के हिसाब से एक मृतक के परिवार के हिस्से में मात्र 1,400 पौंड की राशि आएगी. दूसरी ओर, गैस पीड़ितों के समर्थन में अभियान चला रहे लोगों का कहना है कि शहर का भूमिगत पानी अभी भी ज़हरीला है, जिसकी वजह से बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं और हमारी परेशानी अभी भी समाप्त नहीं हुई है. भोपाल गैस पीड़ितों के मुताबिक़ डाओ को ओलंपिक का प्रायोजक बनाने का अर्थ हमारी भावनाओं का मज़ाक़ उड़ाने के बराबर है. यह बात कुछ ऐसी ही है जैसे कि मृतकों की क़ब्रों पर नाच का आयोजन किया जा रहा हो.

ओलंपिक में हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके और भोपाल के रहने वाले असलम शेर ख़ान इस मुद्दे को विवाद नहीं, बल्कि भावनाओं का मामला बताते हैं. ख़ान कहते हैं कि अगर लंदन ओलंपिक में डाओ की मदद ली जा रही है तो इससे भोपाल के लोगों को बहुत दुख पहुंचेगा. हम भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से अपील करेंगे कि भारत को इस पर कड़ा विरोध जताना चाहिए. भोपाल गैस पीड़ित संगठन के एक कार्यकर्ता सतीनाथ सारंगी कहते हैं कि आज भी लोग यूनियन कार्बाइड हादसे की वजह से मारे जा रहे हैं. बहुत से बच्चे आज भी विकृतियों के साथ पैदा होते हैं. डाओ केमिकल्स इन सब ज़िम्मेदारियों को लेने से इनकार करता आया है, जो हो रहा है वह मानवता के लिए बहुत ग़लत है. हम भोपाल, दिल्ली और हो सके तो लंदन में विरोध प्रदर्शन करेंगे.

हालांकि, किसी खेल के लिए प्रायोजक का चुनाव करना मेज़बान देश का मामला है और यह उसका अधिकार भी है. डाओ को लेकर जो समस्याएं भोपाल के लोगों को हैं, वह ज़रूरी नहीं कि मेज़बान देश को भी हों. ऐसे में लंदन ओलंपिक पर या ब्रिटेन की सरकार पर सवाल खड़ा करना मुश्किल है. लेकिन, हैरत की बात यह है कि भारत सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर अपना मुंह बंद ही रखा है. क्यों सरकार भोपाल गैस पीड़ितों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए एक बार भी औपचारिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराने से परहेज़ कर रही है?

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

**"ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के देश हिस्सा लेते हैं. अगर लंदन ओलंपिक में डाओ जोन्स कंपनी की मदद ली जा रही है तो इससे भोपाल के लोगों को बहुत दुख पहुंचेगा. हम भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से अपील करेंगे कि भारत को इस पर कड़ा विरोध जताना चाहिए. भारत आज दुनिया की बड़ी शक्ति है, उसे अपनी बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखनी चाहिए."**

**-असलम शेर ख़ान,** *पूर्व हॉकी खिलाड़ी*

## जलवा क़ायम है

कहते हैं कि शीर्ष पर पहुंचना आसान है, लेकिन उस स्थान को क़ायम रखना मुश्किल, लेकिन मारिया शारापोवा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है. विश्व की पांचवीं वरीयता प्राप्त रूसी महिला टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा को भले ही ग्रैंड स्लैम ख़िताब जीते हुए तीन साल से ज़्यादा का वक़्त हो गया हो, लेकिन पेशेवर महिला खिलाड़ियों की सालाना कमाई के मामले में वह अब भी अव्वल हैं. तीन ग्रैंड स्लैम ख़िताब जीत चुकी शारापोवा लगातार 7वें साल फोर्ब्स पत्रिका की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर हैं. हाल में वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विम्बलडन के एकल स्पर्धा के ख़िताबी मुक़ाबले में पहुंचने वाली शारापोवा की कमाई वर्तमान में डब्ल्यूटीए रैंकिंग में शीर्ष पर क़ाबिज़ डेनमार्क की कारोलीन वोज्नियास्की से दोगुनी है. वोज्नियास्की कमाई के मामले में शारापोवा के बाद दूसरे स्थान पर हैं. शारापोवा की सालाना आय 2.5 करोड़ डॉलर है. उन्होंने अधिकतर कमाई विज्ञापन के ज़रिए की है. पिछले एक साल में शारापोवा महज़ एक ख़िताब जीत पाई हैं. वोज्नियास्की की सालाना आय 1.25 करोड़ डॉलर है. पिछले साल शारापोवा ने नाइकी कंपनी के विज्ञापन के लिए 8 सालों के लिए सात करोड़ डॉलर के क़रार पर हस्ताक्षर किया था. शारापोवा ने कंधे की चोट से उबरकर इसी साल टेनिस कोर्ट पर वापसी की है. शारापोवा मौजूदा वर्ष में विम्बलडन के ख़िताबी मुक़ाबले में चेक गणराज्य की खिलाड़ी पेत्रा क्वेतोवा से हार गई थीं.

तीसरे स्थान पर अमेरिका की मोटर रेसिंग चालक डानिका पैट्रिक हैं, जिनकी सालाना कमाई 1.2 करोड़ डॉलर है, जबकि चौथे स्थान पर विश्व की पूर्व शीर्ष वरीयता प्राप्त अमेरिका की महिला टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स हैं. वीनस की सालाना कमाई 1.15 करोड़ डॉलर है, जबकि बेल्जियम की टेनिस खिलाड़ी किम क्लास्टर्स की सालाना कमाई 1.1 करोड़ डॉलर है. वीनस की छोटी बहन सेरेना विलियम्स इस मामले में छठे स्थान पर हैं. सेरेना की सालाना कमाई 1.05 करोड़ डॉलर है.

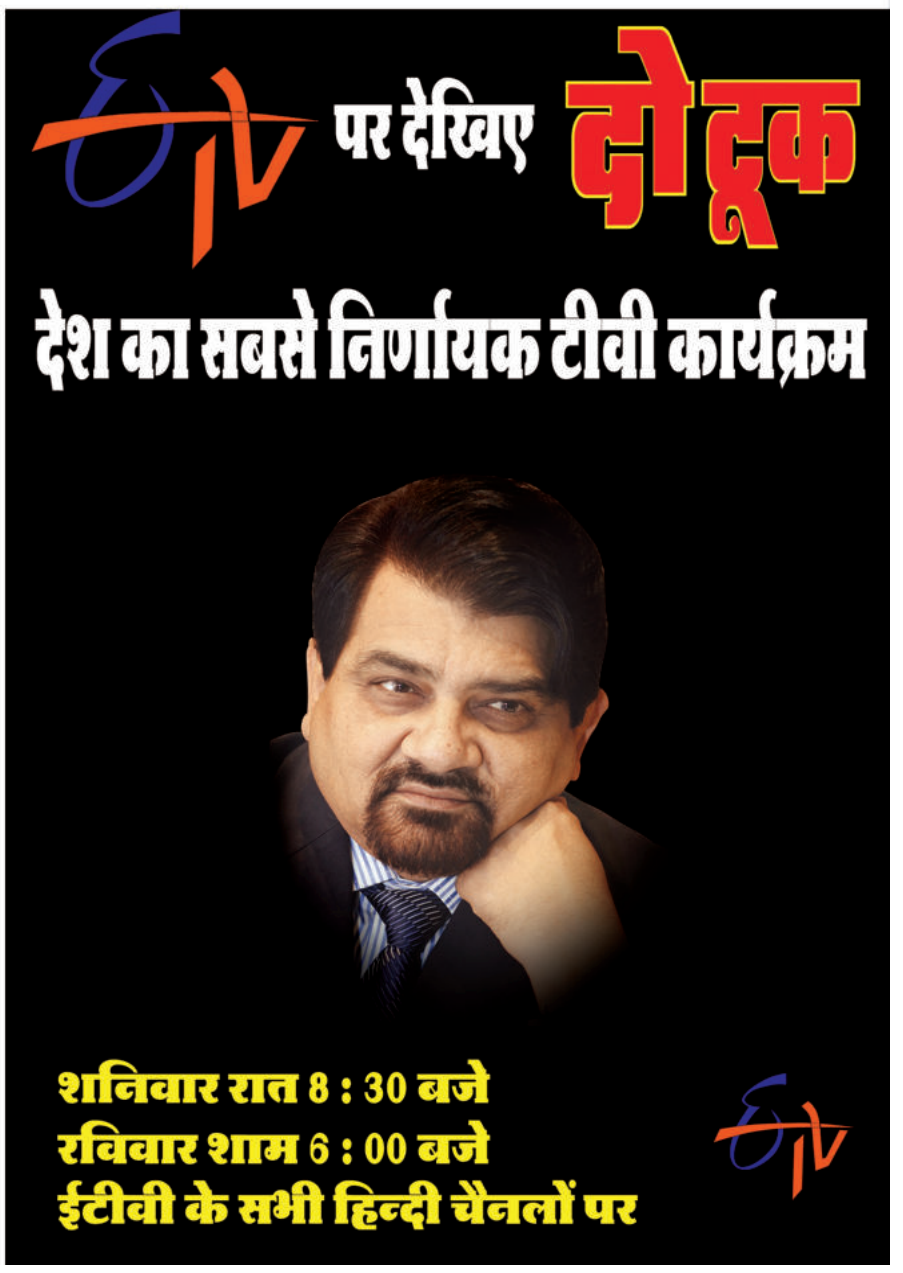

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

रूमी जाफ़री की इस फिल्म में वह अक्षय खन्ना के साथ दिखाई देंगी. इसमें भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया है और इसे यमला पगला दीवाना फेम नितिन मनमोहन प्रोड्यूस कर रहे हैं.

# अनुष्का नए लुक में दिखेंगी

एक बड़े बैनर के साथ लगातार फिल्में करके अनुष्का शर्मा काफ़ी समय से चर्चा में हैं. वैसे, रणवीर सिंह और उनके अफेयर को लेकर भी बातें आती जाती रही हैं. हालांकि अनुष्का का कहना है कि इस सब से डरकर वह अपने जीने का तरीक़ा नहीं बदल सकतीं. बॉलीवुड की हीरोइनों में भले ही ग्लैमरस दिखने की रेस लगी हो, लेकिन अनुष्का शर्मा को यह टैग पसंद नहीं है. अपने दम पर बैंड बाजा बारात जैसी हिट फिल्म देने वाली अनुष्का इन शब्दों से बहुत चिढ़ती हैं. उनका कहना है कि कुछ लोग यह मानते हैं कि फिल्म अच्छे कपड़ों और मेकअप के चलते हिट हुई. वह कहती हैं सच कहूं, तो मेरे लिए इससे ख़राब शब्द और हो ही नहीं सकते. अभी तक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्में करती आई अनुष्का की इमेज गर्ल-नेक्स्ट डोर की है, लेकिन जल्दी ही वह इससे एकदम अलग अवतार में नज़र आएंगी. बता दें कि लेडीज वर्सेज रिकी बहल में उनका लुक बेहद हॉट व ग्लैमरस है. वैसे, इस लुक में अनुष्का को फिट होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि यह एक्स-मॉडल पहले ही अच्छी फ़िगर की मलिका है. इस पर अनुष्का कहती हैं, ख़ुद को फिट रखने के लिए मुझे ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती. दरअसल, मेरी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर ही अच्छा है. हालांकि वह हेल्दी रहने के लिए वर्कआउट करती हैं. वैसे, उनकी इस नई फिल्म लेडीज वर्स रिकी बहल में उनकी ड्रेसेज अकी नरूला डिजाइन कर रहे हैं. अपने लुक के बारे में अनुष्का कहती हैं कि फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग गोवा में हुई है और इसी बात को ध्यान में रखकर ही ड्रेसेज डिज़ाइन की गई हैं. इसका मतलब है कि अनुष्का फिल्म में एक्सपोज भी करेंगी. आख़िर गोवा का मूड ही ऐसा रहता है. इस पर कहती हैं, पूरी फिल्म में मैं लूज पाजामा पहने दिखूंगी. इसमें लुक को बहुत ज़्यादा रिच दिखाने की बजाय कूल व कंफर्ट फैक्टर वाला रखा गया है. हालांकि मेरा करैक्टर इतना ईजी गोइंग नहीं है. फिल्म में वह काफ़ी एंबिशियस लड़की के रोल में हैं.

# नंदिता दास का पुत्र प्रेम

नंदिता दास इन दिनों अपने बेटे के साथ इतनी बिजी हैं कि उन्होंने फिल्मों को साइडलाइन कर दिया है. पहले जहां वह आने वाली 20 में से 2 स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करती थीं, वहीं अब उनकी चॉइस 40 में से 2 की हो गई है. उनका कहना है कि वह इंडस्ट्री गेम में शामिल नहीं हैं, इसलिए उन्हें काम को लेकर कोई इनसिक्युरिटी नहीं है. फिल्म इंडस्ट्री में अपने अब तक के सफ़र को उन्होंने कभी भी ऐक्टिंग और डायरेक्शन को करियर के तौर पर नहीं देखा. यह सिर्फ़ उनके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं. यही वजह है कि वह सिर्फ़ उन्हीं फिल्मों में काम करती हैं, जो उन्हें पसंद आती हैं. वह ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हैं. पिछले दिनों वह फिल्म आई एम में नज़र आईं. बतौर डायरेक्टर फ़िराक़ बनाने के तीन साल बाद उन्होंने इस फिल्म से वापसी की और उस वक़्त वह ख़ुद भी पांच महीने की प्रेगनेंट थीं. उनकी रियल कंडीशन ने उनके रोल में जान डाल दी थी. जब ओनिर उनके पास फिल्म का ऑफर लेकर आए थे, तो उन्होंने कुछ डिफरेंट की डिमांड की. फिल्म में उन्होंने एक ऐसी लड़की का रोल किया, जो अपनी ज़िंदगी में किसी पुरुष के आए बिना मां बनना चाहती थी. लेकिन इस साल उनकी केवल एक फिल्म आई एम रिलीज हुई. सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाने वाली नंदिता ने आगे की प्लानिंग में भी ऐसे ही विषय पर फिल्म बनाने का इरादा किया है. फ़िलहाल ट्रैफिकिंग पर आधारित एक फिल्म के लिए बातचीत चल रही है. हालांकि उन्होंने अभी कोई फिल्म साइन नहीं की है. इसकी शूटिंग साल के अंत में शुरू होगी. फिल्में बनाना तो नंदिता एंज्वॉय करती ही हैं, फ़िलहाल वह मदरहुड इंजॉय कर रही है और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहतीं, जिसके कारण उन्हें अपने बेटे विहान से अलग होना पड़े. तो कह सकते हैं कि उन्होंने फिल्मों को साइडलाइन कर दिया है. आजकल वह अपने बेटे की जॉब कर रही हैं और जब तक उनकी फिल्म शुरू नहीं हो जाती, तब तक उनके पास करने को सोशल वर्क है.

# वापसी की तैयारी में प्रीति

**लंबे समय के बाद प्रीति झिंगयानी एक बार फिर तैयार हैं अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत करने के लिए. जी हां, प्रीति अपने रियल लाइफ पार्टनर प्रवीण डबास के निर्देशन में बन रही फिल्म सही धंधे ग़लत बंदे की प्रोड्यूसर हैं और अपने इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए पटना आए प्रवीण और प्रीति ने चौथी दुनिया से बात की. प्रस्तुत है बातचीत के मुख्य अंश :-**

*प्रश्न : प्रीति पटना आने का अनुभव कैसा रहा?*

**प्रीति :** जी काफ़ी अच्छा, वैसे मैं कुछ साल पहले भी पटना आ चुकी हूं तो मैं इस जगह से काफ़ी परिचित हूं.

*प्रश्न : प्रीति सही धंधे ग़लत बंदे से बतौर प्रोड्यूसर आप अपने करियर की नई शुरुआत कर रही हैं तो कितना अलग और ख़ास रहा आपका यह रोल?*

**प्रीति :** जी मैंने एक्टिंग और प्रोड्यूसिंग अपने दोनों ही रोल को काफ़ी एंजॉय किया. मैं चाहूंगी कि मैं अपनी लाइफ में आगे इन दोनों ही रोल को बैलेंस करके चल सकूं.

*प्रश्न : क्या ख़ास देखने को मिलेगा इस फिल्म में?*

**प्रीति :** जी इसका जवाब तो प्रवीण आपको ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं.

**प्रवीण :** जी, यह फिल्म काफ़ी अलग है एज ए डायरेक्टर एंड राइटर मेरी भी यह पहली फिल्म है, लेकिन फिल्म स्क्रीनिंग के बाद मुझे भरोसा है कि लोगों को यह फिल्म ज़रूर पसंद आएगी. कहानी है चार लड़कों की, जो किसी कारण से ग़लत धंधे में आ जाते हैं और इसके बाद क्या होता है यह तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा. कैरेक्टर ओरिएंटेड फिल्म है और चार लीडिंग कैरेक्टर हैं, जो कि न्यू कमर हैं और मैं भी फिल्म में एक किरदार निभा रहा हूं.

*प्रश्न : प्रीति क्या आप भी आने वाले समय में टीवी रिएलिटी शो में नज़र आ सकती हैं?*

**प्रीति :** जी, एज एन एंकर या होस्ट, हां, लेकिन एज ए कंटेस्टेंट कभी नहीं.

*प्रश्न : प्रीति झिंगयानी का ड्रीम रोल क्या होगा?*

**प्रीति :** मुझे श्रीदेवी के किरदार बहुत पसंद हैं और मैं उनकी फिल्म चालबाज़ जैसा किरदार ज़रूर निभाना चाहूंगी.

*प्रश्न : चलते-चलते आपसे एक अंतिम सवाल कि हम प्रीति झिंगयानी को बड़े परदे पर वापस कब देखेंगे?*

**प्रीति :** जी मेरी वापसी पूरे तरीक़े से अच्छी कहानी और अच्छे डायरेक्टर पर निर्भर करेगी. मुझे कोई गंभीर और अच्छा रोल मिला तो मैं ज़रूर काम करना चाहूंगी.

तृप्ति पाठक
feedback@chauthiduniya.com

# आयशा की दूसरी पारी

आयशा टाकिया की झलक के लिए उनके फैंस बेक़रार हैं, लेकिन आयशा तो शादी के बाद नज़र ही नहीं आईं. कहां गुम हो गईं आयशा, शादी के बाद क्या इरादा है उनका, कहीं अपने फैंस को कोई सरप्राइज तो नहीं दे रही हैं आयशा? दरअसल बात यह है कि सलमान ख़ान के अपोजिट वांटेड जैसी सुपरहिट मूवी देने के बाद शादी रचाने वाली आयशा बॉलीवुड में दूसरी पारी के लिए तैयार हैं. ख़बर है कि वह फिल्म गली-गली में चोर हैं, से वापसी कर रही हैं. हाल में उन्होंने नागेश कूकूनूर के साथ फिल्म मोड़ पूरी की. शादी के बाद यह उनकी पहली फिल्म होगी. रूमी जाफ़री की इस फिल्म में वह अक्षय खन्ना के साथ दिखाई देंगी. इसमें भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया है और इसे यमला पगला दीवाना फेम नितिन मनमोहन प्रोड्यूस कर रहे हैं. जाफ़री कहते हैं कि फिल्म का टाइटल भ्रष्टाचार को ध्यान में रखकर तय किया गया. इसकी शूटिंग भोपाल में की जा रही है. फिल्म 50 दिनों में पूरी हो जाएगी. जाफ़री का कहना है कि उन्होंने अक्षय और आयशा को ध्यान में रखकर ही कैरेक्टर्स लिखे थे. अक्षय फिल्म में भ्रष्टाचार पीड़ित की भूमिका में होंगे, आयशा उनका साथ निभाने वाली पत्नी की भूमिका में. जाफ़री कहते हैं कि फिल्म आ अब लौट चलें, के दिनों से ही अक्षय के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग है. वहीं, डोर जैसी फिल्म में आयशा ने भी ख़ुद को प्रूव किया है. संगीत अनु मलिक ने तैयार किया है और इसका एक गाना रिकॉर्ड भी किया जा चुका है. रोचक तो यह है कि आयशा ने अपनी शादी से पहले भी अक्षय के साथ काम किया है. उस फिल्म का नाम था शादी से पहले. अब देखना यह है कि शादी के बाद क्या होता है!

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

## फिल्म प्रीव्यू

### मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी

हमने उन्हें ख़ूंखार विलेन के रूप में देखा है, एक मज़ेदार पिता की भूमिका के साथ-साथ हंसते-हंसाते पात्र और संजीदा किरदार में भी देखा है, लेकिन अपनी नई फिल्म में दिग्गज अदाकार अनुपम खेर हीरो के रोल में दिखेंगे, जो दुनिया को आतंकी हमलों से बचाएगा. 54 साल के कलाकार एक बैंक क्लर्क की भूमिका में नज़र आएंगे जो दुनिया की सैर पर जाता है, लेकिन उसकी टक्कर आतंकवादियों से हो जाती है. फिल्म मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी में खेर को दुनिया की सैर करते हुए अपना प्यार भी मिल जाता है. फिल्म में बिग बी ने विशेष भूमिका निभाई है. फिल्म में हंसी के पलों के बीच जॉर्ज बुश से लेकर लादेन और युद्ध से लेकर शांति तक की बातें हैं. मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी की ज़्यादातर शूटिंग स्विट्ज़रलैंड और स्कॉटलैंड में हुई है. करण राजदान निर्देशित इस फिल्म में खेर के अलावा शक्ति कपूर, भैरवी गोस्वामी, पाकिस्तानी कलाकार आबिद अली और ऑस्ट्रेलियाई मॉडल एम्मा कियरने हैं. फिल्म के प्रमोशनल सॉन्ग में अनुपम खेर बहुत ही दिलचस्प अंदाज़ में नज़र आएंगे. इस गाने के बोल हैं- बल्ले-बल्ले हो गई बल्ले-बल्ले... जिसे गाया है पॉप सेंसेशन ताज यानी स्टीरियो नेशन ने. फिल्म में मिस्टर भट्टी अमिताभ बच्चन का ज़बरदस्त प्रशंसक है. अंत में बिग बी मेहमान भूमिका में नज़र भी आएंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 22 अगस्त–28 अगस्त 2011

www.chauthiduniya.com

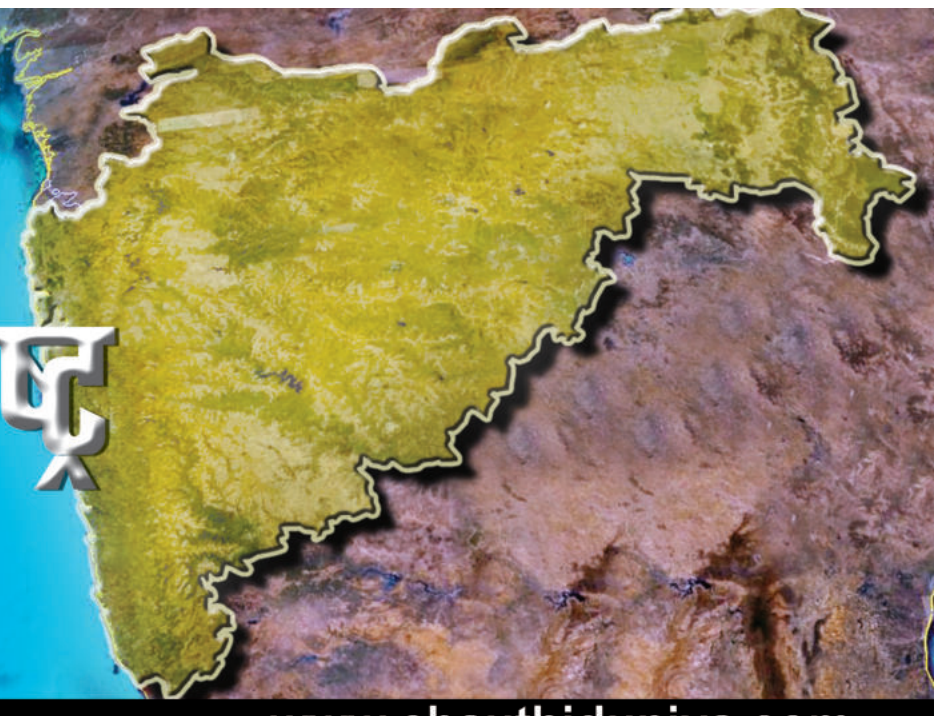


# छलावा न हो भू-अधिग्रहण

प्रवीण महाजन

भूमि अधिग्रहण को लेकर चारों तरफ उथल-पुथल मची हुई है. चाहे महाराष्ट्र का जैतापुर हो या विदर्भ का गोसीखुर्द. निम्न पैनगंगा हो या उत्तर प्रदेश का भट्टा पारसौल और नोएडा. उड़ीसा हो या बिहार, हर जगह ज़मीन के जबरन अधिग्रहीत किए जाने को लेकर सरकार और निजी कंपनियों के खिलाफ किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. सरकारी मनमानी और निजी कंपनियों की ओर से प्रशासनिक तंत्र पैसे का लालच देकर अपनी मुट्ठी में रखने की कवायद जारी है और धीरे-धीरे देशभर की उपजाऊ ज़मीन को औने-पौने दाम पर क़ब्ज़ाने का काला धंधा बेरोकटोक चल रहा है. इन सबके बीच केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में नया भूमि-अधिग्रहण विधेयक लाने जा रही है. हालांकि, यह प्रस्तावित विधेयक संसद में पेश होने से पहले ही विवादों में घिर गया है. नया भूमि-अधिग्रहण विधेयक भू-स्वामी और किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और सरकार व निजी कंपनियों के लिए किस हद तक लाभकारी होगा, वह संसद में पारित होने के बाद ही पता चलेगा.

हालांकि, इस विधेयक का मसौदा ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने जारी कर दिया है. इस विधेयक के मसौदे को तैयार करने में भट्टा पारसौल और उसके बाद नोएडा एक्सटेंशन में भूमि अधिग्रहण को लेकर मचे बवाल की महत्वपूर्ण भूमिका है. कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के भट्टा पारसौल के दौरे के बाद भूमि-अधिग्रहण कानून की खामियों को लेकर काफी हंगामा हुआ. उसके बाद केंद्र सरकार को अचानक भूमि अधिग्रहण अधिनियम में बदलाव करने की जरूरत महसूस हुई. नतीजतन नया बिल बन कर तैयार हो गया और अब संसद में पेश होगा. वैसे देखा जाए तो, इस बिल को लेकर अभी से ही सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं. अगले साल यानी 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में नए भू-अधिग्रहण विधेयक के आने से महाराष्ट्र में हो रहे भूमि-अधिग्रहण पर क्या कोई असर पड़ेगा, यह विधेयक पेश होने के बाद ही पता चलेगा.

महाराष्ट्र के जैतापुर में परमाणु संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए एक ओर सरकार अड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय किसान उसका तीव्र विरोध कर रहे हैं. गोसीखुर्द सरीखे राष्ट्रीय प्रकल्प के लिए पिछले 25 वर्षों से भूमि अधिग्रहण हो रहा है. हालांकि, वहां प्रकल्प ग्रस्तों को अभी भी मुआवजा पाने व पुनर्वास के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है. खास बात यह है कि, जो आज जैतापुर में हो रहा है, क्या वह नया विधेयक आने के बाद थम जाएगा. जैतापुर में किसानों के लिए आंदोलन में सक्रिय वैशाली पाटिल ने नागपुर में आयोजित एक व्याख्यान में बताया कि वहां के किसान किसी भी सूरत में अपनी जमीन परमाणु संयंत्र के लिए देने को तैयार नहीं हैं. इसलिए सरकार के प्रतिनिधियों ने जैतापुर में जमीन मालिकों के बच्चों को बहला-फुसलाकर अपने अभिभावकों पर दबाव डालकर परमाणु संयंत्र के लिए जमीन दिलाने को कहा. बाद में जब बच्चों को सरकार की मंशा और परमाणु संयंत्र से भविष्य में होने वाले नुकसान की हकीकत बताई गई तो सभी छात्र-छात्राओं ने सरकारी प्रतिनिधियों से साफ कहा कि वे स्कूल-कॉलेज छोड़ देंगे पर अपने अभिभावकों से यह नहीं कहेंगे कि जमीन परमाणु संयंत्र को दें. इसके बाद सभी छात्रों ने परमाणु संयंत्र लगाने के सरकारी फैसले के खिलाफ मोर्चा भी निकाला था. सुश्री पाटिल ने बताया कि, जब मुख्यमंत्री हमारे जैतापुर आए तो गांव वालों के साथ ही गांव की सरपंच से कहा कि परमाणु संयंत्र के लिए जमीन देने वाले लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी. लेकिन जब उनके इस आश्वासन पर भी सरपंच चुप रहीं तो मुख्यमंत्री ने उनसे उनकी खामोशी की वजह पूछी. इस पर वहां की कम पढ़ी-लिखी महिला सरपंच का जवाब सुनकर मुख्यमंत्री की बोलती बंद हो गई. सरपंच ने कहा कि जब बिस्तर के नीचे अजगर बैठा हो तो सुकून से नींद कैसे आ सकती है. जैतापुर के लिए परमाणु संयंत्र किसी अजगर से कम नहीं है. शायद, यही वजह है कि वहां के किसान इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं और अपनी जमीन किसी भी हालत में देने को तैयार नहीं हैं. बावजूद इसके सरकार जबरन जमीन अधिग्रहण करने पर तुली है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार नया भूमि-अधिग्रहण बिल लाने के साथ अपना नजरिया बदलेगी?

नए भूमि अधिग्रहण बिल के मसौदे के अनुसार निजी कंपनियां अब सीधे किसानों से जमीन नहीं खरीद सकेंगी. भूमि-अधिग्रहण का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा, सिवाए रक्षा और आपदा प्रबंधन के मामले को छोड़कर. भूमि-अधिग्रहण से पहले प्रभावित होने वाले लोगों में 80 फीसदी लोगों की सहमति लेना अब कानूनी तौर पर जरूरी होगा. भूमि-अधिग्रहण के लिए जो नियम तय किए जाएंगे, उसे बदला नहीं जा सकेगा. एक से अधिक फसल देने वाली कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा. इसके अलावा पुनर्वास कानून को भी इस विधेयक के साथ ही जोड़ दिया गया है. जिस व्यक्ति की जमीन अधिग्रहण क्षेत्र में आएगी, उसे सरकारी दर से 6 गुना अधिक रकम मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा. जमीन का सरकारी दर भूमि की रजिस्टर्ड बिक्री कीमत पर तय किया जाएगा. भू-स्वामी को अगले 20 वर्ष तक 2000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा. पुनर्वास क्षेत्र या कॉलोनी में आधारभूत सुविधाएं पहले के मुकाबले अच्छी और रहने योग्य होंगी. भूमि-अधिग्रहण की ये नियम और शर्तें सरकार ने पिछले दिनों तय की हैं. प्रशासनिक अधिकारियों व सत्तारूढ़ दल के समर्थकों का यह मानना है कि यदि संसद ने ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के इस बिल को मंजूरी दे दी तो भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे देश में मची तू-तू मैं-मैं पर विराम लग जाएगा. दरअसल, इसकी वजह यह है कि भूमि-अधिग्रहण के पुराने प्रावधानों के अनुसार सरकार के पास पहले असीम शक्तियां थीं. जो नए प्रस्तावित विधेयक में सरकार के पास नहीं होंगे. नए विधेयक में अधिग्रहण के साथ पुनर्वास से जुड़े प्रावधानों को भी जोड़ दिया गया है. इसके अलावा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की शर्तों को भी काफी हद तक मान लिया गया है, जबकि जयराम रमेश के पूर्ववर्ती विलासराव देशमुख ने एनएसी के कई महत्वपूर्ण सुझावों को ख़ारिज़ कर दिया था.

ऐसे में यह सवाल पैदा होना लाजिमी है कि क्या नया भूमि-अधिग्रहण विधेयक भू-स्वामियों के लिए वाकई फ़ायदेमंद होगा? महाराष्ट्र के भंडारा जिले में निर्माणाधीन राष्ट्रीय प्रकल्प गोसीखुर्द, यवतमाल का निम्न पैनगंगा, अमरावती में बुल इंडिया के पॉवर प्लांट सोफिया और जैतापुर में परमाणु रिएक्टर की स्थापना और सिंचाई योजनाओं, सड़क परियोजना से प्रभावित किसानों को न्याय मिल पाएगा. सरकार की ओर से एमआईडीसी, मिहान व कई अन्य परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत जमीन से विस्थापित हुए लोगों को अभी तक पुनर्वास का लाभ नहीं मिल सका है. इतना ही नहीं, उनसे ली गई जमीन पर कई औद्योगिक इकाई लगाई गई हैं. इसके अतिरिक्त हजारों हेक्टेयर भूमि अब भी खाली पड़ी हुई है. इन जमीनों को बिल्डरों को सौंप दिया गया है. नांदेड़ में एमआईडीसी के नाम पर किसानों से ली गई कुल भूमि में से 80 हेक्टेयर पर अभी तक कोई औद्योगिक इकाई नहीं लगाई गई है. इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ीं मेधा पाटकर ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में महाराष्ट्र शासन ने यह जानकारी दी है, कि एमआईडीसी के लिए अधिग्रहीत कुल जमीन में से 80 हजार हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी है. एक ऐसी ही जानकारी सेवानिवृत आयुक्त अरुण भाटिया ने भी दी है. उनके मुताबिक सरकार किसानों से जमीन अधिग्रहीत तो कर लेती है, लेकिन इस्तेमाल के बाद जो भूमि शेष बच जाती है उसे किसानों को लौटाया नहीं जाता.

शेष पृष्ठ संख्या - 18 पर

## विस्थापितों के पुनर्वास पर दी जाने वाली सुविधाएं

महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्ति पुनर्वास अनिनियम 1999 की धारा 10(3) के अनुसार कुल 18 नागरिक सुविधाएं देने का प्रावधान है- 1) जनसंख्या के अनुसार खुला कुंआ, बंधा कुंआ, नल द्वारा जलापूर्ति योजना अथवा किसी भी प्रकार की पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था होना. 2) प्रसाधन की सुविधा संपन्न स्कूल व खेल का मैदान, 3) ग्रामपंचायत कार्यालय, चावड़ी और समाज मंदिर, 4) पक्के रास्ते व डांबरीकरण की हुई सड़कें, गांव तक पक्का पहुंच मार्ग 5) रास्तों पर पथदीप सहित बिजली आपूर्ति और आवश्यक होने पर थ्री फेस बिजली कनेक्शन, 6) छप्पर, चबूतरा, बिजली, पानी आपूर्ति सहित दहनभूमि और वहां तक जाने का पक्का मार्ग, 7) पक्की खुली हुई नालियां, 8) आर्थिक सहायता प्राप्त व्यक्तिगत शौचकूप व अति आवश्यक होने पर वहां सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था, 9) गाय-भैंसों को रखने के लिए खुली जगह, पानी के लिए हौद, 10) एस.टी. बससेवा व यात्रियों के ठहरने के लिए पक्का भवन व जमीन, 11) आवश्यक होने पर घरेलू फसल के लिए खुली जगह, 12) चारागाह के लिए सरकारी जमीन, 13) बाजार के लिए विकसित जमीन, आवश्यक होने पर प्रकल्पग्रस्त व्यक्ति को खेत जाने के लिए मार्ग, 14) गावठान होने पर विस्तार के लिए जमीन, 15) नए गांवठान पर जनसंख्या के अनुसार माध्यमिक शाला, दवाखाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बैंक, डाकघर, बच्चों के लिए बगीचा बाबत जमीन, 16) सार्वजनिक आयोजनों व पंजीकृत संस्थाओं के लिए पुराने गांवठान में जमीन, 17) खेल के मैदान के लिए जमीन, 18) उपरोक्त सूची में दी गई सुविधाओं के अलावा प्रकल्पग्रस्त लोगों को जरूरत होने पर पुराने गावठान में अन्य सहूलियत की व्यवस्था की जाएगी.

केंद्र सरकार की परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को पुनर्वास के दौरान राष्ट्रीय पुनर्वास अधिनियम 2007 के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली 26 सुविधाएं- 1) स्वच्छ पीने का पानी, 2) शाला व प्रशिक्षण की व्यवस्था, 3) समाज मंदिर, 4) सड़कें व रास्ते, 5) विद्युत आपूर्ति, 6) कब्रिस्तान व श्मशान भूमि, 7) सार्वजनिक स्वच्छता, 8) मलनिस्सरण की व्यवस्था, 9) जानवरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, 10) सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, 11) घरेलू उपज की व्यवस्था, 12) चारागाह, 13) जलसंचय की व्यवस्था, 14) स्वास्थ्य केंद्र, 15) पोस्ट ऑफिस, 16) सहकारी संस्था, 17) बच्चों के खेलने के लिए मैदान, 18) सामाजिक वनीकरण व कृषि संबंधी वृक्ष लगाने की व्यवस्था, 19) माता व बाल संगोपन के लिए पोषक आहार योजना लागू करना, 20) पूजा स्थल 21) परंपारिक आदिवासी संस्था के लिए जमीन, 22) पंचायत घर 23) खाद व बीज संग्रहित करने के लिए जगह, 24) सार्वजनिक तालाब, 25) सुरक्षात्मक उपाय योजना, 26) सस्ते अनाज की सुविधा इत्यादि.

चौथी दुनिया



ग़ौरतलब है कि राज्य में तक़रीबन 95000 प्राथमिक, माध्यमिक निजी अनुदानित स्कूलें हैं. इन स्कूलों को वेतनेतर अनुदान पिछले 12 वर्षों से नहीं दी गई है.



गोटमार में सावरगांव के लोग भवानी माता मंदिर में पूजा-अर्चना कर पलाश के पेड़ रूपी झड़े पर नारियल एवं तोरण बांधकर जामनदी के बीच गाड़ते हैं.

चौथी दुनिया



## महाराष्ट्र हलचल



मुंबई स्थित शिवनेरी सभागृह में महाराष्ट्र माथाडी कामगार संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलन में संगठन के अध्यक्ष पोपटराव पाटील का सत्कार करते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, कामगार मंत्री राजेंद्र गावित, आनंदराव पाटील व अन्य.



शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक, राजन विचार, बालाजी किणीकर व अन्य टोल वसूली के विरोध में विधान भवन में प्रदर्शन करते हुए.



राष्ट्रवादी कांग्रेस के अदिवासी सेल का महाराष्ट्र अध्यक्ष बनाए जाने पर दशरथ मड़ाव का मुंबई स्थित पार्टी कार्यालय में स्वागत करते उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड़व व अन्य.



महाराष्ट्र शासन सूचना व जनसंपर्क महासंचनालय की ओर से उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-2010 का वितरण करते मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के हाथों लोकमान्य तिलक जीवन गौर पत्रकारिता पुरस्कार ग्रहण करते हुए वरिष्ठ पत्रकार दीनू रणदिवे साथ में सूचना व जनसंपर्क राज्यमंत्री फौजिया खान, सचिव विजय नाहटा व अन्य.



शिवणगांव में प्रकल्पग्रस्त लोगों से उनकी समस्याओं को सुनते नागपुर सुधार प्रन्यास के सभापति प्रवीण दराडे व अन्य



नागपुर के वसंतराव देशपांडे सभागृह में सूफी संगीत प्रस्तुत करती डॉ. ममता जोशी.



नागपुर के मोमिनपुरा इलाके के नागरिकों से चर्चा करते पुलिस आयुक्त अंकुश धनविजय.



# छलावा न हो भू-अधिग्रहण

पृष्ठ 17 का शेष

उन्होंने बताया कि उनके समय में अधिग्रहित जमीन में से आज भी तकरीबन 15-20 हज़ार हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी है. दरअसल, नया भूमि अधिग्रहण विधेयक महज एक छलावा है. [illegible]

feedback@chauthiduniya.com





महाराष्ट्र में बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है यह बाल हक संरक्षण आयोग (बाल अधिकार संरक्षण आयोग) के पदाधिकारियों व सदस्यों को भी पता नहीं है. उनका अनुमान है कि राज्य में बाल श्रमिकों की कुल संख्या साढ़े चार लाख के करीब है. यह राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग के अनुमानित आंकडे़ हैं. वहीं राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रमिकों के लिए कार्यरत सामाजिक संगठनों के अनुसार महाराष्ट्र में बाल श्रमिकों की संख्या सरकारी आंकड़ों से दोगुनी से भी अधिक है.



# विकास को बौना करती बाल मज़दूरी







दीपेश काशीद

बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, पर किन बच्चों को? सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल श्रम वर्तमान में एक कड़वी सच्चाई है. इन बच्चों के जीवन को रौशन करने के लिए सरकार ने नियम-कायदे और योजनाएं अच्छी जरूर बनाई हैं पर उनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कितने कारगर ढंग से किया गया है? इस ओर ध्यान देने का वक्त उन लोगों के पास नहीं है, जो बच्चों को देश का भविष्य बताते थकते नहीं हैं. इस समस्या पर रोक लगाने के सारे उपाय नाकाफी साबित हुए हैं. समस्या के सारे उपाय सतही साबित हुए हैं. ऐसा क्यों है कि कड़े कानून होने और बाल श्रमिकों के पुनर्वास की योजना के बाद भी बालश्रम प्रथा जस की तस आज के आधुनिक भारत में भी बनी हुई है. महाशक्ति की लालसा रखने वाले देश के लिए यह एक कलंक से कम नहीं कहा जा सकता है और इस कलंक को कम आंकने के लिए सरकार आंकड़ेबाजी का खेल खेलती हैं जो आम आदमी की समझ में नहीं आता है. उनको सरकार की उपाय योजनाओं व कानूनों की जानकारी कभी-कभार मंत्रियों-नेताओं या किसी वरिष्ठ अधिकारी के भाषण में सुनने को मिल जाती है. महाराष्ट्र में बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पदाधिकारियों व सदस्यों को भी पता नहीं है. उनका अनुमान है कि राज्य में बाल श्रमिकों की कुल संख्या साढ़े चार लाख के करीब है. यह राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग के अनुमानित आंकड़ें हैं. वहीं राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रमिकों के लिए कार्यरत सामाजिक संगठनों के अनुसार महाराष्ट्र में बाल श्रमिकों की संख्या सरकारी आंकड़ों से दोगुनी से भी अधिक है.

पिछले दिनों अकोला जिले में बालश्रमिकों के हित संरक्षण करने वाली विविध संगठनों की गतिविधियों का जायजा लेने महाराष्ट्र बाल हक संरक्षण आयोग सदस्य सूर्यकांत कुलकर्णी पधारे थे. उन्होंने पत्रकारों से औपचारिक बातचीत करते हुए बताया कि पूरे राज्य में साढ़े चार लाख के करीब बाल श्रमिक हैं मगर ये आंकड़े अनुमानित हैं. बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है. कुलकर्णी साहब ने एक और सच्चाई बताई कि राज्य में बाल श्रमिकों के उद्धार के लिए कार्य कर रही संस्थाओं में से मात्र 15-20 प्रतिशत संस्थाओं का काम संतोषजनक है. बाकी बोगस हैं या नाममात्र की हैं. ऐसी संस्थाओं की जांच अलग तरीके से करने का प्रस्ताव आयोग ने सरकार को दिया है. बाल अधिकार संरक्षण बाबत कानून रहने पर भी उसकी कमजोरियां निकाल कर कारखाना संचालक इससे साफ बच निकलता है. मगर अब इस परिस्थिति में बदलाव आएगा. अब उन कारखानों में जहां बच्चों से काम कराया जाता है, उसके संचालक को स्कूल खोलना अनिवार्य किया जा रहा है. इसे कड़ाई से लागू किया जाएगा. कुलकर्णी साहब ने यह हकीकत तो बयान कर दी कि राज्य में बाल श्रमिकों की वास्तविक संख्या से बाल हक संरक्षण आयोग अनजान है. सरकार व आयोग जो भी उपाय योजनाएं बना रहे हैं वह अनुमान के आधार पर बना रहे हैं. इन स्थितियों में यह सवाल उठना लाजिमी है कि अनुमान पर आधारित योजनाएं कहां तक कारगर साबित हो सकती हैं? वैसे भी सारी सरकारी योजनाएं भ्रष्ट प्रशासन के मकड़जाल में फंस कर दम तोड़ने लगती हैं.

दरअसल गरीबी की कोख में ही बाल मजदूरी का जन्म होता है. एक बार जो बालक मजदूर बन जाता है वह जिन्दगी भर मजदूरी करने को अभिशप्त हो जाता है. यह किसी विडंबना से कम नहीं है कि आज हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा भारत विश्व पटल पर महाशक्ति बनने का सपना संजोए है, देश के डेढ़-दो करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करने को विवश हैं. बचपन बचाओ आंदोलन के अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पौने दो करोड़ बाल श्रमिक है. महाराष्ट्र में देश के बाल मजदूरों में से 9.5 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाने की बजाय बालमजदूरी करने को मजबूर हैं. अब यदि राष्ट्रीय आंकड़ों के लिहाज से बाल हक संरक्षण आयोग के सदस्य कुलकर्णी साहब द्वारा व्यक्त आंकड़ों की तुलना करें तो करीब 6 से 7 लाख का अंतर दिखाई देता है यानी राज्य मे बाल मजदूरों की संख्या दस से बारह लाख के आसपास होनी चाहिए. वैसे हर सरकार इस मामले में असलियत प्रकट नहीं करना चाहती है, इसके कई सामाजिक-आर्थिक कारण हैं. इसीलिए सरकार व उसके बाल श्रम से संबंधित विभागों के पास बाल मजदूरों के सही आंकड़े नहीं हैं. हालांकि बाल श्रमिकों के उद्धार के लिए हर साल करोड़ों का बजट बनाया जाता है पर आवंटित रकम कहां जाती है? इसका जवाब न मंत्रियों के पास है और न अफसरों के पास. महाराष्ट्र सरकार के श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल 3 लाख 90 हजार बाल मजदूर राज्य में थे. इनमें से ढाई लाख कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे. इस लिहाज से भी यदि कुलकर्णी द्वारा अनुमानित बाल मजदूरों के आंकड़ों से तुलना की जाए तो उनमें 60 हजार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे यह पता चलता है कि सरकार इस समस्या पर गंभीर नहीं है. हालांकि राज्य के श्रम मंत्रालय की प्रधान सचिव डॉ. कविता गुप्ता की अध्यक्षता में बाल श्रमिकों को छुड़ाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया था पर उसने कितने बाल श्रमिकों को मुक्त करा कर उनका पुनर्वास किया, इसके अब तक कोई आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं. वर्ष 2011 के प्रारंभिक माहों में सरकार द्वारा राज्य के सात जिलों में कराये गए सर्वे में जो आंकड़ें सामने आए हैं, वह हमारी आखें खोलने के लिए पर्याप्त हैं. सर्वे के अनुसार राज्य के सात जिलों में बाल मजदूरों की संख्या 46 हजार 220 है. नांदेड़ में 11195, जालना में 10162, बीड़ में 9675, जलगांव 6223, नंदुरबार 4121, अमरावती 3314 और धुले में 1530 बाल मजदूर हैं. ये सरकारी आंकड़ें है और सिर्फ सात जिलों के हैं बाकी 26 ज़िलों का सर्वे अभी तक हुआ ही नहीं है.

चिंताजनक बात यह है कि अधिकतर बाल मजदूर को बेहद खतरनाक कामों में लगाया गया है. एक रिपोर्ट के अनुसार हर एक मिनट में एक बाल मजदूर काम से जुड़ी दुर्घटनाओं का शिकार होता है. बीमारी से ग्रस्त होता है और मानसिक सदमा झेलने को मजबूर है. इन स्थितियों में यदि वास्तव में बच्चे देश का भविष्य होते हैं तो जोखिम भरे काम करने वाले बच्चों को की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए. मगर बाल मजदूर दिवस को जो चिन्ता बच्चों को लेकर भा[illegible] दिया जाता है. बच्चे चाय [illegible] काम करते नज़र आते हैं. [illegible] शिक्षित करने के नाम पर [illegible] भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई. [illegible] से चौदह वर्ष तक के कुल [illegible] कक्षा दसवीं तक पहुंचते-[illegible] तलाश में भटकने लगते हैं. [illegible] न कोई काम करते हैं. इ[illegible] समाधान होता नहीं दिखाई[illegible] लिखा रहता है कि देश का [illegible] झुठलाती है राज्य की बाल [illegible]

feedback@chauthiduniya.com



# पांढुर्णा का विश्वप्रसिद्ध गोटमार मेला





विजय धवले

मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्णा में प्राचीन काल से गोटमार की परम्परा चली आ रही हैं. आज 21वी सदी में इस प्रकार की घटनायें कम ही दिखाई देती हैं. परन्तु आज भी परम्परा के नाम पर पांढुर्णा मे प्रतिवर्ष पोला पर्व के दूसरे दिन गोटमार का आयोजन किया जाता है. पांढुर्णा मे जाम नदी के दोनों ओर सैकड़ों की संख्या में लोग एक-दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं. पत्थरों से लड़ा जाने वाला यह युद्ध पाषाण युग का स्मरण कराता है, जिसमें हथियारों का उपयोग नहीं किया जाता था, वरन पत्थरों से एक-दूसरे को पराजित कर अपने सम्मान की रक्षा के लिये युद्ध किया जाता था. गोटमार सुबह 10 बजे से सूर्यास्त तक चलता है. पत्थरों की बौछार के चलते प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल जाते हैं. इस प्राचीन परम्परा को बंद कराने के लिये प्रशासनिक स्तर पर अनेक बार प्रयास किये गये, पर सभी प्रयास विफल हो गये. इसके स्वरूप को बदलने के लिये प्रशासन ने पत्थरों की जगह रबर की गेंदो को गोटमार के स्थान पर रखने के प्रयास किये परन्तु यह प्रयास भी विफल हो गया है. दो वर्ष पूर्व गोटमार को रोकने के लिये झंडा ही नहीं गाड़ने दिया गया. इस पर भवानी माता मंदिर से झंडा हटाकर चंडी माता मंदिर पहुंचा दिया गया. परन्तु इसके बावजूद भी लोगों के आक्रोश पर प्रशासन को झंडा वापस जाम नदी मे पहुंचाकर गोटमार संपन्न कराने के लिये विवश होना पड़ा.

मध्यप्रदेश राज्य के छिन्दवाड़ा जिला मुख्यालय से 100 कि.मी. की दूरी, पर नई दिल्ली-चेन्नई मध्य रेलवे मार्ग व नई दिल्ली-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 69 पर स्थित लगभग 50,000 आबादी वाली संतरानगरी के नाम से प्रसिद्ध पांढुर्णा में सदियों से पोला त्यौहार के दूसरे दिन गोटमार मेला सम्पन्न होता है. युद्ध में जिस तरह आक्रमण एवं प्रतिरक्षा की स्थिति होती है, उसी तरह पांढुर्णा के गोटमार में सावरगांव के लोग भवानी माता मंदीर में पूजा-अर्चना कर पलाश के पेड़ रूपी झंडे पर नारियल एवं तोरण बांधकर जामनदी के बीच गाड़ते हैं. इस झंडे की रक्षा के लिये अपने जान की बाजी लगाने के लिये लोग मैदान मे उतरकर, दूसरी तरफ खड़े पांढुर्णा पक्ष के लोगों पर पत्थरों से आक्रमण करते हैं, और पांढुर्णा के लोग भी पत्थरों के जवाब मे सावरगांव के लोगों पर पत्थरों की बौछार करते हैं और झंडे को काटकर अपने कब्जे में करने का प्रयास दोनों पक्ष करते हैं. अगर पांढुर्णा के लोग झंडा काटने में सफल हो जाते हैं तो गोटमार समाप्त हो जाती है. परन्तु असफलता की स्थिति में दोनों पक्षों के लोग आपसी समझौते पर झंडा उखाड़ कर गोटमार समाप्त कर देते हैं. इसके पश्चात उक्त झंडा किले पर स्थित मां चंडिका के मंदिर में समर्पित कर देते हैं.

**ऐतिहासिक मान्यता –** गोटमार प्रारंभ होने के संबंध में कई किवदंतियां प्रचलित हैं. किन्तु उसका ठोस आधार यह माना जाता है कि प्राचीन पिंडारी जाती के लोगों की बहुलता का यह क्षेत्र कालान्तर में नागपुर के शासक भोसले ने अपने आधिपत्य में कर लिया था. इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखने के लिये देवगढ़ के आदिवासी शासक दलपत शाह को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था. दलपत शाह ने नगर के किले में मां चंडिका की स्थापना की थी. किन्तु कुछ समय पश्चात दलपत शाह ने राजस्व देने से इंकार कर भोसले नरेश से बगावत कर दी थी. स्वयं को यहां का अधिपति घोषित कर दिया था. इससे दलपत शाह को सबक सिखाने के लिये भोसले नरेश ने अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजी. किन्तु दलपत शाह की आदिवासी सेना के पास युद्ध के हथियारों का अभाव था. इसलिए उन्होंने पत्थरों से मुकाबला किया. इस युद्ध में पत्थरों की मार से भोसले की सेना को हार का सामना करना पड़ा था. बाद में दलपत शाह ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और उसे जाटवा के नाम से जाना जाने लगा. पांढुर्णा मे आज भी जाटवा वार्ड और उसके व्दारा निर्मित प्राचीन चंडिका मंदिर मौजूद है. इस घटना को परम्परा मानकर सदियों से प्रतिवर्ष गोटमार मेला आयोजित किया जाता है.

**गोटमार से हानि –** यह विवाद का विषय नहीं है कि गोटमार मेले की शुरूआत कैसे हुई और उससे क्या लाभ हुआ. किसने साहस का परिचय दिया, बल्कि महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अब तक कितने लोग घायल हुए और कितने लोगों की मौत हो गई. गोटमार मेला आज के शान्तप्रिय देश मे लिये क्या संदेश देता है? प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं. गत वर्ष 400 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. गोटमार मेला के अवसर पर पांढुर्णा मे शराब पर बंदी रहने से शराब की कालाबाजारी बढ़ जाती है. लोग शराब पीकर गोटमार में शामिल होते हैं. पुलिस प्रशासन शराब बंदी के लाख दावे करता हो, लेकिन गोटमार मे अधिकांश लोग शराब पीकर रहते हैं. कुछ लोग गोटमार मे गोफन का प्रयोग करते हैं. गोफन में पत्थर को रस्सी से बांधकर फेंका जाता है जिससे पत्थर अधिक तीव्रता से सामने वाले व्यक्ति पर प्रहार करता है. इससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है. यदि पत्थर सिर पर लगता है तो अधिक रक्तस्राव से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

# सरकार ने अनुदान रोका



आलोक मिश्रा



महाराष्ट्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय अपनी शिक्षा नीति के प्रति कितना सजग है यह उसके द्वारा किए गए निर्णयों और उनके अमल से पता चलता है. इसका उदाहरण है राज्य की निजी अनुदानित शिक्षा संस्थाओं को दिया जाने वाला अनुदान. सरकार निजी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान तो देती है पर तरसा-तरसा कर देती है. इसी का नतीजा है कि कई स्कूलों को संपत्ति नीलामी तक की नोटिस मिल चुकी है. कई स्कूलों पर महानगर पालिका का करोड़ों का कर और बिजली बिल बकाया है. वजह है शिक्षा संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान को सरकार ने रोक रखा है. सरकार पर अनुदानित स्कूलों को मिलने वाले अनुदान के 792 करोड़ रुपये बकाया हैं. वेतनेत्तर अनुदान की रकम पिछले 12 वर्षों से सरकार ने रोक रखी है. रोकने का कोई स्पष्ट कारण संस्था संचालकों को नहीं बताया गया है. यह हाल तब है जब पूरे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है और निजी शिक्षा संस्थाओं में भी 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश दिए जाने का प्रावधान किया गया है. इससे निजी शिक्षा संस्थाओं के सामने विकट संकट पैदा हो गया है.ग़ौरतलब है कि राज्य में तकरीबन 95000 प्राथमिक, माध्यमिक निजी अनुदानित स्कूल हैं. इन स्कूलों को वेतनेतर अनुदान पिछले 12 वर्षों से नहीं दिया गया है. इनकी भरपाई के रूप में इन निजी स्कूलों को बिना अनुदानित कक्षा 11वीं की फीस बढ़ाने की इजाजत देने की मांग राज्य शिक्षण संस्था महामंडल ने राज्य सरकार से की है. इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए महामंडल के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटिल की अध्यक्षता में अगस्त माह के पहले सप्ताह में बैठक हुई. इस संबंध में पाटिल का कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से बारह साल पहले निजी शिक्षा संस्थाओं को कुछ मात्रा में वेतनेतर अनुदान दिया जाता था. इस अनुदान में शिक्षण की इमारत का किराया, महानगर पालिका का संपत्ति कर आदि जैसे खर्चों के लिए अनुदान से मिलने वाली रकम उपयोगी सिद्ध होती थी. लेकिन जब से यह अनुदान मिलना बंद हो गया है तब से उक्त खर्चों का बोझ संस्थाओं के ऊपर बढ़ गया है. यह सरासर अनुदानित स्कूलों पर सरकार द्वारा किया जा रहा अन्याय है. इससे कई संस्थाओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब तक यह समझ में नहीं आया है कि सुचारू रूप से संचालित इन स्कूलों को वेतनेतर अनुदान देना सरकार ने क्यों बंद कर दिया है? उन्होंने यह भी बताया कि नंदूरबार शिक्षा संस्था द्वारा स्कूल इमारत का भाड़ा (किराया) न भरपाने के कारण महानगर पालिका ने किराये की बकाया रकम वसूल करने के लिए नीलामी करने का आदेश निकाला है. इससे वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों व शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय होता नज़र आ रहा है.

यह भी बताया जाता है कि मराठी माध्यम के स्कूलों पर भी सामान्य दर से अधिक संपत्ति कर लगाया जाता है. इसी तरह बिजली बिल भी व्यवसायी दर से लगाया जा रहा है. इससे निजी शिक्षण संस्थाओं को सरकारी कर भारी बोझ सहन करना पड़ रहा है. मुंबई में स्थित विद्या विकास एजुकेशन सोसायटी का हाल वेतनेतर अनुदान सरकार से न मिलने के कारण खस्ता है. अनुदान न मिलने की वजह से सोसायटी ने महानगर पालिका का संपत्ति कर सहित अन्य कर चुकता नहीं किया है. संस्था पर मनपा प्रशासन ने करीब डेढ़ करोड़ रुपये का बकाया निकाला है. इसी तरह औरंगाबाद शिक्षण संस्था पर भी वहां के मनपा प्रशासन ने दस लाख रुपये का बकाया निकाला है. सरकार की इस उदासीनता के संबंध में पाटिल ने बताया कि 1995 तक सरकार की ओर से निजी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को 12 प्रतिशत के हिसाब से स्कूल इमारत के भाड़े के रूप में दिया जाता था. उसके बाद से यह अनुदान देना सरकार ने बंद कर दिया है. सरकार पर वेतनेतर अनुदान की रकम 12 साल में बढ़ते-बढ़ते 792 करोड़ रुपये हो गई है. इसके अलावा 1998 से सरकार ने नए शिक्षकेतर कर्मचारियों की भर्ती व पदोन्नति पर एक सुनियोजित नीति के तहत रोक लगा रखी है जिससे 35 हजार शिक्षकेतर कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है. जिन शिक्षण संस्थाओं में प्रयोगशाला इंचार्ज, सहायक, लाइब्रेरियन, चपरासी, लिपिक आदि सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनकी जगह भरने की अनुमति सरकार ने अब तक नहीं दी है. इससे कई स्कूलों को कर्मचारियों की कमी से भी जूझना पड़ रहा है. इसके चलते बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है क्योंकि जिन कर्मचारियों की जगह रिक्त है उनके काम भी शिक्षकों को करने पड़ते हैं. साथ ही केंद्र सरकार द्वारा देश में शिक्षा अधिकार क़ानून के अनुसार नई व्यवस्थापन समिति स्थापित करने का आदेश दिया गया है. इसके पहले भी शिक्षण संस्थाओं में व्यवस्थापन समिति कार्यरत थी. परन्तु नई समिति भी पूर्व समिति के समांतर होगी, मगर नई समिति से स्कूल संचालकों को बाहर रखा गया है.

**सरकार ने वेतनेतर अनुदान पर 12 वर्ष से लगा रखी है रोक**

**निजी शिक्षण संस्थाओं के 792 करोड़ बकाया**

**राज्य में तकरीबन 95000 प्राथमिक, माध्यमिक निजी अनुदानित स्कूल हैं. इन स्कूलों को वेतनेतर अनुदान पिछले 12 वर्षों से नहीं दिया गया है. इनकी भरपाई के रूप में इन निजी स्कूलों को बिना अनुदानित कक्षा 11वीं की फीस बढ़ाने की इजाजत देने की मांग राज्य शिक्षण संस्था महामंडल ने राज्य सरकार से की है. इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए महामंडल के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटिल की अध्यक्षता में अगस्त माह के पहले सप्ताह में बैठक हुई.**

महामंडल के पदाधिकारियों ने बताया की नई व्यवस्थापन समिति के मुद्दे पर मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ में याचिका दायर की गई है. इस पर अदालत ने सरकार के इस कानून पर रोक लगा दी है. पाटिल ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थाओं को सरकार कक्षा 11वीं शुरू करने की इजाजत तो देती है पर अनुदान नहीं देती है. साथ ही छात्रों से ली जाने वाली फीस पर भी नियंत्रण रखना चाहती है. शिक्षकों को वेतन देने के लिए आठ लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं जबकि छात्र-छात्राओं से फीस के रूप में मात्र तीन लाख रुपये संस्था को मिलते हैं. इसलिए कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों से ज्यादा फीस वसूल करने की इजाजत सरकार द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं को दिया जाना चाहिए. यदि हमारी इस मांग पर सरकार विचार नहीं करती है तो आने वाले समय में महामंडल के मार्फत जिला शाखाओं द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर पूरे राज्य में आंदोलन छेड़ा जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

# राऊत कितना खाऊत





राज्य के मंत्री व नेता किसी न किसी विवाद व घोटाले में उलझते नज़र आ रहे हैं. विवादों और घोटालों का नेताओं, मंत्रियों और अफसरों का चोली-दामन सा साथ होता है. वैसे भी आज के दौर में यदि मंत्री-संतरी-नेता का किसी विवाद या घोटाले में नाम न आए तो काहे का नेता-अफसर. इनके बिना घोटाला घट नहीं सकता और घोटालेबाज घोटाला कर नहीं सकते. भाई, समझने वाली बात है कि इनके चारों ओर चापलूसों का जमघट ही इसीलिए लगा रहता है कि मंत्री महोदय उन्हें उपकृत करेंगे. सत्ता की मलाई खाने के बाद जो मलाई की खुरचन बचेगी वह उनके हिस्से में आएगी. यही कारण है हर दिन कोई न कोई नया घोटाला उजागर होता है और उसमें हमारे किसी न किसी राजनेता-मंत्री या उनके करीबी का नाम जुड़ा रहता है. यही तो भारतीय प्रगति की निशानी है. गरीबी और करीबी मे बड़ा फर्क होता है पर दोनों में संबंध करीब का रहता है. गरीबों के नाम पर योजनाए गरीबी दूर करने या पिछड़े दलितों को न्याय दिलाने के नाम पर बनती हैं, पर फ़ायदा करीबियों को होता है. यही रहस्य भइया, गरीबों के और गरीब होते जाने का और अमीर के और अमीर होते जाने का. अब राज्य के रोज़गार गारंटी मंत्री नितिन राऊत भी ढाई सौ करोड़ के टीडीआर घोटाले के जंजाल में उलझते नजर आ रहे हैं. विधानसभा में विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से ने राऊत पर खाउत होने का आरोप लगाया है. बतौर सबूत उन्होंने सदन में एक सीडी पेश की है. सीडी में अपने माननीय मंत्री महोदय के तत्कालीन निजी सचिव की बातचीत दर्ज है. बातचीत में उक्त सचिव किसी सौदे की बात पर बार-बार मंत्रिवर राऊत का नाम ले रहा है. ऐसी विधायकों-मंत्रियों के बीच चर्चा है और यह चर्चा मीडिया में ख़बर है. बिना सरकार से अनुमति लिए बिना मंत्रिवर महोदय ने अपने प्रिय निजी सचिव को आंबेडकर नगर के प्रशासक मंडल में प्रशासक बना कर उपकृत किया था, पर यह बात विपक्ष को हजम नहीं हुई और बवाल हो गया. हालांकि राऊत के एक सहयोगी आवास राज्यमंत्री सचिन अहीर ने बचाव करने का प्रयास ज़रूर किया. परन्तु विपक्षी दल के नेता के नियम-कायदे के तर्क ने उनको चुप होने पर मजबूर कर दिया. विपक्ष के नेता ने सवाल दग़ागा कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई तत्कालीन गृह राज्यमंत्री के निजी सचिव जाकीकोरे साहब को आंबेडकर नगर प्रशासक मंडल का प्रशासक बनाने की. यदि किसी कारण नियुक्त किया जाना था तो सरकार से अनुमति क्यों नहीं ली. इसके अलावा जो सीडी सबूत के रूप में सदन में पेश की गई, उसमें जो कुछ रिकॉर्ड है, उससे यही ज़ाहिर होता है कि किसी सौदे पर विवाद हुआ है. विवाद पर बहस होने पर जाकीकोरे ने बार-बार नितिन राऊत का नाम लेकर उनके दामन को कोरा न रहने दिया. अब विपक्ष अड़ गया है कि इस पूरे मामले की सीआईडी जांच कराई जानी चाहिए. मगर पता चला है कि राऊत साहब इससे कतई चिंतित नहीं हैं. हों भी क्यों? आख़िर पहले वे गृह राज्यमंत्री रह चुके हैं. सारे अधिकारी-कर्मचारी उनके मातहत रह चुके हैं फिर घबराने वाली की कोई बात ही नहीं है. वैसे भी राऊत साहब कोई पहली बार विवादों में तो घिरे नहीं हैं. विवादों का सामना पहले भी कर चुके हैं और एक घोटाले के आरोप का भी सामना कर ही लेंगे. अव्वल तो सरकार विपक्ष की सीआईडी जांच की मांग जल्दी मानेगी नहीं और यदि मान भी गई तो जांच नौ दिन चले अढ़ाई कोस की गति से चलती रहेगी. तब तक बचा हुआ कार्यकाल निकल ही जाएगा. किन्तु राऊत साहब उपराजधानी की जनता को आप पर बहुत नाज था, पर आपके राज में ये क्या हो रहा है? आपका अपना आदमी आपके दामन को दाग़-दाग़ कर रहा है. ऐसे चमचों को उपकृत करने का भला क्या फ़ायदा? चाय से केटली ज़्यादा गरम हुई तो यही हाल होता है. आप की इस घटना से आपके सभी साथी मंत्रियों को सोचना चाहिए कि चाय से केटली कितनी गरम रखनी चाहिए. राऊत साहब सोचिए ज़रा कि यदि मामला अदालत में चला गया तो फिर आपको अपने चमचों का मोह कितना भारी पड़ेगा.



नितिन राऊत

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# ज़िला परिषद में दंगल









राजेन्द्र सिंह अहिर

लोकतांत्रिक राजनीति में विपक्ष की सत्तापक्ष की अपेक्षा अधिक सशक्त भूमिका होती है. लेकिन इसके लिए जरूरी होता है सत्ता का मोह त्याग कर जनहित में विपक्ष की भूमिका सकारात्मक हो. यदि विपक्ष सत्ता का मोह त्याग नहीं पाता है तो वह अलोकतांत्रिक कदम उठा कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि उसके सदस्य किसी न किसी तरह सत्तारूढ़ दल को बेदखल करके खुद पुनः सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए उतावले दिखाई देते हैं. महाराष्ट्र की उपराजधानी की स्थानीय निकाय संस्थाओं में कुछ ऐसा ही राजनीतिक परिदृश्य दिखाई दे रहा हैं. कहीं जनहित से जुड़े मुद्दों पर सत्तारूढ़ दल विचार-विमर्श करना चाहता है तो कहीं विपक्ष लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने की बजाय अलोकतांत्रिक तरीकों को अपना कर नकारात्मक राजनीति कर रहा है. जुलाई माह में मनपा की आमसभा में सत्तारूढ़ और विपक्ष में तनातनी के चलते जनहित के मुद्दे पीछे छूट गए. उसके बाद अगस्त के पहले ही सप्ताह में जिला परिषद की आमसभा में भी सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हुए दंगल (सदस्यों के बीच पहलवानी दांवपेंच) के कारण जनता से जुड़ी बातें कहीं खो गईं. राजनीति आरोप-प्रत्यारोप तक तो संसदीय प्रणाली में चलता है पर जब किसी संस्था के जनप्रतिनिधि मवालियों की तरह अपनी बांहें चढ़ाकर कुश्ती के दांवपेंच दिखाने लगे, एक-दूसरे के हाथ-पांव तोड़ने पर उतारू हो जाएं तो लोग चिन्तित हो उठते हैं. उनके मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उमड़ने-घुमड़ने लगता है कि आखिर उनके माननीय जनप्रतिनिधि किस लोकतंत्र का प्रदर्शन कर रहे हैं? जिला परिषद की 2 अगस्त की सभा में जो कुछ हुआ व अशोभनीय था. इसके लिए दोनों ही पक्षों के नेता जिम्मेदार थे, क्योंकि किसी ओर से संयम नहीं बरता गया. इस दंगल में एक सदस्य का हाथ टूटा, सारी शिक्षा-तहजीब को भूलकर गालियां की बौछार दोनों ओर से हुई. विपक्षी सदस्यों ने सदन से संबंधित कागजातों की होली जलाकर सारी हदें पार कर दीं. कम से कम जनप्रतिनिधियों को इतनी नैतिकता तो रखनी चाहिए कि वहां महिला सदस्य भी उपस्थित हैं.

ध्यान देने वाली विशेष बात यह है कि जिला परिषद में पूर्व सत्ता का सुख भोग चुकी और वर्तमान में विपक्ष की सीट पर अपने को सभी दलों से अलग हटकर राजनीति करने वाली पार्टी भाजपा के सदस्य बैठे थे. भाजपा के चुने गए जनप्रतिनिधियों से जनता यह अपेक्षा करती है कि उनके आचरण से संघ प्राप्त संस्कारों की झलक मिलेगी. मगर जिला परिषद में भाजपा सदस्यों के आचरण में संघ के संस्कार कहीं भी दिखाई नहीं दिए. समझ में नहीं आता है कि भाजपा को हो क्या गया है? भारतीय संस्कृति, संस्कार व रीति-रिवाजों-परंपराओं की दुहाई देने वालों को हो क्या जाता है कि भारतीय संस्कृति की मान-मर्यादाओं को भूल जाते हैं. जि.प. सभा में हंगामें के दौरान भाजपा सदस्य विनोद नितनवरे जब देवीदास कठाणे को नाश्ते की प्लेट मार रहे तब पार्टी वरिष्ठ सदस्यों ने उनको यह आचरण करने से क्यों नहीं रोका. नितनवरे को रोकने की बजाय भाजपा के वरिष्ठ सदस्य व जि.प. के पूर्व अध्यक्ष रमेश मानकर शिक्षण सभापति जिभकाटे की ओर दौड़ लगा दी. विपक्षी सदस्यों का अपनी सीटों पर खड़े होकर सत्तापक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने तक बात हजम की जा सकती है पर सभा सदन दस्तावेजों की होली जलाना समझ के परे है. हंगामें का मुख्य कारण यह था कि सत्तापक्ष की बात न विपक्ष सुनना चाहता था और न विपक्ष की बात सत्ता पक्ष. दोनों के अहंकार के आगे जनता से जुड़े मुद्दे हंगामे में खो गए. यहां तक की कि कांग्रेस के सदस्य उपासराव भुते ने जब उमरेड रोड में हुई दुर्घटना में मारे गए 12 लोगों को श्रद्धांजलि देने और उनके परिवारों के प्रति सांत्वना व्यक्त करने का प्रस्ताव रखा तो उनके इस संवेदनशील प्रस्ताव को विपक्ष ने ठुकरा कर अपनी असंवेदनशीलता का ही परिचय दिया. विपक्ष के सदस्य इस प्रस्ताव की जगह भाजपा ने समाज कल्याण सभापति शांताराम मड़ावी द्वारा रेखा मसराम को मैना कहे जाने का गैरजरूरी मुद्दा उठाया. ऐसा लगता है कि जिला परिषद की सभा में विपक्ष जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय सभा न होने देने की रणनीति बना कर आया था. इसीलिए तो जब कठाणे जलापूर्ति के मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़े हुए तो उनको प्लेट फेंककर मारी गई. हंगामे के बाद अपने-अपने को निर्दोष साबित करने की कवायद शुरू हो गई है. जिला परिषद के अध्यक्ष सुरेश भोयर व उपाध्यक्ष नितिन राठी का कहना था कि हमारे द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से विपक्ष डरा हुआ है. उसके पास कोई मुद्दा नहीं है. इसलिए हंगामा कर अपनी असफलता छिपाना चाहती है. उन्हें अपना अस्तित्प बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा. उन्होंने जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय हंगामा कर अपनी संस्कृति का परिचय दे दिया है. दूसरी ओर विपक्ष के नेता आनंदराव राउत ने अपने दल के सदस्यों का बचाव करते हुए कहा कि सभा चलाने में अध्यक्ष असफल रहे. जिले से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषय थे, जिन पर गौर करना जरूरी नहीं समझा. वहीं पूर्व अध्यक्ष रमेश मानकर ने कहा कि इस हंगामे के दौरान भाजपा के किसी सदस्य ने किसी के साथ कोई हाथापायी नहीं की. लेकिन भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि उसकी मुख्य सहयोगी शिवसेना ने उससे किनारा क्यों कर लिया? शिवसेना नेता तपेश्वर वैद्य ने कांग्रेस और भाजपा को इस हंगामे के लिए बराबर का दोषी ठहराते हुए स्पष्ट किया न अध्यक्ष को सभा चलाना आता है और न भाजपा को विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना. जिले से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों को छोड़कर भाजपा अनावश्यक मुद्दों में उलझ गई जिससे यह हंगामा हुआ. दोनों ने अपना-अपना पक्ष रखकर अपना बचाव करने का भले बाद में प्रयास कर रहे हों पर जनता को जि.प. से जो संदेश गया है वह कतई लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
दिल्ली, 22 अगस्त–28 अगस्त 2011
Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

नक्सलियों द्वारा 18 लोगों की हत्या किए जाने के बाद भी 30-40 हजार से अधिक आदिवासियों का मुखर हो कर जगह-जगह शांति रैलियों में शामिल होना यह दर्शाता है कि अवसर मिलने पर वे नक्सलियों के खिलाफ बोल सकते हैं.

# आदिवासियों की नक्सलियों को चुनौती

**नक्सली हर साल नक्सल आंदोलन के संस्थापकों में से एक चारू मजूमदार की याद में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाते हैं. इस दौरान वे अधिक से अधिक हिंसक वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं. शहीद सप्ताह के मध्य गढचिरोली जिले में प्रशासनिक गतिविधियों पर विराम-सा लग जाता है. कुछ इलाकों में सरकारी बसों का आना जाना बंद हो जाता है. नागरिकों से शहीद सप्ताह बंद के दरम्यान नक्सली निर्देशों का पालन किए जाने के पर्चे बांटे जाते हैं. अवहेलना करने पर इनका कोप को झेलना पड़ता है. यह भी बताया जाता है कि अधिकतर सरकारी कर्मचारी शहीद सप्ताह शुरू होने के पहले ही छुट्टी लेकर अपने गांव चले जाते हैं या अपने घर में ही रहना मुनासिब समझते हैं. आदिवासी समाज के लोग नक्सलियों की दहशत में रहते हैं. एक तरह से पूरे आदिवासी समाज को नक्सनियों का समर्थक मानने की आम धारणा है.**

राजेश नामदेव

नक्सलियों की सर्वहारा विचारों की आड़ में की जा रही दहशत फैलाने वाली हरकतों ने उनका चेहरा बेनकाब कर दिया है. किसी भी आदिवासी को मुखबिर बता कर मौत के घाट उतार देना. किसी आदिवासी का पुलिस के पास जाने पर नक्सलियों द्वारा उनको प्रताड़ित करना, पुलिस भर्ती के लिए गए युवकों के गांव लौटने पर उनकी हत्या कर देना, युवक-युवतियों को जबरन नक्सली दलम में शामिल करना, आदिवासी युवतियों का नक्सलियों द्वारा यौन शोषण करने जैसी घटनाओं ने आदिवासी समाज का उनके प्रति मोहभंग कर दिया है. अब वे नहीं चाहते कि उनके बेटे-बेटियां नक्सली दल में शामिल हों और उनकी राह चलें. इसलिए आदिवासियों ने नक्सलियों की मनमानी बर्दाश्त न करने का मन बनाया है. इसी की प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र के सर्वाधिक नक्सल समस्या से ग्रस्त गढ़चिरोली ज़िले में नक्सलियों द्वारा 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाये जा रहे शहीद सप्ताह का आदिवासियों ने पुरजोर विरोध किया. जगह-जगह रैली निकाल कर नक्सली हिंसा पर अपना रोष व्यक्त किया और शांति कायम रखने की अपील की. यह आदिवासियों का दबाव ही था कि शहीद सप्ताह के दरम्यान गढ़चिरोली में एक भी हिंसक वारदात नहीं हुई.

उल्लेखनीय है कि नक्सली हर साल नक्सल आंदोलन के संस्थापकों में से एक चारू मजूमदार की याद में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाते हैं. इस दौरान वे अधिक से अधिक हिंसक वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं. शहीद सप्ताह के मध्य गढ़चिरोली जिले में प्रशासनिक गतिविधियों पर विराम-सा लग जाता है. कुछ इलाकों में सरकारी बसों का आना जाना बंद हो जाता है. नागरिकों से शहीद सप्ताह बंद के दरम्यान नक्सली निर्देशों का पालन किए जाने के पर्चे बांटे जाते हैं. अवहेलना करने पर नक्सलियों के कोप को झेलना पड़ता है. यह भी बताया जाता है कि अधिकतर सरकारी कर्मचारी शहीद सप्ताह शुरू होने के पहले ही छुट्टी लेकर अपने गांव चले जाते हैं या अपने घर में ही रहना मुनासिब समझते हैं. आदिवासी समाज के लोग नक्सलियों की दहशत में रहते हैं. एक तरह से पूरे आदिवासी समाज को नक्सलियों का समर्थक माने जाने की आम धारणा है. दूसरी ओर पुलिस द्वारा नक्सलियों के शहीद सप्ताह का विरोध करने का आह्वान आदिवासियों से किया जाता है. मगर आदिवासी अब तक नक्सलियों के खिलाफ चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते थे. किन्तु अब आदिवासी समाज में बदलाव आ रहा है. वे नक्सलियों की मनमानी से तंग आ गए हैं. इसी कारण से अब और उनके जुल्मों को अब बर्दाश्त न करने का निर्णय लिया है.

इस वर्ष जब पुलिस प्रशासन ने आदिवासियों से शहीद सप्ताह का विरोध करने और शांति रैली निकालने का आह्वान किया तो आदिवासी समाज में आ रहा बदलाव साफ देखने को मिला. शहरी क्षेत्रों के साथ ही नक्सलियों का गढ़ कहलाने वाले दुर्गम क्षेत्रों में भी नक्सलियों ने शांति रैली में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और नगर-गांव में घूम-घूम कर नक्सली हिंसा रोकने की मांग की. शांति-अमन के साथ रहकर विकास का पुरजोर विरोध किया. बताया जाता है कि पिछले वर्षों में शहीद सप्ताह के दौरान तालुका स्तर पर शांति रैली निकाली जाती थी, पर इस बार गढ़चिरोली शहर के साथ ही नारगुंडा, भामरागढ़, कोठी, ग्यारापत्ती, राजाराम खांदला, देचलीपेठा, लाहेरी, धोडराज, कोसापल्ली, दामरंचा जैसे सबसे अधिक नक्सली प्रभावित दुर्गम क्षेत्र में स्थित गांवों में भी शांति रैली निकाल कर नक्सलियों के विरुद्ध आवाज उठाई. विशेष बात यह रही कि इन रैलियों मे आदिवासी समाज के लोगों ने बिना किसी दबाव के भाग लिया. नेलगोंडा में पुलिस थाना न होने के बावजूद वहां शांति रैली निकाल कर नक्सलियों को आदिवासियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब हम हिंसा नहीं चाहते हैं. इसी तरह प्राणहिता नदी के तट पर स्थित गांव देचलीपेठा में दो से ढाई हजार आदिवासियों ने शांति रैली में शामिल हुए. एटापल्ली में निकली शांति रैली मे आस-पास के करीब 24-25 गांव के तीन-चार आदिवासियों ने हिस्सा लिया. यहां पर आदिवासी समाज की शांति रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर नगर प्रशासन ने तुरत-फुरत स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन कर डाला. इसी तरह का नजारा कामासूर, मुखनपल्ली, तोडगांव सहित अन्य गांवों में देखा गया.

आमतौर पर यह धारणा है कि नक्सलियों के विरुद्ध आदिवासी कभी कुछ नहीं बोलते है. चुप रहकर उनका समर्थन ही करते हैं. परन्तु अब तस्वीर बदल रही है. विछले दो माह में नक्सलियों द्वारा 18 लोगों की हत्या किए जाने के बाद भी 30-40 हजार से अधिक आदिवासियों का मुखर हो कर जगह-जगह शांति रैलियों में शामिल होना यह दर्शाता है कि अवसर मिलने पर वे नक्सलियों के खिलाफ बोल सकते हैं. उनकी हिंसा का विरोध कर सकते हैं. ऐसा पहली बार हुआ है कि कोठी, नारगुंडा, भामरागढ़, देचलीपेठा, नेलगोंडा जैसे दुर्गम इलाकों में आदिवासियों ने पुलिस के आह्वान पर शांति रैली में भाग लिया है, जबकि इन गांवों को सर्वाधिक नक्सली प्रभावित गांव माना जाता है. यह पुलिस के लिए शुभ संकेत है कि जिन आदिवासियों को पुलिस कर्मी नक्सलियों का समर्थक मानने की धारणा बना रखी थी वे अब उनका साथ दे रहे हैं. अपनी जान की परवाह न कर नक्सलियों के विरोध में सामने आ रहे हैं, इससे नक्सली गतिविधियों में अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी. इससे पुलिस जवानों का बल बढ़ेगा.

आदिवासी समाज में आ रहे इस परिवर्तन की वजह क्या है? इस सवाल को जब भामरागढ़ और एटापल्ली के शिक्षकों से पूछा गया तो उन्होंने जो कारण बताए, वे सरकार और पुलिस प्रशासन की आंख खोलने वाले हैं. इन शिक्षकों ने बताया कि पिछले दिनों एटापल्ली-भामरागढ़ सहित आस-पास के 20-25 युवक पुलिस भर्ती के लिए गए थे. उनकी पुलिस में भर्ती तो नहीं हो सकी, पर जब वे लौट कर आए तो उनको नक्सलियों की धमकियां मिलने लगी. दो गांव लौटे युवकों की नक्सलियों ने हत्या कर दी. बाकी युवक नक्सलियों के भय से गांव नहीं लौट रहे हैं, बल्कि गढ़चिरोली में रह कर डेढ़-दो हजार की नौकरी कर गुजारा कर रहे हैं. इन घटनाओं से आदिवासियों के मन में नक्सलियों के विरुद्ध बगावत करने की भावना भर दी है. अब यह सरकार और प्रशासन का काम है कि वह इस अवसर का लाभ उठाये या गंवाए. यदि इस क्षेत्र के आदिवासी युवकों को सरकार काम देती है तो कौन-सा युवक नक्सली बनना चाहेगा? सभी रोजगार पाना चाहते हैं और शांति से रहना चाहते हैं. यही वह वजह है कि आज जान की परवाह न कर आदिवासी नक्सलियों को चुनौती देने लगा है.

feedback@chauthiduniya.com

## नेता रहे नदारद

**शहीद सप्ताह के विरोध में निकाली गई शांति रैलियों में एक खास बात यह नजर आई कि इनमें किसी भी राजनीतिक दल का नेता नजर नहीं आाया. इससे यह बात साफ हो गई कि जुबानी जमा खर्च करके नक्सल समस्या का विरोध करने वाले नेताओं का रवैया जमीनी स्तर पर क्या है? शायद उन्हें अपने प्राणों का मोह रहा हो या चुनाव के समय लाल सलाम वालों के समर्थन की जरूरत ने उनको रोक लिया हो. वजह कुछ भी हो पर इतना तो तय है कि इनकी नजर में अपनी जान व स्वार्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है.**

## पलटवार करने की आशंका

**आदिवासियों द्वारा बड़ी संख्या में शांति रैलियों में भाग लेना नक्सलियों को रास नहीं आ रहा है. इसके मद्देनजर यह आशंका बढ़ गई है कि नक्सली अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पलटवार कर सकते हैं. वे किसी भी हालत में नहीं चाहते कि महाराष्ट्र का आदिवासी समाज किसी भी सूरत में उनके खिलाफ खड़ा हो. इसलिए नक्सली पुनः हिंसक वारदातें कर क्षेत्र में दहशत का माहौल बना सकते हैं. पुलिस प्रशासन इसके प्रति चौकन्ना जरूर है पर नक्सलियों की गतिविधियों पर वह अंकुश लगाने में कितना सक्षम है, इस बात को लेकर लोगों के मन में आशंका बनी हुई है. इस संबंध में गड़चिरोली के पुलिस अधिक्षक विरेश प्रभु का कहना है कि इस बार नक्सलियों के दमनचक्र से बाहर निकलते हुए आदिवासियों ने हमारे विभाग द्वारा आयोजित शांति रैलियों व जनजागरण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है. इससे पुलिस के हौसले में इजाफा हुआ है. जहां तक नक्सलियों के पलटवार करने आशंका की बात है तो यहां तैनात सभी बल सतर्क हैं. हम सतत नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं.**

## नक्सली आदिवासियों से डरते हैं : सुरेश द्वादशीवार

सुरेश द्वादशीवार

**नक्सली समस्याग्रस्त क्षेत्र में सबसे पहले शांति यात्रा निकाल कर आदिवासियों को जागरूक करने का प्रयास करने वाले वरिष्ठ पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश द्वादशीवार का कहना है कि नक्सलियों को सरकार और पुलिस से डर नहीं लगता है. वे सबसे अधिक डरते हैं आदिवासियों से. उनका असली डर आदिवासियों के बच्चों से है क्योंकि आज वे पढ़-लिख कर डॉक्टर-इंजीनियर बन रहे हैं. यही बच्चे आगे चलकर अपने समाज का नेतृत्व करेंगे. अब तक गड़चिरोली में नक्सलियों ने 800 से अधिक आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया है. वे नहीं चाहते कि आदिवासियों के बच्चे स्कूल जाएं. उनमें जागरुकता आए. इसलिए वे आदिवासी बच्चों के स्कूल सर्टीफिकेट जला देते हैं. किसी सरकारी नौकरी पर गए युवकों के वापस आने पर मार देते हैं. वे नहीं चाहते कि आदिवासी युवक सरकारी नौकरी में जाएं. नक्सलियों को डर है कि उनके हाथ से नेतृत्व छिन जाएगा और आदिवासियों से मिल रहा समर्थन बंद हो जाएगा. हमने जब शांति यात्रा निकाली थी तो उस समय आदिवासियों ने हमारा नाच-गा कर स्वागत किया था. इसके पहले किसी ने आदिवासियों का सही तरीके से हौसला नहीं बढ़ाया पर अब स्थितियां धीरे-धीरे बदल रही हैं. उनमें जागरुकता आ रही है जिसका नतीजा है आज वह मौत का डर त्याग कर शांति रैलियों में भाग ले रहे हैं.**

# चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 22 अगस्त–28 अगस्त 2011

www.chauthiduniya.com

Website : sanjeevanibuildcon.in

"संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI STATION
BIT Pithoria, Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9661337777 / 9472722024

9472727767 / 9162779209


# बिना काम का दरबार

बिहार शरीफ का वेद प्रकाश 11 अप्रैल 2011 को को जनता दरबार में आया था, नीतीश जी उससे बड़े प्यार से मिले और उसकी समस्या के समाधान के लिए डीएम साहब को निर्देशित किया. वेद प्रकाश जब अपने ज़िले के डीएम से मिला तो उसे कड़ी फटकार लगाते हुए कहा गया कि क्या ज़रूरत थी जनता दरबार में जाने की. जनता दरबार की हक़ीक़त यह है कि अब उसे पागल घोषित कर रविवार व सोमवार को घर में बंद रखा जाता है.

फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

सरोज सिंह

मुख्यमंत्री का जनता दरबार यानी कि ऐसी अदालत जिसमें हर जगह से थका हारा इंसान सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ख़ुद रूबरू होकर अपनी फ़रियाद उन्हें सुनाकर न्याय की गुहार लगाता है. हर सोमवार को लगने वाला यह दरबार बिहारवासियों के लिए उम्मीद का एक ऐसा कोना है जहां सूबे के दूर दराज से आए लाचार व परेशान लोगों का मेला लगता है. मुख्यमंत्री ख़ुद आवेदन लेकर समस्या सुनते हैं और दरबार में ही संबंधित विभाग के बैठे मंत्रियों व सचिवों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज देते हैं. मतलब पूरी सरकार ही बैठती है समस्याओं के निदान के लिए ताकि इस दरबार से कोई निराश न जाए. लेकिन जनता दरबार में आए मामलों के निष्पादन के आंकड़े बताते हैं कि कैसे एक सुस्त प्रशासनिक तंत्र जनता के हित की एक सुंदर परिकल्पना को ज़िंदा दफ़न कर रहा है. ज़िलों में जनता दरबार से गए मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. जनता दरबार में पहुंचे फ़रियादियों को ज़िले के अधिकारी दुश्मन की नज़र से देख रहे हैं. कई लोगों पर फ़र्ज़ी मुकदमा दायर कर जेल भी भेजा गया है. बिहार शरीफ के वेद प्रकाश को तो पागल बताकर रविवार व सोमवार को घर में बंद रखने का फरमान सुना दिया गया ताकि वह सोमवार को मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में दोबारा शिकायत करने न जा सके. ऐसे किस्से यह बतलाते हैं कि आम इंसान को राहत देने के लिए लगाए जाने वाले इस सबसे बड़े दरबार से हताश व निराश लौट रहे लोगों के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है.

जनता दरबार शुरू करने के पीछे मक़सद यही था कि मुख्यमंत्री ख़ुद लोगों का दर्द महसूस कर सकें. अगर पूरी ईमानदारी के साथ इस परिकल्पना पर काम होता तो शायद आज तस्वीर बिल्कुल अलग होती. लेकिन चौथी दुनिया के पास उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों में मिली जानकारी यही बताती है कि इस पूरी परिकल्पना को चौपट करके रख दिया गया है. आंकड़ें हताश व हैरान करने वाले हैं. लगभग पांच सालों में जनता दरबार में दो लाख चालीस हजार सात सौ इक्कतीस लोगों ने आवेदन दिया. 20 अप्रैल 2006 से 31 दिसंबर 2006 तक 29,672 लोगों ने आवेदन दिया. इसी तरह अगले साल यानी 2007 में 14,646, साल 2008 में 27,873, साल 2009 में 45784 तथा साल 2010 में 67,897 लोगों ने जनता दरबार में आवेदन दिया. पहली जनवरी 2011 से 23 मई 2011तक 54,859 लोग जनता दरबार में आवेदन कर चुके हैं. दस्तावेज में दर्ज आंकड़ें बताते हैं कि 20 अप्रैल 2006 से लेकर 31 दिसंबर 2008 तक के निष्पादित मामलों के बारे में सरकार के पास वर्तमान में सूचना उपलब्ध नहीं है. साल 2009 में 45,784 आवेदन आए, जिसमें मात्र 7195 आवेदनों को ही निष्पादित किया जा सका. इसी तरह 2010 में 67897 आवेदनों में से केवल 7642 आवेदनों का ही निपटारा किया जा सका. साल 2011 के 23 मई तक 54859 आवेदनों में से केवल 1121 आवेदनों का ही निपटारा किया जा सका है. इन आंकड़ों से सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह जनता के सपनों व उम्मीदों के साथ जनता दरबार में खिलवाड़ किया जा रहा है.

नवादा ज़िले के सिरदला के निवासी शंभू लाल की ग़लती बस इतनी थी कि उसने नवादा के आला अधिकारियों के ख़िलाफ़ मुख्यमंत्री से शिकायत दर्ज कराई थी. इस काम का दंड यह मिला कि उसे बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया और 31 महीने तक जेल में रहना पड़ा. 21 अप्रैल 2011 को नवादा की अदालत ने शंभू लाल को बेकसूर घोषित कर दिया. इसी तरह आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय को भी बिना वजह 29 दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी थी. इन पर 2008 में ज़िलाधिकारी ने रंगदारी मांगने का झूठा केस कर दिया था. लगभग इसी तरह का व्यवहार हर ज़िले में हो रहा है. बिहार शरीफ के वेद प्रकाश को तो पागल तक घोषित कर दिया गया. 11 अप्रैल 2011 को वेद प्रकाश जनता दरबार में आया था. इसका रजिस्टेशन नंबर 1104117041 था. नीतीश जी इससे बड़े प्यार से मिले और उसका हौसला बढ़ाया. उसकी समस्या के समाधान के लिए डीएम साहब को निर्देशित किया गया. वेद प्रकाश जब अपने ज़िले के डीएम से मिला तो उसे कड़ी फटकार लगाते हुए कहा गया कि क्या ज़रूरत थी जनता दरबार में जाने की. उसकी पिटाई भी की गई. उसके घर वालों को कहा गया कि वेद प्रकाश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए इसे रविवार व सोमवार को घर में बंद रखा जाए. लेकिन 8 अगस्त 2011 को वह एक बार फिर जनता दरबार में आया. उसने बताया कि वह शनिवार को ही घर से निकल गया. साहस करके वह जनता दरबार में चला तो आया पर उसे यह डर सता रहा है कि पता नहीं वापस बिहार शरीफ लौटने पर क्या होगा. वेद प्रकाश कहता है कि वह पागल नहीं है. पटना के डॉक्टरों ने कहा है कि बस उसे कमज़ोरी है. इसी तरह आठ अगस्त को जनता दरबार में आए बेगूसराय के सुखदेव शर्मा– रजिस्ट्रेशन नंबर 0808113005 तो इतना हताश था कि उसने आत्मदाह तक की धमकी दे डाली. उसने बताया कि डीएम के यहां कई बार फ़रियाद कर चुका हूं पर कुछ नहीं हुआ. यहां से भी निराश लौट रहा हूं. किसी तरह दो हज़ार इंतजाम कर एम्बुलेंस से पटना आया पर सब बेकार गया. ज़िले में अफसरों से कहा कि कम से कम एक जनवितरण की दुकान आवंटित कर दीजिए पर मेरी बात नहीं सुनी गई. इसी तरह अंजनी कुमार मगध प्रमंडल में महिला पर्यवेक्षकों के एसीपी लाभ के मामले में कोई भी कार्रवाई न होने पर दुखी नज़र आए. उन्होंने कहा कि आयुक्त कुछ सुनते नहीं इसलिए इस दरबार में फरियाद करने आया हूं. छपरा के रणविजय सिंह ज़िले में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर कई बार इस दरबार का चक्कर लगा चुके हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. वैशाली ज़िले के शिक्षा मित्र विजय तो 18 बार जनता दरबार में आ चुके हैं. इनका दुख यह है कि तीन साल नियुक्ति को पर वेतन नहीं मिल रहा है. 36 बार वह डीएम और 330 बार बीडीओ के यहां आवेदन दे चुके हैं.

ये कुछ उदाहरण बताते हैं कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम काम किस तरीके से कर रहा है. जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार कहते हैं कि आंकड़ों में मत जाइए. सरकार पूरी संजीदगी के साथ समस्याओं के निपटारे में लगी है. बड़ी मुश्किल है, आंकड़ों में अगर नहीं देखें तो फिर सच और झूठ का क्या पैमाना होगा. भावना यही है कि जनता दरबार से लोगों को सही मायनों में राहत मिले वरना फिर यह बिना काम का दरबार बनकर रह जाएगा.


feedback@chauthiduniya.com


## नेताजी कहिन

डॉ. अनिल सुलभ

यह दरबार जनता के साथ छलावा है. लोग दूर-दूर से यहां आते हैं पर खाली हाथ लौट रहे हैं. यह नीतीश कुमार का राजनीतिक नाटक है, इसे तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए.

नीतीश कुमार को यह ग़लतफहमी है कि जनता दरबार से उनकी इमेज दुनिया भर में बन रही है, पर हक़ीक़त यह है कि इस दरबार से निराश लौटने वाले हर शख्स के दिल में उनकी बदरंग तस्वीर बन रही है.

प्रेमकुमार मणि

शिव प्रकाश राय

लोग क़र्ज़ लेकर किसी तरह जनता दरबार में जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि न्याय मिलेगा पर उन्हें निराशा हाथ लग रही है. ज़िले के अफसर तो और भी मनमानी कर रहे हैं.

जनता दरबार बिहार के भोले-भाले लोगों की भावनाओं के साथ बस खिलवाड़ है. लाचार व परेशान लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है.

राघवेंद्र कुशवाहा

नीरज कुमार

जनता दरबार की सफलता को निष्पादित होने वाले मामलों के आंकड़ों में खोजना ग़लत होगा. दरअसल, वहां जो मामले आते हैं, उनके अनेक आयाम हैं. कुछ कोर्ट से जुड़े होते हैं तो कुछ छंटनी आदि के होते हैं.

जीपीओ के बीडी आईएस अधिकारी अनिल कुमार से जब यूआईडी कार्ड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूआईडी कार्ड व्यक्ति विशेष की अपनी पहचान होगी.





रेलवे की उदासीनता के कारण अनाज सड़ता है. अनाज को सुरक्षित रखने के लिए न तो शेड बना है और न ही रैक प्वाइंट की चाहरदीवारी की गई है.




## यू.आई.डी. कार्ड
# यह कार्ड सिर्फ़ छलावा है

[illegible]



अनिल कुमार

भारत में लगभग तीन करोड़ कार्ड बन चुके हैं. इन तीन करोड़ कार्ड में कुछ कार्ड ग़लत भी हो सकते हैं. इसके अलावा में बिजली के अभाव में कार्ड का प्रयोग मुश्किल है.

देवेंद्र दुबे
feedback@chauthiduniya.com



# रामाश्रय की ताजपोशी से राजद में अंतर्कलह

**युवा राजद के प्रदेश महासचिव फ़ैज़ुर्रहमान फैज़ ज़िलाध्यक्ष पद पर सहनी की पुर्नवापसी पर असंतोष जताते हुए अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देते हुए पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद को संबोधित पत्र में उल्लेख किया है कि दल विरोधी व्यक्तियों ने आपको दिग्भ्रमित करते हुए अपना हित साधा है, जिस कारण आपकी और दल की छवि धूमिल हुई है और ऐसे लोगों को प्राथमिकता देने से पार्टी के आम कार्यकर्ता बहुत आहत हुए हैं. ऐसे व्यक्ति को ज़िले की कमान सौंपना कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान के साथ खिलवाड़ है.**



विकास कुमार

समस्तीपुर ज़िले में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अंतर्कलह से जूझ रही है, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नज़रअंदाज़ करते हुए इसे गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं. ज़िलाध्यक्ष पद पर फिर से रामाश्रय सहनी के क़ाबिज़ हो जाने से कार्यकर्ता अचंभित हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रामाश्रय सहनी की कार्यप्रणाली संदेहास्पद रही थी. सहनी को लेकर उपजे विवाद में राजद से कई कद्दावर लोग इधर से उधर हो गये और ज़िले में राजद के आठ विधायकों की संख्या घटकर मात्र दो रह गई. हुआ यह था कि विधानसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो ने टिकट वितरण में रामाश्रय सहनी और गजेंद्र सिंह की खूब सुनी थी. सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में राजद ने अपने सिटिंग एमएलए रामचंद्र निषाद का टिकट काटकर पूर्व जिलाध्यक्ष रामाश्रय सहनी को जदयू के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष एवं मौजूदा सरकार में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के ख़िलाफ़ चुनाव में उतारा था, लेकिन लालू प्रसाद का यह निर्णय बाद में ग़लत साबित हुआ.

संगठन के दृष्टिकोण से ज़िले में राजद अभी भी अव्वल स्थान पर है. पार्टी में जमीन से जुड़े नेताओं की कमी नहीं है लेकिन हाल के दिनों में पार्टी सुप्रीमो द्वारा रामाश्रय सहनी को फिर से पार्टी की बागडोर सौंप दिये जाने से पार्टी में गहरा असंतोष है, पर अचंभित नेता कार्यकर्ता कुछ बोलेने से बेहतर चुप रहना समझ रहे हैं. पार्टी की जिला इकाई में यह चर्चा ज़ोरों पर है कि जनता अब जागरूक हो चली है. लोग नेता के चरित्र को सबसे पहले देखते है. 15वीं विधानसभा एवं पंचायत चुनाव के परिणाम भी बताते हैं कि आपराधिक छवि के नेता को लोग नकार रहे हैं. ऐसे में सहनी के बेटे के आपराधिक कारनामे से पार्टी की छवि धूमिल हुई है और ऐसे व्यक्ति को ज़िला की कमान सौंपने से पहले लालू जी को सौ बार सोच विचार कर लेना चाहिए था.

युवा राजद के प्रदेश महासचिव फैर्जुरहमान फैज जिलाध्यक्ष पद पर सहनी की पुर्नवापसी पर असंतोष जताते हुए अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देते हुए पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद को संबोधित पत्र में उल्लेख किया है कि दल विरोधी व्यक्तियों ने आपको दिग्भ्रमित करते हुए अपना हित साधा है, जिस कारण आपकी और दल की छवि धूमिल हुई है और ऐसे लोगों को प्राथमिकता देने से पार्टी के आम कार्यकर्ता बहुत आहत हुए हैं. ऐसे व्यक्ति को जिले की कमान सौंपना कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान के साथ खिलवाड़ है. आपके द्वारा कार्यकर्ताओं की अनदेखी दलहित में नहीं है. वहीं जिले के एक पूर्व विधायक बताते हैं कि पार्टी एक विशाल पेड़ की तरह होती है. कार्यकर्ता इस पेड़ की जड़ होते हैं और नेता इस पेड़ पर ठहरे हुए पक्षी की तरह होते हैं. पार्टी सुप्रीमो को पक्षियों की खूब चिंता है, लेकिन जड़ की कोई चिंता नहीं है. यही कारण है कि हमारी पार्टी गरीब-गुरूबो, शोषित-पीड़ित, अकलियतों की आवाज़ होने के बाद भी सत्ता से बेदखल हो गई और आज हाशिये पर है. पार्टी की इस स्थिति के लिए कुछ अवसरवादी नेता ज़िम्मेदार हैं, जिनके खिलाफ लालू जी की चुप्पी को कार्यकर्ता पचा नहीं पा रहे हैं. वहीं ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का मनाना है कि अभी संगठन को नये सिरे से सजाये-संवारे जाने की ज़रूरत है, ऐसे में किसी नए चेहरे को ज़िलाध्यक्ष की ज़िम्मेदारी सौंपने की आवश्यकता है, जिससे पार्टी में व्याप्त खेमेबाजी समाप्त हो सके. कुछ पुराने कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस ज़िले में पार्टी का एमवाय समीकरण काफ़ी मज़बूत है, जिसे देखते हुए जिलाध्यक्ष का मनोनयन होना चाहिये. इस मानसिकता के नेता कार्यकर्ता कहते हैं कि खुर्शीद आलम नसीम शाद को हटाकर रामाश्रय सहनी को जिलाध्यक्ष बनाने से बेहतर फैर्जुरहमान फैज, सुनील कुमार पुष्पम, अजय कुमार बुल्गानिन, हरिश्चंद्र पोद्दार या विधान पार्षद रोमा भारती में से किसी एक को ज़िलाध्यक्ष बनाना पार्टी के लिए ज़्यादा बेहतर होता. ऐसा न होना दर्शाता है कि लालू जी अभी भी ग़लत सलाहकारों से घिरे हुए हैं.



सुनील कुमार पुष्पम



रोमा भारती



रामाश्रय सहनी



गजेंद्र सिंह

feedback@chauthiduniya.com

# बैंकों को करोड़ों की चपत



राजेश सिन्हा

ज़मीन की फ़र्ज़ी रसीद, केवाला और फर्जी एलपीसी(भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र) के नाम पर विभिन्न बैंकों को ऋण के नाम पर करोड़ों का चूना लगाया गया. खगड़िया ही नहीं अन्य ज़िलों में भी इस तरह की लूट का खेल खेला गया है, लेकिन फ़िलवक़्त खगड़िया ज़िले में हुए फ़र्ज़ीवाड़ा का मामला खुलकर सामने आ गया है. अभी तक चालीस फ़र्ज़ी एलपीसी पकड़े जाने के बाद भी हालात यह है कि ऋणधारकों से ऋण की अदायगी के लिए जब इनसे सम्पर्क करने की कोशिश की जाती है तो ज्ञात होता है कि अमुक नाम का कोई व्यक्ति इस इलाके में है ही नहीं. बिहार के खगड़िया जिला सहित अन्य जिलों में भी बहुत बड़े संगठित गिरोह के द्वारा ज़मीन की फ़र्ज़ी रसीद, केवाला और फ़र्ज़ी एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र) के आधार पर विभिन्न बैंकों को करोड़ों रुपये की चपत लगाई गई है. ऋण वितरण के दौरान संबंधित बैंक के पदाधिकारियों द्वारा लक्ष्मीनारायण के कारण आंख बंद कर ली गई थीं, लेकिन अब जब ऋण वसूली के लिए ऋणधारकों का अता-पता नहीं मिल पा रहा है तो वैसे पदाधिकारी सकते में आ जाते हैं. जमीन किसी और के नाम से जबकि मालगुजारी रसीद किसी और के नाम से जमा कर विभिन्न बैंकों से केसीसी लोन सहित अन्य तरह के लोन तथाकथित लाभुकों के द्वारा उठा लिए गए हैं. अब हालात यह है कि ऋण वसूली के क्रम में जब संबंधित बैंक के फील्ड ऑफिसर या अन्य पदाधिकारी ऋणधारकों के घर पहुंचते हैं तो यह ज्ञात होता है कि इस नाम का कोई शख्स इस इलाके में है ही नहीं. बिहार के अन्य जिलों में भी इस तरह की लूट का खेल खेला गया है. अन्य ज़िलों के मामले अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं लेकिन खगड़िया जिला का मामला खुलकर सामने आ गया है. इस तरह बार-बार मिल रही शिकायत के आधार पर चौथी दुनिया के द्वारा जब मामले की गहन तफ्तीश की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य इभरकर सामने आए.

गैर सरकारी आंकड़ों पर अगर भरोसा करें तो खगड़िया जिले के ही विभिन्न बैंकों को तीन करोड़ बाईस लाख रूपये की चपत फर्जीवाड़ा करने वालों ने लगाई है. हालांकि विभिन्न बैंकों के पदाधिकारियों के द्वारा यह दबे जुबान में कहा जा रहा है कि फर्जीवाड़ा करने वालों ने इस तरह का कुकृत्य करने का मन बनाया था लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी. जबकि फ़र्ज़ी लोन दिलाने के मामले में अपने आपको काफी दक्ष कहने वाले एक युवक ने स्पष्ट तौर पर बताया कि विभिन्न बैंकों के ऋण वितरण बही की जांच गहन तरीके से अगर की जाय तो कई सफेदपोशों के साथ-साथ बैंककर्मियों पर गाज गिरनी तय है. राजदार के मुताबिक वैसे तो लगभग सभी बैंकों से फर्जी जमीन की रसीद, केवाला और फर्जी एलपीसी(भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र) के आधार पर केसीसी लोन सहित अन्य तरह के लोन आवंटित किए गए हैं लेकिन इस मामले में सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया काफी आगे निकल चुका है. किसान गोल्ड योजना के नाम पर तथाकथित किसानों के द्वारा दलालों के माध्यम से करोड़ों की चपत इस बैंक को लगाई जा चुकी है. फर्जी केवाला और एलपीसी के नाम पर बैंक को करोड़ों का चूना लगाने के बाद जब दलालों के द्वारा एक बार फिर बैंक को चूना लगाने की नीति निर्धारित की गई तो इस बार दलालों का मंसूबा धरा-धरा का रह गया. इस दौरान लगभग चालीस ऋण आवेदकों के केवाला और एलपीसी फर्जी पाए गए. इतना ही नहीं सीओ, सीआई और हल्का कर्मचारी के हस्ताक्षर और मोहर भी फर्जी पाए गए. तत्काल कार्रवाई करते हुए सीओ अशोक कुमार सिंह ने सर्वप्रथम ऋण आवेदकों को ही दोषी मानते हुए यह जानने का प्रयास किया कि आखिर सीओ, सीआई और हल्का कर्मचारी के हूबहू हस्ताक्षर और मोहर कौन बना रहा है. कई माह तक जब इस मामले को पूरी तरह खंगालना संभव नहीं हो सका तब इस मामले को एक बार फिर दफन कर दिया गया. फर्जीवाड़ा करने वालों की पहचान कर कब तक कार्रवाई की जाएगी और कब तक फ़र्ज़ी काग़ज़ात के आधार पर लोग फर्जी ऋण पाते रहेंगे, यह तो संबंधित पदाधिकारी ही जानें, लेकिन इतना तय है कि जब तक सीओ, सीआई और हल्का कर्मचारी की मिलीभगत नहीं होगी तब तक किसी के लिए भी किसी बैंक से फर्जी ऋण पाना आसान नहीं होगा. वैसे चालीस से अधिक फर्जी एलपीसी पकड़े जाने के बाद अंचल प्रशासन द्वारा अर्जीदाता को ही दोषी मानकर कार्रवाई की जा रही है. अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि सभी अर्जीदाताओं से इस बात की जानकारी ली जा रही है कि आखिर फर्जी एलपीसी और लगान रसीद किसके द्वारा ऋणआवेदाकों को उपलब्ध करायी जा रही है. सीओ के अनुसार अभी तक चालीस फर्जी लगान रसीद पाई गई हैं. हल्का कर्मचारी के हस्ताक्षर और रसीद भी फर्जी पाई गई हैं. अशोक के मुताबिक़ इस तरह की लूट के खेल में संलिप्त मास्टर माइंड तक पहुंचने के लिए कई तरह के जाल बिछाए गए हैं. कुछ संलिप्त लोगो के नाम सामने आए हैं. दूसरी तरफ खगड़िया प्रखंड अंतर्गत बरैय बंगराहा निवासी अवध पासवान पुत्र- विशो पासवान(लगान रसीद संख्या-535432) के संदर्भ में हल्का कर्मचारी गोपाल मिश्र ने यह स्पष्ट लिखा कि पंजी-2 से मिलान करने पर यह पाया गया कि भूस्वामित्य प्रमाण पत्र नकली है. लेकिन वह यह देखकर चौंक पड़े कि उक्त एलपीसी पर इनका ही हस्ताक्षर है. इसी तरह मंजू देवी पति शत्रुघ्न पासवान(लगान रसीद संख्या 75639), बन्नी के रामस्वरूप सिंह पिता सोगारथ सिंह(लगान रसीद संख्या645217) रहुआ के रामलगन महतो(लगान रसीद संख्या553876), रामसूजान सिंह(लगान रसीद संख्या538484), बभनगामा के अमलेश पासवानलगान रसीद संख्या 636225) सहित अन्य के एलपीसी फर्जी पाए गए. अंचलाधिकारी अशोक के मुताबिक इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. आरंभिक तौर पर अर्जी दाताओं को ही दोषी माना जा रहा है, लेकिन इस तरह के मामले में सफेदपोशों की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है. जानकार के मुताबिक गंगौर ओपी क्षेत्र अंतर्गत रहुआ गांव की स्वीटी देवी पति विभूति भूषण महतो(लगान रसीद संख्या 646810) भी फ़र्ज़ी पाया गया. इसके पूर्व भदास गांव की सुलेखा देवी पति अनिल साह (लगान रसीद संख्या 13830) को मुफसिल थाना पुलिस को जांच के बावत इसलिए भेजा गया क्योंकि अंचल प्रशासन के अनुसार किसी भी लगान रसीद का नम्बर पांच अंक का हो ही नहीं सकता. जानकारों का यहां तक दावा है कि अगर सभी हल्का कर्मचारी के विभिन्न कागजातों की जांच की जाए तो यह स्पष्ट हो जायगा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत हल्का कर्मचारी फर्जीवाड़ा करने वालों के शार्गिद बनकर जाली लगान रसीद उपलब्ध कराकर न केवल सरकार को चूना लगाने में व्यस्त हैं बल्कि भूमि विवाद की पृष्ठभूमि भी तैयार की जा रही है. उधर, अनुमंडल पदाधिकारी सुभाष चंद्र मंडल का कहना है कि पहले इस तरह की शिकायत नहीं मिली थी. अब जबकि इस तरह का मामला सामने आया है तो निश्चित तौर पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायगी और दोषियों को हर हालत में जेल भेजा जायगा. लेकिन इतना तय है कि गोरखधंधा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो इस तरह की धोखाधड़ी चलती ही रहेगी.

**खगड़िया**








feedback@chauthiduniya.com

# गुलाबबाग में बस कीचड़ ही कीचड़



नीरज कुमार सिंह

कहा जाता है सुशासन में विकास की चमक हर तरफ दिख रही है लेकिन पूर्णिया के गुलाबबाग कृषि उत्पादन बाज़ार समिति प्रांगण की नारकीय हालत सुशासन में विकास का दंभ भरने वाली सरकार के हर दावे को झुठला रही है. आज जहां प्रांगण की सभी सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, वहीं मरम्मत एवं रख-रखाव के अभाव में सारे भवन जीर्ण-शीर्ण होकर छत से बारिश की बूंदे टपका रहे हैं. मालूम हो कि सन 1975 में कृषि उत्पादन बाज़ार समिति गुलाबबाग की स्थापना हुई थी. स्थापनकाल से ही बाज़ार समिति गुलाबबाग उत्तर बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध मंडी के रूप में उभरकर सामने आयी. इसकी व्यापारिक प्रसिद्धि और सम्पर्क सुदूर केरल से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक फैली. विदित हो कि करोड़ों के राजस्व देने में गुलाबबाग मंडी अब्बल रही है. लेकिन वर्तमान सुशासन के सरकार द्वारा जब से किसानों के हित में बाजार समिति को भंग किया गया तभी से ही रख-रखाव के अभाव में सड़क तो क्या भवन भी जर्जर होने लगे और आवारा पशुओं के साथ सुअरों को बसेरा भी प्रांगण बन गया. वर्तमान में बाजार समिति की सारी सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं. सड़कों पर इतने बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं कि इसमें भैंसें भी डुबकी लगाती हैं. कूड़ा-कचरा एवं मल-मूत्र के कारण प्रांगण सूअरों का रैन बसेरा बन गया है, जिससे यत्र-तत्र सरांध बदबू की महक एवं गंदगी से व्यवसायी असमय ही विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं. प्रांगण में एक व्यवसायिक केंद्र से दूसरे व्यवसायी तक पहुंचने में सड़क पर कीचड़, गड्ढे, जल, सुअर के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता है. आलम यह है कि सड़क में गड्ढे होने के कारण नित्य ट्रक समेत दो-चार वाहनों का पलटना लाजिमी हो गया है. जिससे वाहनों का परिचालन ठप पड़ जाता है. व्यवसायियों के प्रतिष्ठान की छत से पानी तो क्या दीवार एवं पलस्तर भी टूट रहे हैं.





**प्रांगण में एक व्यवसायिक केंद्र से दूसरे व्यवसायी तक पहुंचने में सड़क पर कीचड़, गड्ढे, जल, सुअर के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता है. आलम यह है कि सड़क में गड्ढे होने के कारण नित्य ट्रक समेत दो-चार वाहनों का पलटना लाजिमी हो गया है. जिससे वाहनों का परिचालन ठप पड़ जाता है.**

इस संबंध में गुलाबबाग आलू प्याज कृषक व्यवसायी संघ के अध्यक्ष बबलू चौधरी का कहना है कि वर्तमान में हमलोग सरकार की लापरवाही के चलते सुअरों के साथ रहने को विवश हैं, वहीं संरक्षक मुन्ना गुप्ता का कहना है कि सरकार को उच्च राजस्व देने के बावजूद भी हमलोग को सुविधा नदारद है. लहसुन, मिर्च व्यवसायी संघ के सुरेश चौधरी का कहना है कि आज बाहर के व्यापारी सड़क एवं गंदगी के चलते प्रांगण में नहीं आना चाहते हैं, जिससे हमलोगों के व्यवसाय पर असर पड़ रहा है. कृषि उत्पादन बाजार समिति के जीर्णोधार एवं गंदगी के बारे में बाजार समिति के पदेन सचिव सह सदर अनुमंडलाधिकारी पूर्णिया कुंदन कुमार सिंह से जब बात की गई उनका कहना था कि इस संबंध में राज्य के कृषि विभाग को लिखित जानकारी भेजी गई है. कृषि विभाग शीघ्र इस मद में राशि का आवंटन करेगा, राशि आते ही इसके जीर्णोधार पर शीघ्र ही ध्यान दिया जायेगा.

feedback@chauthiduniya.com

## बाहर के खाने से बचें : डॉ शंकर

सीवान के जाने माने डॉक्टर शंकर सिंह का कहना है कि बरसात और इसके बाद भी लोगों को बाहर के खाने से बचना चाहिए. उन्होंने कहा कि ख़ासकर स्कूली बच्चे सड़क पर बिकने वाला सामान खाते हैं. फिर पेट की बीमारी घर ले आते हैं. बरसात के मौसम में तो इसका प्रकोप काफी बढ़ जाता है. इसलिए गार्जियन को भी चाहिए कि वे बच्चों को बाहर का खाना न खाने दें. जहां तक संभव हो पानी उबाल कर पीएं और घर में भी साफ सफाई रखें. सिंह की राय है कि अगर हमलोग थोड़ा सा परहेज करें तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है. उन्होंने संतुलित आहार पर ज़ोर दिया. उनकी राय में संतुलित आहार के अभाव में शरीर का संतुलन गड़बड़ाने लगता है. सिंह ने कहा कि इन दिनों डेंगू का भी प्रकोप बढ़ा है इसलिए मच्छरों को पास न आने दें और घर के आस पास इस बात का ख्याल रखें की पानी जमा नहीं हो पाए. पानी जमा होने से डेंगू के मच्छर पनपते हैं और बीमारी फैलने का ख़तरा बढ़ जाता है. डॉ. शंकर सिंह का मानना है कि एक डॉक्टर को पूरे सेवा भाव से रोगियों का इलाज करना चाहिए. हर तरह के रोगी आते हैं इसलिए उनके मिजाज को समझकर उनका इलाज होना चाहिए. उन्होंने कहा कि रोगियों का इलाज कर उन्हें संतुष्टि मिलती है. लगता है भगवान ने इस धरती पर भेजा है तो मानवता की जितनी सेवा हो सके उसे करूं. इससे बड़ा सुख जीवन में कुछ नहीं है.



डॉ. शंकर सिंह

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# सड़ गया ग़रीबों का अनाज





मनोज ठाकुर

कोसी प्रमंडल में खाद्यान आपूर्ति में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. ग़रीबों के लिए आया कुछ अनाज गायब हो गया तो कुछ सड़ गया. अनाजों की ढुलाई ऐसी हुई कि की गड़बड़ी की बू आने लगी. इस गड़बड़ी का भंडाफोड़ तब हुआ, जब खाद्यान पानी में सड़ने लगा और इसकी बदबू चारों ओर फैलने लगी. इस संबंध में दर्ज एफआईआर पर आज तक न तो कोई गिरफ्तारी हो पाई और न ही कोई कारवाई. 15 अप्रैल और 20 अप्रैल को पटियाला से दो रैक चावल रेलवे रैक प्वाइंट सहरसा पहुंचा. जिसमें एक लाख 23 हजार 920 बोरी चावल था. इस चावल को रैक प्वाइंट से एसएफसी और एफसीआई के सहरसा, मधेपुरा, सुपौल व राधोपुर के गोदाम तक सुरक्षित पहुंचाने का ज़िम्मा एफसीआई द्वारा नियुक्त तीन परिवहन अभिकर्ता सुबोध कुमार, घनश्याम चौधरी व विजय कुमार विमल का थी. कुमार व चौधरी ने एसएफसी के गोदाम में जगह न होने का कारण उठाव से इंकार कर दिया. लेकिन विमल सारे चावल का उठाव करने को तैयार हो गए. फाइलों पर लिखी बातों पर अगर भरोसा करें तो वह 1 लाख 20 हजार 920 बोरी को सुरक्षित गोदाम तक पहुंचाने में सफल रहे. लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कुमार व चौधरी ने जो तीन एसएफसी गोदाम के खाली नहीं होने की लिखित सूचना दी, क्या वह ग़लत थी? अगर इनकी सूचना सही थी तो शेष बचे दो गोदामों में क्या इतनी जगह थी कि अनाज को वहां रखा गया. अगर गोदाम खाली था तो फिर जब पांच में तीन गोदाम पूरी तरह भरे थे शेष दो गोदाम क्यों खाली थे? 15 अप्रैल से 8 जून यानी की एफआईआर होने तक इन सवा लाख बोरी चावल के उठाव संबंधित दो दर्जन से अधिक पत्र रेलवे रैंक प्वाइंट प्रभारी, प्रबंधक भंडार, गोदाम प्रभारी समेत विमल व ज़िला प्रशासन द्वारा उठाव सम्पन्न कराने हेतु प्रतिनियुक्त समिति सदस्य सहरसा द्वारा एक दूसरे को लिखे गये. इन पत्रों से वर्षों से हो रही गड़बड़ी का भंडाफोड़ होता है. विमल ने अपने पत्रांक 9 दिनांक 02.06.2011 में ट्रक संख्या एच आर 38 एच 4378 में 600 बोरी, डब्लू बी 23– 6052 से 350 बोरी, बी आर 11 – 8347 से 300 बोरी, डब्लू बी 59– 2160 से 300 बोरी चावल ढोने की बात प्रतिदिन करते हैं. इनसे एक कदम बढ़ कर भारतीय खाद्य निगम सहरसा के गोदाम संख्या 2 के गोदाम प्रभारी गरीब दास ने पत्रांक खा.नि./सहरसा दिनांक 21.05.2011 को तीन ट्रकों जी जे 6 डब्लू 7911 से 450 बोरी, एच आर 38 जी 6111 से 500 बोरी व एक अन्य ट्रक से 400 बोरी चावल पहुंचने की बात करते हैं. लेकिन दिनांक 07.06.2011 को भारतीय खाद्य निगम सहरसा के गोदाम में आपूर्ति निरीक्षक शहरी क्षेत्र सहरसा किशोर साह, कार्यपालक पदाधिकारी सदर सहरसा अशोक कुमार सिंह द्वारा ट्रक संख्या एच आर 38 एच 4378 पर 240 बोरा, डब्लू बी 23 – 6052 पर 260 बोरा, बी आर 11 – 8347 पर 240 बोरा, डब्लू बी 59 – 2160 पर 240 बोरा सड़ा चावल जब्त किया गया. यानी ट्रक की क्षमता थी 240 बोरा चावल लादने की, लेकिन गोदाम की फाईलों में इन ट्रकों में कहीं 600 बोरा तो कभी 500 बोरा तो कभी 350 बोरा तक चावल लद कर आते दिखलाया गया. मतलब क्षमता से तीन गुना माल ट्रकों पर लदता रहा.



सहरसा सदर थाने में 8 जून को दर्ज प्राथमिकी संख्या 263/11 में मात्र तीन हजार बोरा चावल बर्बाद होने का उल्लेख है. अनुमंडल पदाधिकारी सहरसा के पत्रांक 776 गो. दिनांक 08.06.2011 के आलोक में गरीब दास प्रभारी गोदाम संख्या 2, उमा कांत झा प्रबंधक भंडार व मो. सरफराज खान क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय खाद्यनिगम सहरसा के विरुद्ध 272, 273,418,429,469 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 14/14 (ए)/15/16 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1954 के अंतर्गत मामला तो दर्ज कर लिया गया है. विमल का इस मामले में कहना है कि रेलवे की उदासीनता के कारण अनाज सड़ता व गायब होता है. अनाज को सुरक्षित रखने के लिए न तो शेड है और न ही रैक प्वाइंट की चाहरदीवारी की गई है. किसी भी तरह की गड़बड़ी से इंकार करते हुए विमल कहते हैं कि प्रकृति की मार से भी हमलोग लाचार हो जाते हैं. जिस अनाज के सड़ने की बात कही जा रही है वह बारिश व तूफान के कारण हुआ है. हमलोग चाहकर भी इसे नहीं बचा पाते. जब तक शेड का निर्माण नहीं होगा और चाहरदीवारी नहीं बनेगी, तब तक हमलोग लाचार हैं.

feedback@chauthiduniya.com


डा. जाकिर हुसैन संस्थान
www.zhi.org.in स्थापित-1979
UGC-भारत सरकार मान्यता-प्राप्त पाठ्यक्रम
BCA BBA BMLT
BHM HOTEL MGT. B.Sc-IT BRIT रेडियोलॉजी
MBA B.Sc Bio-Tech BJMC पत्रकारिता
MCA M.Sc Bio-Tech MJMC पत्रकारिता मास-काम
Patna : Hartali More, Ph: 0612-2520647, 3269707
Munger : Magistrate Colony, Ph: 06344-228346, 322888
Bhagalpur : Adampur Chowk, Ph: 0641-2409298, 3201117
Muzaffarpur : Kalambag Chowk, Ph: 0621-2241519, 3205993

A fastest Growing Company
Maker Of
ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalamin,Lycopene,Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
ASRFEN-P
Aceclofenace + paracetamol Serratiopeptidase Tab.
FLUCEN
Flupentixol & Melitracen Tablets
Carbo-XT
Ferrous Ascorbate With Folic Acid Tab.
ECTALOPAM
Escitalopram Oxalate &Clonazepam Tablets
MUSTAL
Levocetirizine Hydrochloride Montelukast Sodium Tab.
ariskon Pharma Pvt.Ltd.

EXPERT BANK COACHING
MODERN STUDY CENTER
West of Patel Field, Kashipur, SAMASTIPUR
बेहतर मार्गदर्शन, अधिकतम सफलता की गारंटी, न्यूनतम शुल्क के साथ
• Expert & Experienced Faculties के मार्गदर्शन में नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स एवं परीक्षा पूर्व विशेष TEST SERIES के साथ. अब जून 2011 से Test With Discussion Classes. सप्ताह में कम से कम 2–3 Test Series • English Classes For XI & XII Speaking & Competitive Courses के लिए • Notes, Practice-set, Model Paper With Answer, Competitive Test Series अब पत्राचार द्वारा भी मंगवा सकते हैं. • Bank (Clerk/P.O.), SSC, RLY (Non Tech & ALP Tech), Sachivalya Sahayak, TET (Teacher Eligibility Test) की तैयारी एवं मार्गदर्शन हेतु EXPERT BANK COACHING अवश्य Join करें.
एक विशेष सूचना बिहार के किसी भी जिला/ब्लॉक/मुहल्ला या गांव में चलने वाली कोचिंग संस्थान के संचालक हमारे यहां से Notes, Test Srries etc. के लिए 'Franchies' लेकर हमारे संस्थान का अभिन्न अंग बन सकते हैं. इस वर्ष November 2011 से मैट्रिक के लिए भी Notes, Practice-set, Model Paper With Answer & ATOM BOMBS (सभी विषयों का) उपलब्ध करायी जायेगी.
A. Kumar (Anil Kumar) Chairman, Modern Study Centre & Expert Bank Coaching
Contect : 9835006852, 9471043020.

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
1 YEAR WARRANTY
CENTURY POLYPLAST INDUSTRIES
NATURE

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
FREE
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001

बाबा वैद्यनाथ वेलफेयर सोसायटी
भी आई पी चौक, बी देवघर, झारखण्ड
August 15
हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक मनोज कौशिक (सचिव)